खण्ड-130, अंक-3
मंगलवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1875
(23 फरवरी, 1954 ई0)

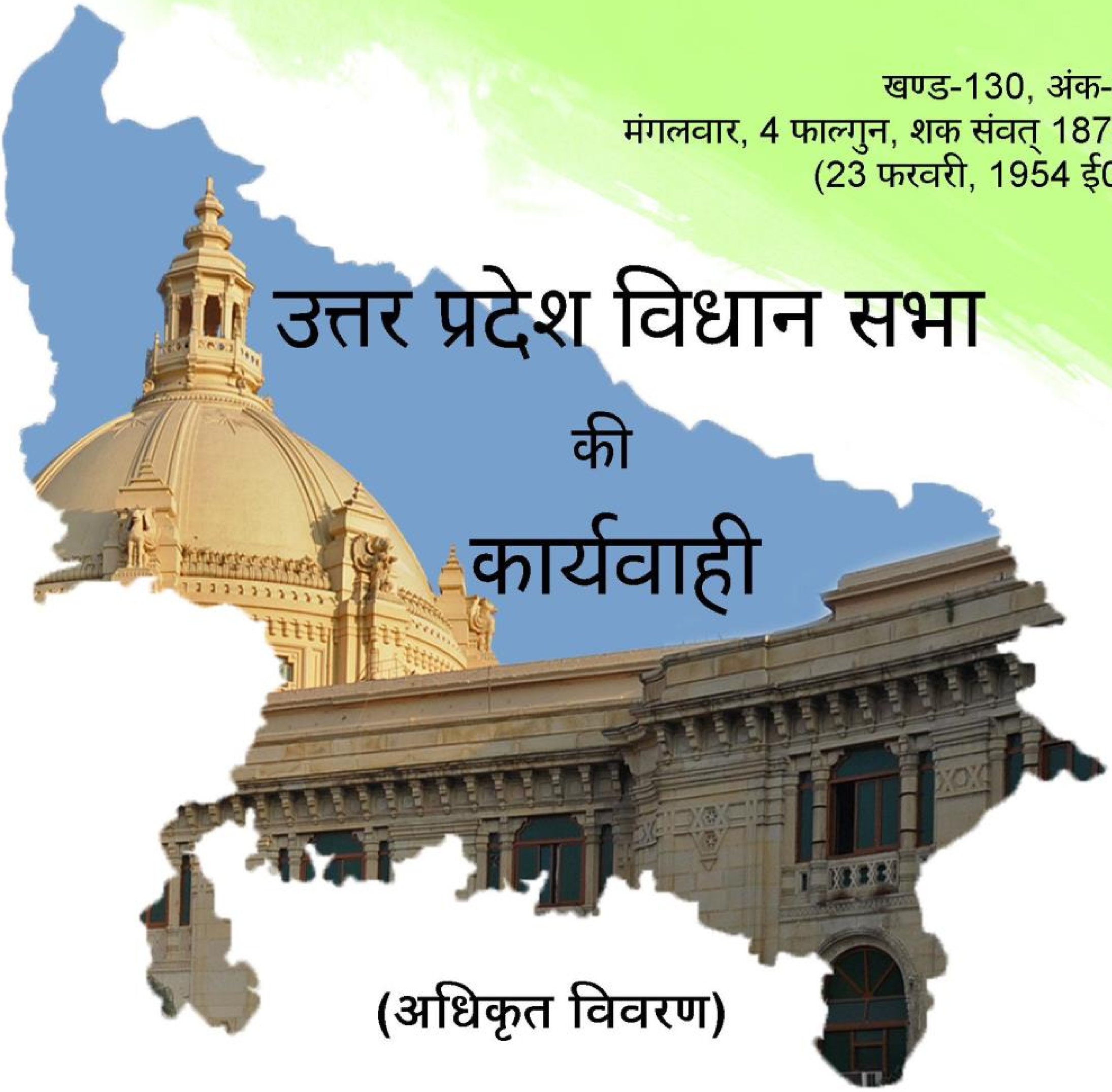

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 130 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ फ़रवरी, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५९)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन, ख्वाजा श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री

गुलजार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्द कुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दूराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मितल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराज कुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बिश्रामराय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नोलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हुसैन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री

सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

(१६ फरवरी, १९५४ के स्थगित प्रश्न।)

* * *

इलाहाबाद पावर हाउस से फतेहपुर को बिजली

*६—श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार फतेहपुर इलाहाबाद पावर हाउस की ४,००० किलोवाट बिजली को जो फाजिल है फतेहपुर में लाकर उससे ट्यूबवेल्स चालित किये जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—सरकार इस पर विचार कर रही है कि फतेहपुर को बिजली कैसे दी जाय।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माननीय वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर को बिजली कैसे दी जाय इस सवाल का हल कब तक निकल सकेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कब तक के लिये तो मैं वादा नहीं कर सकता मगर हम कोशिश जरूर यह करते हैं कि जितनी जल्द हो सके किया जाय।

* * *

इलाहाबाद के नागरिकों द्वारा बिजली कर का विरोध

*१७—श्री कल्याण चन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद के नागरिकों ने ३१ जुलाई को सरकार द्वारा २५ प्रतिशत बिजली की ड्यूटी लगाने के विरोध में ३ घंटे तक बिजली न जलाने के रूप में हड़ताल की थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

* * *

नोट—तारांकित प्रश्न १७ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा।

नैनीताल में भुजाण से बेतालघाट तक बिजली की योजना

*२२--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या जिला प्लानिंग कमेटी, नैनीताल ने भुजाण से बेतालघाट तक सिंचाई के हेतु बिजली लाइन की कोई योजना विद्युत शक्ति विभाग के पास भेजी है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां। अभी इस योजना की जांच हो रही है।

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--[वापस लिये गये।]

*३--श्री लक्ष्मण राव क़दम (जिला झांसी)--[२३ मार्च, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

*४-५--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--[१६ मार्च, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

गोरखपुर बर्ड घाट पर यंत्रचालित नौकायें

*६--श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर बर्ड घाट पर यन्त्रचालित कितनी नौकायें हैं और वह किन-किन दामों पर खरीदी गई थीं ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--बर्डघाट, गोरखपुर पर निम्नलिखित ५ यंत्रचालित नौकायें हैं:--

		संख्या	मूल्य रु०
ट्रक बोट	.. ..	एक	२०,००० रु०
मोटर बोट	.. ..	एक	९,००० रु०
सी हार्स	.. ..	दो	३,६०० रु०
क्रूजर	.. ..	एक	८,२७५ रु०

*७--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 'क्रूजर' और 'सी हार्स' बर्ड घाट के लिये किसी कला विशेषज्ञ की राय से खरीदी गई थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--क्रूजर श्री डी० एल० नियोगी, डिप्टी चीफ मैरिन सुपरिन्टेन्डेन्ट, आसाम रेलवे, कलकत्ता, की राय से खरीदा गया था।

सी हार्स के लिये कोई टेकनिकल परामर्श नहीं लिया गया था। एक वैसा ही सी हार्स देवरिया जिले में संतोषप्रद काम कर रहा था। उसी को देख कर जिला बाढ़ सहायक कमेटी के सदस्यों की राय से यहां भी दो सी हार्स खरीदे गये। देवरिया में संतोषप्रद काम करने के कारण किसी कला विशेषज्ञ का परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझा गया।

*८--श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष की बाढ़ में 'क्रूजर' और 'सी हार्स' ने बाढ़ सहायता में कुछ कार्य किया ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न २२ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछा।

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस वर्ष क्रूजर बाढ़ के दिनों में अधिक काम न कर सका क्योंकि २७ जुलाई, १९५३ ई० को जब वह बाढ़ सहायता का काम कर रहा था उसकी पंखी पानी में गिर गयी जो बाढ़ का पानी कम होने पर खोजी जा सकी।

सी हार्स द्वारा सदर तहसील के ग्रामों की जो नदियों के किनारे पर हैं जैसे मौआपार, बलुईगांडा, लहसड़ी, फरसही, घुनघुन कोठा इत्यादि गांवों की देख-भाल की गई थी। अगस्त मास में एक सी हार्स जिला बलिया भी भेजा गया था।

श्री केशव पाण्डेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ये ट्रक बोट और मोटर बोट कब खरीदे गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ट्रक बोट सन् ४७-४८ में खरीदे गये, मोटर बोट सन् १९४६ में खरीदे गये, सी हार्स सन् ५१ में और क्रूजर सन् ५२ में खरीदे गये।

श्री केशव पाण्डेय---क्या यह सही है कि ट्रक बोट नये जान कर खरीदे गये थे मगर गोरखपुर पहुंचते समय रास्ते में चार जगह मरम्मत की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री केशव पाण्डेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आसाम रेलवे के चीफ़ मैनेजिंग सुपरिन्टेंडेंट ने क्रूजर खरीदने के बारे में कहा था कि यह तेज पानी में नहीं चल सकता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उनकी राय से खरीदा गया था। उन्होंने क्या राय दी थी, यह इस वक्त मेरे पास है नहीं।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि क्रूजर कितने में खरीदा गया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह जवाब में दे दिया गया है।

श्री राम जी सहाय (जिला देवरिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिले के लिये जो ट्रक खरीदा गया था वह कभी भी काम में नहीं आया?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री केशव पाण्डेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सी हार्स को खरीदने के लिये जो टेकनिकल ओपिनियन दी गई थी उसे बाढ़ सहायक कमेटी के सामने रखा गया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जवाब में यह कहा गया है कि इसमें टेकनिकल ओपीनियन नहीं ली गई थी क्योंकि देवरिया में इसने सफलतापूर्वक काम किया था। इसलिये केवल बाढ़ सहायक कमेटी की राय से खरीदा गया।

श्री केशव पांडेय---बाढ़ सहायक कमेटी के सामने यह रिजोल्यूशन कब आया था क्या उसको मंत्री जी मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये तो नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो सी हार्स अगस्त के महीने में बलिया जिले में भेजा गया था उसने अच्छी तरह से काम किया?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री केशव पाण्डेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्रूजर जब से खरीद रक्खाया तब से उसने कोई काम नहीं किया, वह बराबर बीमार पड़ा रहा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले यह बतलाया गया था कि २७ जुलाई तक उसने ठीक काम किया। उसके बाद खराब हो गया। उसके बाद फिर उसने एक महीने के बाद कुछ काम किया।

श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस क्रूजर पर कितना खर्च होता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सारा खर्चा १५ सौ रुपया साल का है।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या यह सच है कि वह बाढ़ के दिनों में कभी काम में नहीं आया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जवाब में बताया जा चुका है कि काम में आया लेकिन कम आया।

श्री रामजी सहाय—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह ट्रक पूरा ठग साबित हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—आप गोरखपुर के बारे में पूछ रहे हैं या देवरिया के बारे में ?

श्री रामजी सहाय—गोरखपुर के बारे में।

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी कोई इत्तिला नहीं है और न आज तक माननीय सदस्य ने कोई इत्तिला दी कि कोई ठग वहां है।

श्री केशव पाण्डेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पांच जो यंत्रचालित नौकायें गोरखपुर में हैं उनके लिये कोई टेक्निकल मैन भी रखा गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो उसमें चालक रखे जाते हैं वे मैकेनिक टाइप के आदमी रखे जाते हैं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जि [illegible] उत्तर "इत्तिला नहीं है" में दिया हुआ है उनकी इत्तिला मंगायेंगे ?

[illegible]—किस प्रश्न से सम्बन्ध है ?

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—तीनों प्रश्नों से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष—इसमें तो इत्तिला दी हुई है। मैं समझता हूं कि आप ने गलत सुना है। इत्तिला तो उन्होंने दी है।

देवरिया में कसया ग्राम के नलकूप का कार्य

*९—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला देवरिया में कसया (कुशीनगर) में बने ट्यूबवेल ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—कसया ग्राम के निकट बने हुये नलकूप संतोषप्रद कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक नलकूप एक छोटे डिजिल इन्जिन से चलता है, जिसमें कभी-कभी छोटे-छोटे दोष हो हो जाते हैं, परन्तु उन दोषों पर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दिया जाता है।

*१०—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार वहां बड़ी पावर की मशीन लगाने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति--इन नलकूपों को चलाने के लिये देवरिया में डेढ़-डेढ़ सौ किलोवाट के चार बड़े डीजिल इंजिनों का पावर स्टेशन बनाया जा रहा है, जिसमें से दो इंजिनों के मार्च, १९५४ के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि खेतों में पानी पहुंचाने के पहिले वह मशीन गर्म हो जाने के कारण बन्द हो जाती है ?

श्री राममूर्ति --मशीन तो लगातार चलने से सभी बन्द हो जाती हैं। खास कर अगर यह मशीन गर्म हो जाती होगी तो उसका इन्तजाम करा दिया जायगा।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या यह सही है कि इस मशीन में बराबर गड़बड़ी रहा करती है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि गड़बड़ी होती है। अगर माननीय सदस्य किसी खास कुयें के बारे में बतलाना चाहें तो बतला दें उसका इन्तजाम कर दिया जायगा।

बस्ती जिले के बर्डपुर तथा अलीदापुर इलाकों में बांधों, कूल्हों आदि का प्रबन्ध

*११--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले के उत्तरी भाग में बर्डपुर व अलीदापुर इलाके में भूतपूर्व अंगरेज जमींदारों ने जो कूल्हे व रिजर्वायर्स तथा पुल बनवाये थे और जो जमींदारी टूटने के बाद से सरकार के प्रबन्ध में हैं, उन कूल्हों, रिजर्वायर तथा उनसे सम्बन्धित पुलों आदि की मरम्मत सरकार द्वारा कब कराई जायेगी ?

श्री राममूर्ति--बर्डपुर तथा अलीदापुर इलाकों के तमाम बांध, कूल्हे तथा उनसे सम्बन्धित पुल सरकार के प्रबन्ध में आ गये हैं और सरकार ने उनकी मरम्मत पिछले साल भी करायी थी और इस साल भी करा रही है। परन्तु जो कूल्हे बहुत छोटे हैं और जो नहर की गूलों के समान हैं उनकी सफाई काश्तकारों द्वारा ही होती रहेगी, जैसा कि प्रान्त की नहरों पर नियम है।

श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस क्षेत्र के ५ कूल्हे रिजवायर और उससे संबंधित पुलों की हालत पहले की अपेक्षा बहुत खराब है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह बात गलत है। मैं स्वयं उन्हें देख आया हूं।

बस्ती में बांसी-नौगढ़ सड़क का निर्माण

*१२--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में बांसी से नौगढ़ बाजार तक जो सड़क बनाई जा रही है उसकी शुरुआत कबसे हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--फरवरी, १९४७।

*१३--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह सड़क कितनी लम्बी है और कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बांसी से नौगढ़ बाजार तक की दूरी १३ मील २ फर्लांग है जिसमें पहले ९ मील ६ फर्लांग बांसी-नौगढ़ सड़क कहलाते हैं और शेष मील नौगढ़-शोहरतगढ़ सड़क का भाग है।

सड़क निर्माण-कार्य की पूर्ति भविष्य में धनराशि की प्राप्ति पर निर्भर है।

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह ९ मील ६ फर्लांग सड़क जो सन् ४७ से बन रही है वह कब तक पूरी होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह शीघ्र पूरी हो जायगी इसमें बहुत काम हो गया है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार अपने देश की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुये नौगढ़ होते हुये जो सड़क लुम्बनी तक गई है उसको बनवाने की कृपा करेगी क्योंकि विदेशी लोग उस सड़क से जाते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस पर विचार किया जायगा, रुपये मिलने पर इसे भी देखा जायगा।

*१४-१५---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---[१ मार्च, १९५४ के लिये प्र० सं० ३०-३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१६-१७---श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---[९ मार्च, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

सोगाई, जिला बनारस में पम्पिंग प्लाण्ट

*१८---श्री राम लखन (जिला बनारस) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि मौजा सोगाई, जिला बनारस के निवासियों ने छोटी सिंचाई योजना के अनुसार Pumping plant के लिये गतवर्ष प्रार्थना-पत्र दिया था परन्तु अब तक वहां के निवासियों को Pumping plant नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

सूचना मन्त्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)---पम्पिंग प्लान्ट सोगाई ग्राम में लगा हुआ है। इस प्लान्ट को अभी गांव वाले चलाने में असमर्थ रहे हैं, अतः नहर विभाग ने चलाया है। नये नियमों के अनुसार ग्राम सभा को यह प्लान्ट भविष्य में चलाने के लिये दे देने का प्रश्न विचाराधीन है।

पहाड़ी इलाकों में सरकारी कर्मचारियों को पहाड़ी भत्ता

*१९---श्री राम लखन (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सरकारी कर्मचारी पहाड़ी इलाकों में भेजे जाते हैं उन्हें कोई Hill allowance दिया जा है ? यदि हां, तो किस हिसाब से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, मुख्तलिफ दरों से पहाड़ी भत्ता दिया जाता है और आम तौर पर इन दरों का हिसाब सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह के अनुसार लगाया जाता है।

*२०---श्री राम लखन (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Hill Allowance देने का क्या नियम है और कौन-कौन से ऐसे पहाड़ी क्षत्र हैं जिनमें यह भत्ता दिया जाता है? क्या चकिया, जिला बनारस के पहाड़ी क्षेत्र के सभी विभाग के कर्मचारियों को, जिनको बराबर जंगल में रहना पड़ता है, Hill Allowance मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पहाड़ों में रहन-सहन का खर्चा ज्यादा होने से पिछले दिनों नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और देहरादून के जिलों में पहाड़ का भत्ता दिया जाता था। लेकिन यह रियायत अगस्त, १९५१ ई० से बन्द कर दी गई है पर उन सरकारी कर्मचारियों को यह रियायत अब भी मिलती है जो इस तारीख से पहिले इसके पाने के हकदार थे।

यह भत्ता चकिया में नहीं मिलता है क्योंकि चकिया ऊपर बताये हुये पहाड़ी जिलों में नहीं आता है। इसके अलावा यह भत्ता किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस बिना पर नहीं दिया जाता है कि उसे जंगल में बहुत दिनों रहना पड़ता है।

नैनीताल में गौला या कलसा नदी से जल प्राप्ति के साधन

*२१—श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार हल्द्वानी तहसील, जिला नैनीताल में पानी व सिंचाई के पानी की भीषण कमी को देखते हुये गौला या कलसा नदी पर कोई बांध बनाने की योजना हेतु सर्वे कराने का विचार कर रही है।

श्री राममूर्ति—गौला तथा कलसा नदियों में सिंचाई तथा पीने का पानी एकत्रित करने के लिये बांध बनाना संभव नहीं है, इसके लिये अन्य साधनों की जांच की जा रही है, परन्तु अभी तक कोई संतोषजनक तथा कार्यान्वित करने योग्य योजना ज्ञात नहीं हो सकी है।

जिला नैनीताल में लोगढ़-योजना अन्वेषण

*२२—श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम लोगढ़, पट्टी चौभैंसी, जिला नैनीताल के लोगों ने अपने ग्राम में सिंचाई व पीने के हेतु पानी लाने के लिये कुछ रुपया एकत्र कर लिया है? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या सहायता करने का विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति—जी हां। इस संबंध में सरकार लोगढ़ योजना का अन्वेषण preliminary survey करा चुकी है। इसको कार्यान्वित करने में कुल व्यय लगभग १,२७,००० रुपया होगा। पहाड़ में नहरों के निर्माण का कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है और वही विभाग इस योजना पर विचार करेगा।

गवर्नमेंट हाउस के नैनीताल के निम्न कर्मचारियों का वेतन

*२३—श्री नारायण दत्त तिवारी—(अनुपस्थित) क्या यह सही है कि गवर्नमेंट हाउस नैनीताल के माली तथा पी० डब्ल्यू० डी० के अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की बुनियादी तनख्वाह केवल १५ रु० मासिक है और उन्हें हिल अथवा विन्टर एलाउन्स नहीं मिलता? अगर हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—गवर्नमेंट हाउस नैनीताल के सब से कम तनख्वाह पाने वाले माली तथा पी० डब्ल्यू० डी० मजदूर को निम्न समय-भूति के अनुसार वेतन मिलता है :—

माली	२०—१/२—२५
पी० डब्ल्यू० डी० मजदूर	१५—१/२—२०

२० रुपया मासिक मंहगाई इसके अतिरिक्त है। हिल अथवा विन्टर एलाउन्स इन्हें नहीं दिया जाता और न इस संबंध में कोई और कार्यवाही हो रही है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि और विभाग के कर्मचारियों को पहाड़ों पर हिल अलाउन्स भी दिया जाता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह जरूरी समझती है कि इन छोटे कर्मचारियों की पहाड़ों पर १५ रुपये में गुजर नहीं होती?

श्री अध्यक्ष—यह विवाद का प्रश्न है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

अतारांकित प्रश्न

राप्ती नदी पर पुल बनाने की योजना

१—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार को पता है कि बस्ती जिले का उत्तरी भाग जो कि राप्ती नदी से उत्तर में है राप्ती नदी पर पुल न होने से जिले से अलग हो जाता है ? अगर हां, तो क्या सरकार राप्ती नदी पर पुल बनवाने का विचार कर रही है ?

निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारी लाल)—जी हां, पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

विधान सभा के सदस्य श्री गजेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इटावा का रात तार आया है कि श्री गजेंद्र सिंह, एम० एल० ए०, दफा ३ स्पेशल पावर ऐक्ट में कल रात १० बजे गिरफ्तार कर लिये गये हैं। उनका पत्र भी मेरे पास आ रहा है। तो मैं यह सूचना सदन को देता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह की श्री पद्मनाथ सिंह के भाषण के कुछ शब्दों के विरुद्ध आपत्ति

श्री अध्यक्ष—मेरे पास राजा वीरेंद्रशाह की यह शिकायत आई कि सदन में जिस समय वह मौजूद नहीं थे, तारीख १६ की बात है, तो उनके भाषण के बाद श्री पद्मनाथ सिंह बोले और चूंकि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिनमें श्री वीरेंद्रशाह जी के ऊपर प्रत्यक्ष आक्षेप होता है और सदन की जो पार्लियामेंटरी पद्धति है, और प्रतिष्ठा है, उसके विरुद्ध भी है और कुछ व्यक्तिगत हमले का भी उसमें आभास होता है। मैंने इस विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके भाषण की रिपोर्ट मैंने देखी। मैं समझता हूं कि जिन शब्दों में उन्होंने अपने विचार जाहिर किये वे शब्द उचित नहीं हैं। श्री पद्मनाथ सिंह ने उनका उद्देश्य यह बताया कि वे किसी वर्ग के विषय में जिक्र कर रहे थे और उनके दिमाग में उसका ही चित्र था न कि श्री वीरेन्द्रशाह जी तथा श्री बालेन्दुशाह जी को लक्ष्य करके कहना था (बालेन्दुशाह जी भी उस समय तक बोल चुके थे।) माननीय सदस्य ने "वह लोग जो गरीबों की हड्डियां चूस रहे हैं" आदि शब्दों, जिनको मैं यहां फिर दोहराना नहीं चाहता, का प्रयोग किया था लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग जब किसी के नाम के साथ किया जाता है तो उसका उद्देश्य चाहे जितना ऊंचा क्यों न रहा हो या वर्ग विशेष के लिये ही उनका मतलब क्यों न रहा हो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं होता। ये शब्द श्री वीरेन्द्रशाह जी की गैरहाजिरी में कहे गये थे, अगर वे मौजूद होते तो मेरा विचार है कि वीरेंन्द्रशाह जी के कहने पर माननीय सदस्य उन वाक्यों को वापिस ले लेते। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि उन वाक्यों को उस भाषण में से निकाल दूं और इसी की प्रार्थना वीरेंद्रशाह जी ने की भी है। यही बात उस समय भी होती जब कि वे अपने शब्दों को वापस ले लेते और बाद में कोई शिकायत न रह जाती। इसलिये मैं इन वाक्यों को हटा दूंगा और इसके लिये कि संदर्भ न बिगड़ने पाये कुछ शब्दों का हेरफेर भी करना होगा जिसे मैं प्रसंग को देखते हुये कर दूंगा।

सार्वजनिक लेखा समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने यह प्रश्न उठाया कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के वे सभापति हैं और नियमानुसार कमेटी ही अपने सभापति को चुनती है अतः वे निर्वाचित

सभापति हैं। साधारणतः कमेटी की रिपोर्ट सभापति द्वारा ही उपस्थित की जाती है इसलिये उन्होंने यह इजाजत चाही है कि सदन के सामने उनको रिपोर्ट उपस्थित करने की इजाजत दी जाय। इस विषय में मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि दूसरी जगहों में किस तरह का रिवाज है और क्या यह वैधानिक प्रश्न है या रूढ़ि का प्रश्न है? इतना तो मैं स्पष्ट ही कर देना चाहता हूं कि यह वैधानिक प्रश्न की कोटि में नहीं आता क्योंकि हर जगह इस विषय में भिन्न-भिन्न रूढ़ियां प्रचलित हैं।

मैंने देखा कि नई दिल्ली से जो तार आया है उसमें यह बताया गया है कि चेयरमैन की नियुक्ति स्पीकर के द्वारा होती है तथा स्पीकर असरकारी व्यक्ति को ही चेयरमैन नियुक्त करते हैं न कि फाइनेंस मिनिस्टर को और वही असरकारी व्यक्ति रिपोर्ट को पेश करता है।

पश्चिमी बंगाल में तरीका यह है कि कमेटी ही अपना चेयरमैन चुनती है और मिनिस्टर ऐक्स आफीशियो मेम्बर की तरह कमेटी में रहता है, जैसा कि हमारे यहां है लेकिन वहां कमेटी का चेयरमैन ही रिपोर्ट को पेश करता है। पूर्वी पंजाब में चेयरमैन भी असरकारी होता है और वही रिपोर्ट पेश करता है। नागपुर और मध्य प्रदेश में भी यही तरीका है। बम्बई में तरीका दूसरा है। वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ऐक्स-आफीशियो चेयरमैन होता है और वही रिपोर्ट पेश करता है। इसी तरह से पटना और बिहार में भी यही तरीका है लेकिन उन्होंने यह भी लिखा है कि यह उनके नियम पुराने हैं उससे मालूम होता है कि वे इनमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। मद्रास में जो रिवाज हमारे यहां है वही है। चेयरमैन कमेटी चुनती है और वह असरकारी होता है लेकिन साधारणतया उन्होंने लिखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर रिपोर्ट पेश करते हैं जो कि एक्स-आफिशियो सदस्य हैं, यही हमारे यहां का तरीका है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों ही प्रथायें कामयाबी के साथ चल रही हैं, कभी उनमें कोई झगड़ा नहीं हुआ नहीं तो बदल देते। ऐसी अवस्था में यह रूढ़ि जो चल रही है वह भी चलायी जा सकती है और इसको यदि बदल दें तो वह भी चलायी जा सकती है। इसमें सिद्धांत की बात तो यह है कि कमेटी जिसके ऊपर विश्वास करती है वही सभापति चुना जाता है और जब उसमें इतना विश्वास कमेटी ने प्रकट किया तो कोई कारण नहीं है कि वही सभापति रिपोर्ट कमेटी की तरफ से पेश करे। यह सदन की बनायी हुई कमेटी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से निर्वाचित है, सब दल के लोग उसमें चुने जाते हैं लेकिन जिस वक्त कोई सदस्य कमेटी का मेम्बर बन जाता है चूंकि कमेटी सदन की है और वह भी केवल हिसाब की जांच करने के विषय में है इस कारण वह सदन का प्रतिनिधि होता है न कि किसी पार्टी विशेष का। हिसाब के लिये जिम्मेदार सरकार ही रहती है तो यह प्रथा जो चली कि असरकारी लोगों को उसका चेयरमैन बनावें इस प्रथा के बनाने में सरकार ने बहुमत में होते हुये भी एक तरह अल्पमत के लिये जेस्चर किया कि भाई, यह हमारा हिसाब है, तुम पूरी तरह जांच लो और इसीलिये हम तुममें से ही एक को चेयरमैन भी बना देते हैं। यद्यपि बहुमत में हमारा पक्ष ही उस कमेटी में भी रहता है। तो जब कमेटी में इस प्रकार का जेस्चर दिया तो मैं तो यही उचित समझता हूं कि चेयरमैन जो कमेटी का हो वही उसको पेश करे जब तक कि कमेटी इस मत की न हो कि अगर सभापति किसी कारण से गैरहाजिर हो जाय तो उसे कोई दूसरा मेम्बर पेश करे। अगर इस तरह से प्रथा का बदलना हो जाय तो मैं समझता हूं कि उचित ही होगा। यह मेरी इस वक्त राय है। सिर्फ मैं एक मौका देना चाहता हूं उन लोगों को जो मेरी राय से सहमत नहीं हैं। ऐसे अगर किसी भी दल के लोग हों तो उनमें से एक व्यक्ति या दो चार व्यक्ति मुझे लिख कर भेजें कि वे किस कारण से मेरी राय से सहमत नहीं हैं। क्योंकि मैं प्रथा बदल रहा हूं इसलिये मैं यह मौका देना चाहता हूं कि दो-चार आदमी जो भी हों वे कारण बतलावें कि मुझसे क्यों सहमत नहीं हैं। अगर उसके बाद मुझे कोई बात ऐसी दिखलाई दी कि मैं अपना मत परिवर्तन करूं तो दूसरी तरफ के लोगों को भी मैं मौका दूंगा। लेकिन यदि मैं इस मत का परिवर्तन न करूं तो मैं परसों तक यह जाहिर कर दूंगा कि मैंने अपना मत परिवर्तन नहीं किया

[श्री अध्यक्ष]

और यही प्रथा चलेगी। कल तक अपनी राय इस संबंध में जो सदस्य भेजना चाहें कृपा कर लिख कर भेज दें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने सम्मति दी वह बहुत ही अच्छी सम्मति है और अब फिर उसके लिये और मौका देना मैं समझता हूं कि अनावश्यक है। इसलिये आप कोई मौका न दें, आपकी जो सम्मति है वह बहुत ही अच्छी सम्मति है।

श्री अध्यक्ष---अच्छी सम्मति तो है। मगर कोई उसका विरोध न करे तो जो मैंने सम्मति दी है उसमें चार चांद और लग जायेंगे।

श्री राज नारायण---इस तरह से आपने मौका दिया है तो आइन्दा के लिये हमें भी इस तरह के कार्य के लिये मौका मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है।

श्री अध्यक्ष---मैं यह बतला दूं कि यह जरूरी नहीं है कि हर बात के लिये मौका दूं। बात यह है कि पहले की जो प्रथा है उसे मैं बदल रहा हूं इसे सर्वसम्मति से स्वीकार होना चाहिये इसलिये मैंने यह मौका दिया। अगर सदस्यों ने इस विषय पर अपनी राय पहिले जाहिर कर दी होती तो फिर उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलता।

१९५४-५५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---आनरेबिल स्पीकर साहब.....

श्री प्रभाकर शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट आफ आर्डर। प्रस्तुत आय-व्ययक की जो प्रतियां हम सदस्यों को दी गई हैं उसके खंड ४ के पृष्ठ २०८ से २१७ के कुछ स्थान लुप्त हो गये हैं। संभव है कि कुछ प्रतियों में दोबारा जोड़ दी गयी हों। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि हम लोगों को अतिरिक्त पूरक के रूप में इन पृष्ठों का दिया जाना आवश्यक है या नहीं?

श्री अध्यक्ष---मैं यह जानना चाहता हूं कि और भी किसी माननीय सदस्य के बजट की प्रति में इस तरह की कमी है?

कुछ सदस्य---जी हां?

श्री अध्यक्ष---तो इसकी वजह से काम नहीं रुकेगा क्योंकि आपने तो आज बताया है और बहस कल से चल रही है, तो बहस तो जारी रहेगी।

श्री प्रभाकर शुक्ल---मैंने तो श्रीमन्, आपकी व्यवस्था चाही है कि इन पृष्ठों की अतिरिक्त पूरक के रूप में प्रतियां सदस्यों को दी जानी आवश्यक हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष---सब लोग नहीं कह रहे हैं। कुछ लोगों के पास मौजूद हैं और कुछ लोगों के पास नहीं हैं। वह आपके पास पहुंच जायगी और पहुंचना जरूरी है।

*श्री सुल्तान आलम खां---अध्यक्ष महोदय, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को इस बजट के लिये, जो उन्होंने भवन में पेश किया है, मुबारकबाद देता हूं। यह सही है कि किसी हुकूमत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का बजट उस हुकूमत की साल भर की कार्यवाहियों का आइनादार होता है। उसको पढ़कर हमें इस बात का मौका मिलता है कि हम यह देख सकें कि इस हुकूमत ने साल भर में हम लोगों के लिये क्या किया और आइन्दा आनेवाले साल में क्या करने वाली है। हमें यह भी मौका है कि हम उस वक्त अपनी तजवीजात हुकूमत के सामने पेश करें। जाहिर है कि बजट का कोई आइटम मुकम्मिल नहीं हो सकता लेकिन उसी के साथ यह भी जरूरी है कि उन तजवीजात पर गवर्नमेंट गौर करे और हो सके तो आइन्दा के बजट में उन पर तामील करे। इस एतबार से मैं जब इस बजट को देखता हूं तो मुझे खुशी है और मैं यह समझता हूं कि बजट में इस बात की ईमानदाराना कोशिश की गई है कि इस सूबे के अन्दर डेवलपमेंट और प्लानिंग के प्रोग्राम पर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा जाय। मैं यह नहीं कहता कि बजट में कुछ खामियां नहीं हैं। दुनिया में, इन्सान के हर काम में कुछ न कुछ खामियां हो सकती हैं लेकिन आन दि होल, अगर हम बजट के सफहों पर नजर डालें और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर को पढ़ें तो हमें यह बात माननी पड़ेगी कि इस बजट के जरिये से इस बात की कोशिश की गई है कि सूबे को जल्द से जल्द डेवलपमेंट और प्लानिंग के रास्ते पर डाला जाय। मैं जब कल अपने दोस्त लीडर आफ दि आपोजीशन की तकरीर सुन रहा था तो मैंने ताज्जुब से अपने आंखों को मला और यह महसूस किया कि जो तजवीजात मेरे दोस्त ने पेश की हैं उनमें से बाज तजावीज को मान लिया जाय तो इस सूबे के अन्दर बजट तो क्या एक ऐनार्की पैदा हो जायगी। मैं इस बात को मानता हूं कि मेरे दोस्त राज नारायण जी ने बड़ी मेहनत से अपनी बजट की स्पीच तैयार की थी, उन्होंने काफी गौर से बजट को पढ़ा है, और काफी कोशिश इस बात की की है कि आंकड़े रखे जायं और उनकी स्पीच इस माने में काफी एजूकेटिव वैल्यू रखती है मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन फिर भी मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि उन्होंने अपनी तकरीर में बाज-बाज चीजें ऐसी कही हैं जिनका किसी सूरत में भी माना नहीं जा सकता है। मसलन तकरीर के दौरान में एक मर्तबा उन्होंने यह फर्माया कि बनारस में डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन इतना खराब है कि वहां पर दो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। यानी एक हिन्दू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एक मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मैं नहीं समझ सकता कि इस सेक्यूलेरिज्म के जमाने में और ऐसे जमाने में जब कि हमारे मुल्क का कांस्टीटयूशन हमें सेक्यूलेरिज्म की तरफ ले जा रहा है यह बात किस तरह से मुनासिब हो सकती है।

मेरे दोस्त ने अपनी तकरीर के दौरान में यह भी कहा कि लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई खास तवज्जह नहीं दी गई। इसके मुताल्लिक मैं उनसे सिर्फ यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर वे इस बजट के सफों को दोहरायें तो उन्हें मालूम हो जायगा कि गवर्नमेंट ने दोनों यूनिवर्सिटियों के लिये क्या किया है और क्या कर रही है। मेरे अर्ज करने का मतलब यह था कि ऐसी बहुत सी बातें उनकी तरफ से कही गईं जो मैंने नोट की हैं लेकिन उनको दोहराकर मैं इस हाउस का वक्त खराब करना नहीं चाहता। मैं अर्ज करना यह चाहता हूं कि मुनासिब यह है और जरूरत इस बात की है कि जो सजेशन दिये जायं वे ऐसे हों जो कि कारआमद हो सकें और जिन पर अमल किया जा सके। अगर इस किस्म के सजेशन आते हैं कि जिन पर अमल नहीं हो सकता तो उनसे हम हाउस में कोई खास बात नहीं पैदा कर सकते हैं।

जनाबवाला, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जिस वक्त इस ऐवान में २३६ मेम्बर थे उस वक्त बजट पर जनरल डिस्कशन के लिये दो रोज दिये जाते थे और एक मौके पर, जहां तक कि मेरी याद काम करती है, तीन रोज रक्खे गये थे। लेकिन अब इस हाउस के अन्दर तकरीबन दुगने मेम्बर हो गये हैं, ४३१ की तादाद हो गई है इसलिये इस सूरत में अगर बजाय तीन दिन के चार दिन आइन्दा रखे जायं तो मैं समझता हूं कि कोई नामुनासिब बात नहीं होगी।

[श्री सुल्तान आलम खां]

इस बजट के देखने से यह पता चलता है कि इस साल बजट पर ८१ करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर के जरिये से खर्च किया जायगा। अगर हम आगे और पढ़ें तो हम यह भी देखते हैं कि इस बजट में २० करोड़ रुपया और ऐसा है जो कैपिटल एक्सपेण्डीचर के जरिये से इस सूबे में खर्च किया जायगा। अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाय तो पता यह चलता है कि इस साल गवर्नमेंट का यह इरादा है कि १०१ करोड़ रुपया यानी एक अरब और एक करोड़ बजट के अन्दर इस सूबे के अन्दर खर्च करेगी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह तादाद हमेशा बढ़ती चली जा रही है। सिर्फ सवाल यह जरूर पैदा होता है कि प्लानिंग के प्रोग्राम को पूरा करने के लिये बाकी रकम हम कहां से ला सकेंगे। पिछले बजट को देखने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट ने रुपया हासिल करने के लिए जो कुछ कोशिश वह कर सकती थी, जरूर की। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो एकोनोमी ड्राइव चलाया था उसमें ढाई करोड़ रुपये की बचत हुई थी जो कि डेवलपमेंट और प्लानिंग पर खर्च हुआ। इस साल गवर्नमेंट फिर एक कमेटी बिठाना चाहती है जिसमें इस ऐवान के मेम्बर भी शामिल होंगे, जो कि इस बात पर गौर करेगी कि किस जगह से रुपया बचा कर के डेवलपमेंट और प्लानिंग के काम पर खर्च किया जाय। इसके अलावा बजट को देखने से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर पढ़ने के बाद जो चीजें हमें मालूम होती हैं वे चीजें ऐसी हैं जिन्हें यह हाउस पसन्द करेगा। जैसे खाने-पीने के मामले में हम बड़ी हद तक सेल्फ सफीशेन्ट हो गये हैं और होते जा रहे हैं। उसका सबूत यह है कि जो कंट्रोल का कानून हमारे सूबे में लागू था उसमें बड़ी हद तक रिलैक्जेशन कर दिया गया है और सिर्फ बाज आस्टेरिटी के मुकामात पर, डेफिसिट एरियाज में कायम है।

इससे यह मालूम होता है कि जहां तक गल्ले का और खाने-पीने की चीजों का ताल्लुक है, वह तो हमारे सूबे और मुल्क में बाकी नहीं रहा, जो पहले था। हमें यह भी मालूम पड़ता है कि जो कीमतें पिछले दो साल में ऊंची से ऊंची हो गई थीं उन कीमतों में कुछ न कुछ गिराव हो गया है, अगर्चे वह गिराव अभी तक इतना नहीं हो सका है कि जिससे आम पब्लिक पूरा फायदा उठा सके, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गिराव की टैंडेंसी है।

हमें यह देख कर खुशी होती है कि इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। अलबत्ता हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, अपनी तकरीर में यह जरूर फरमाया था कि अगर डेवलपमेंट और प्लानिंग के प्रोग्राम के लिये हमें जरूरत पड़ी और किसी दूसरे जरिये से हम रिसोर्सेज हासिल न कर सके तो हम और टैक्स जरूर लगायेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा कहने में वह हक बजानिब हैं। लेकिन मैं बड़े अदब से उनसे यह जरूर अर्ज करूंगा कि जिस वक्त मजीद टैक्स लगाने का सवाल पेश हो तो उस वक्त चन्द बातें गौर करने की हैं और वह यह हैं कि हमें यह भी देखना है कि हमारे मुल्क के अन्दर नेशनल इन्कम और पर कैपिटा इन्कम कहां तक बढ़ी है या घटी है। अभी दो तीन-रोज हुये जब पार्लियामेंट में एक साहब ने सवाल किया था और उन्होंने यह पूछा था कि यह बतलाया जाय कि पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है या घटी है और नेशनल इन्कम मुल्क में बढ़ी है या घटी है। तो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो आदाद शुमार बतलाये थे उन आदाद शुमार को तो मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उससे बेकार हाउस का वक्त सर्फ होगा लेकिन उससे यह जरूर मालूम हुआ कि पिछले दो सालों में यह आमदनी बढ़ी है। लेकिन इस सिलसिले में वहां के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नेशनल इन्कम कमेटी बिठलाई है, सेंटर में

और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया को दे दी है। उस कमेटी की रिपोर्ट से जरूर यह जाहिर होता है कि पर कैपिटा इनकम पिछले साल से कुछ घट रही है और उससे हमारी नेशनल इनकम पर जरूर असर पड़ेगा। तो यह वाक़आत ऐसे हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट भी ध्यान में रखे अगर किसी वक्त उसको कोई नया टैक्स लगाने की जरूरत पड़ जाय। इसमें शक नहीं है कि टैक्जेशन की पालिसी बहुत ही अहम पालिसी होती है और उसके ऊपर सूबे के बजट और उसके तमाम खर्च का इनहिसार होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि इसकी तरफ गवर्नमेंट अपनी काफी तवज्जह मबजूल कर रही है, इसलिये कि इसी बजट को पढ़ने से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सेल्स टैक्स जिसके मुताल्लिक अक्सर बड़ी शिकायतें सुनने में आयी हैं उसमें भी गवर्नमेंट कुछ रिआयत देना चाहती है और वह रिआयत यह है कि जहां तक काटेज इंडस्ट्रीज के प्राडक्ट्स का ताल्लुक है गवर्नमेंट उसे एक्जेम्प्ट करना चाहती है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट का यह फेल भी ऐसा है कि हाउस के चारों तरफ के लोग ख्वाह इस तरफ के बैठने वाले हों, ख्वाह उस तरफ के बैठने वाले हों, वह इसे पसन्द करेंगे और इसे वेलकम करेंगे।

फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर से यह भी पता चलता है कि इस फाइव ईयर प्लान के गुजरने के बाद इसी तरह से कोई और प्लान हमारे सामने आयेंगे। यह तो समुन्दर में एक कतरा के बराबर है और २२ साल के बाद उन्हें उम्मीद यह है कि जो प्रोडक्शन इस वक्त सूबे में है वह भी सौ फीसदी बढ़ जायगा। यह जाहिर है कि जो इस वक्त फाइव ईयर प्लान हमारे सामने चल रहा है उसमें सब से ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि सूबे के अन्दर और मुल्क के अन्दर गल्ला बढ़ाने के जराये बहम पहुंचाये जायं। इसी वजह से सब से ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि हमारे मुल्क के अन्दर आबपाशी के जराये बढ़ाये जायं और आबपाशी के जराये बढ़ाने के साथ-साथ गल्ले की पैदावार बढ़ सकती है। अगर हम बजट को पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि रिहंड जैसी स्कीम जिस पर ३५ करोड़ रुपये इस गवर्नमेंट के सर्फ होंगे और जिसको अब प्लानिंग कमीशन ने फाइव ईयर प्लान में भी ले लिया है, जिस वक्त वह मुकम्मल हो जायगा तो उससे गल्ले का मामला बहुत काफी हद तक हल हो जायगा। लेकिन जाहिर है कि फाइव ईयर प्लान हो या टेन ईयर प्लान हो, कोई भी प्लान हो, जो सूबे में या मुल्क में चलाया जाय, वह कारआमद उसी वक्त हो सकता है जब हम सब लोग उसके ऊपर पूरा ध्यान दें और उसमें अपना सहयोग दें और उसको कांग्रेस का प्लान न समझें बल्कि हम उसको नेशनल प्लान समझें और नेशनल प्लान समझने की वजह यह है कि जो प्लान इस वक्त तैयार हुआ है और जो हमारे सामने है वह सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्लान नहीं है। उसके मश्विरे में वे तमाम जिम्मेदार हस्तियां जो इस मुल्क में हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखती हैं उन सबका मशविरा उसमें शामिल है। इस वजह से वह प्लान कांग्रेस गवर्नमेंट की प्लान नहीं कही जा सकती, बल्कि यह सही मानों में एक नेशनल प्लान है और जब तक नेशनल प्लान में पूरे तौर से सब का सहयोग हासिल न हो उस वक्त तक उसका चलना मुश्किल है। आपकी इजाजत से दो सवाल और जवाब की सूरत में जो प्लानिंग कमीशन की तरफ से दिये गये हैं वे पढ़ देना चाहता हूं और वह यह हैं—

"Since the Plan is a practical one, with targets that are not unattainable, what are the essentials for its fulfilment ?"

इसका जवाब है—

(A) Freedom from world war and internal disturbances,
(B) Close co-operation between Central and State Governments,

[श्री सुल्तान आलम खां]

(C) Public co-operation,

(D) Honest and efficient administration.

जाहिर है कि गवर्नमेंट इसी तरफ चल रही है कि मुल्क और सूबे में शान्ति और अमन कायम किया जाय। मैं समझता हूं कि इस प्वाइंट पर अगर मैं कुछ ज्यादा कहूं तो शायद वह मेरे स्कोप के बाहर की बात होगी, इसलिये कि डिफेंस और सिक्योटिरी का मामला इस गवर्नमेंट से ताल्लुक नहीं रखता गवर्नमेंट आफ इंडिया से रखता है। लेकिन फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि जहां तक इंटरनेशनल पीस के कायम रखने का ताल्लुक है, जिस पर हमारे कांस्टीटयूशन ने सब से ज्यादा जोर दिया है, यह गवर्नमेंट उसकी तरफ पूरे तरीके से आगे कदम बढ़ा रही है।

दूसरी चीज जहां तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स का ताल्लुक है, कोई दो सवाल पैदा नहीं हो सकते कि उनमें कोआपरेशन नहीं है। लेकिन तीसरा सवाल पब्लिक कोआपरेशन का है। यह सबसे जरूरी और अहम है। अगर पब्लिक कोआपरेशन न हो तो कोई कानून आप बना लें वह कभी कामियाबी से चल नहीं सकता और उसके ऊपर सिर्फ सरकारी अधिकारी अमलदरामद नहीं कर सकते जब तक कि पूरा कोआपरेशन पब्लिक का न मिले। इसीलिये मैं सब से ज्यादा जोर पब्लिक कोआपरेशन पर देता हूं। इसी सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि मुल्क के अन्दर बहुत सी पार्टियां हैं, उनका एक पोलिटिकल प्रोग्राम है, उनके कुछ आइडियल्स हैं, सही है, वे अपने-अपने आइडियल्स पर कायम रह सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क की तरक्की, मुल्क की सिक्योरिटी के सिलसिले में सब लोग अपने तमाम एख्तिलाफात कबूल करके कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं कि जिसमें सबका कोआपरेशन हासिल हो। अगर यह कोआपरेशन हासिल हुआ तो इसके जरिये से फाइव इयर प्लान तरक्की कर सकती है और अगर ऐसा हो जाय तो इससे हमारा मुल्क बहुत आगे बढ़ सकता है और जैसा कि आनरेबिल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, वह तो यह उम्मीद रखते हैं कि अगर इसी किस्म से प्लान चलती रही तो २२ साल के अन्दर जितना प्रोडक्शन आज है उसका १०० फीसदी बढ़ जायगा।

अब दूसरा सवाल है:—

"What are the ways in which the public can contribute to the success of these projects ?"

तो उसमें भी कई चीजें दी हुई हैं और उसके अन्दर यह भी लिखा है:—

"By subscribing to the loans raised specifically for financing major irrigation projects by paying better fees and increased water rates."

दूसरी चीजें भी लिखी हैं। तो यह सही है कि अगर हमें इसको कामियाब बनाना है तो कुछ न कुछ अपने ऊपर सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। यह सही है कि बाज वक्त ऐसी बात भी हो सकती है, जिसके मुताल्लिक हमें गवर्नमेंट के सामने अपनी कुछ राय रखनी पड़े। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो इर्रीगेशन रेट्स दो मर्तबा बढ़ कर करीब सवा दो गुने हो गये हैं अब कीमत स्टेबिल हो गई हैं और काश्तकार की कमोडिटी की कीमत कम होती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के सामने मौक़ा है और वह इस पर जरूर गौर करेगी कि इर्रीगेशन के रेट्स में कहां तक कमी की जा सकती है।

जनाबवाला, इसी सूरत से हमारे सामने बहुत से महकमे हैं जिनमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन मैंने जैसा अर्ज किया कि जरूरत इस चीज की है कि हम अपने सजेशन्स कांक्रीट सूरत में दें और देने के बाद उन पर अमल करें। हमारे सूबे के अन्दर मुख्तलिफ महकमों की स्टैंडिंग कमेटीज हैं। जरूरत इस बात की है कि उनकी मीटिंग्स ज्यादा से ज्यादा काल हों और उनमें तमाम बिल्स आयें और इस बात का मौका मिल सके कि वह एडवाइज कर सके कि किस तरह से अपना प्रोग्राम चलायें। मुझे यकीन है कि हाउस के अन्दर और बाहर लोग इस नीति से काम लें और गवर्नमेंट को अपना सहयोग दें और मुझे कामिल यकीन है कि गवर्नमेंट उस सहयोग को जरूर कबूल करेगी तो कोई वजह नहीं है कि इस पांच साल के अर्से में जिसमें से तीन साल का अर्सा गुजर चुका है, हम इस काबिल न हो जायं कि जहां तक हमारे खाने-पीने का ताल्लुक है, हम बिल्कुल सेल्फ सफीशेंट हो जायं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को उनके बजट पर बधाई देना चाहता हूं। कल श्रीमन्, इस सभा भवन में माननीय विरोधी पक्ष के नेता के प्रवचन सुनने के समय मैंने बड़ी चेष्टा की कि उनके प्रिय वेद और मनुस्मृति के उस अध्याय को ढूंढ़ निकालूं जिससे कुछ ऐसे भी आदेश हों कि सभासदों को किस प्रकार से सभा भवन में कपोल कल्पना करनी चाहिये मैंने बड़ी चेष्टा की कि वितंडावाद के सम्बन्ध में मनु दादा का आदेश प्राप्त कर सकूं लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। पर इस सभा भवन में मुझे ब्रिटेन के प्रधान मंत्री मिस्टर डिजरेली की प्रेतात्मा दिखाई दी जो यह कह रही थी कि :—

"This shows how much easier it is to be critical than correct."

इससे यह प्रकट होता है कि आलोचना करना कितना सरल है और सही बात का कहना कितना कठिन है।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में जनतंत्र प्रणाली अभी नयी है, उसकी परम्परा बनाने में अभी तो कुछ देर लगेगी जो इस उत्तर प्रदेश में किसी विदेशी समाजवाद के आने पर इतना भाईचारा स्थापित कर सकते हैं वह तो विदेशी समाजवाद के प्रति कुछ न कुछ श्रद्धा रखते होंगे। १४ अप्रैल, सन् १९५३ ई० को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ था और तुरन्त ही वाद विवाद भी शुरू हो गया था, उस समय वहां पर विरोधी पक्ष के नेता श्री मौरीसन थे। मैं निवेदन करूंगा कि उस समय का उनका वह भाषण हमारे श्री राजनारायण जी पढ़ लें। वह भाषण कितना सौम्य और सुन्दर था। उन्होंने अपना भाषण प्रारम्भ किया वित्त मंत्री को बधाई देते हुये और उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये और उन्होंने आलोचना में यह कहा कि वह तो पुनः बाद में होती रहेगी। हमारे यहां श्रीमन्, मैं नहीं जानता कि कैसी परिपाटी चल रही है कि बजट के समय माननीय विरोधी पक्ष के नेता का भाषण शुरू होता है पर्दाफाश से, पर्दाफाश से नहीं, बल्कि पर्दाफास से। मैं नहीं जानता कि श्रीमान्, कि इस प्रकार की परिपाटी का भविष्य में चल कर क्या परिणाम होगा।

बजट के भाषण की परिपाटी के सम्बन्ध में कहने के बाद श्रीमन्, डाल्टन की थ्योरी से कल हमको कायल करने वाले हिमायती श्री राजनारायण जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने कभी डाल्टन की थ्योरी को पढ़ कर उसके बाद ब्रिटेन के श्री स्टैफर्ड क्रिप्स का भी नाम सुना है या नहीं। वे विश्वविख्यात समाजवादी थे। उनके विषय में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूं। अगर मैं गलत कहता होऊं तो वह मिस्टर राल्फ मोरले से पूछ लें कि सेल्स टैक्स और परचेज

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

टैक्स के जन्मदाता यही श्री स्टैफर्ड क्रिप्स थे और यह उनकी कितनी विचित्र बात थी कि जिस देश के लिये श्री विलियम कीनन के कथनानुसार इंगलैण्ड में ७०-८० लाख, ६ करोड़ की आबादी में से गरीबी की हालत में रहते हैं वहां पर उस टैक्स की दर समाजवादी क्रिप्स ने क्या मुकर्रर की। राजनारायण जी को मालूम है या नहीं। पांच औंस यानी ढाई छटांक टुबैको खरीदने के लिये जिसका दाम २० शिलिंग होता है, करीब १६ शिलिंग सैल्स टैक्स होता है। समाजवादी सरकार ने स्कूली किताबों तथा अन्य स्टेशनरी वग़ैरह जैसे कापी पेंसिल वग़ैरह पर यानी ६० स्कूली चीजों पर टैक्स लगा रखा है और विचित्र बात यह है कि जो आमदनी होती है उसका ७० प्रतिशत स्कूलों को ग्रांट के रूप में दे दिया जाता है। जब कि हमारे यहां आज सरकार ५ करोड़ से अधिक सेल्स टैक्स में कमाती नहीं और ९ करोड़ शिक्षा पर खर्च करती है। यह समाजवादी और कांग्रेसी न्याय का अन्तर है।

मुझे आश्चर्य होता है यह देख और सुनकर कि पता नहीं कैसे और कहां से श्री राजनारायण को यह मालूम हुआ कि इंगलैण्ड की पुलिस पर बजट का ०.७८ खर्चा होता है। इंगलैण्ड की पुलिस के बजट को जानने लिए और समझने के लिए बहुत कुछ सीखना चाहिये और जानना चाहिये। वहां पर पुलिस का खर्चा कई जगह होता है। वहां एक वेस्ट मिनिस्टर की पुलिस होती है उस पर अलग होता है। एक मेट्रोपोलिटन पुलिस होती है और शायद आपको यह सुनकर गर्व होना चाहिये कि हमारे इसी उत्तर प्रदेश का एक आई० पी० पुलिस अफसर उस मेट्रोपोलिटन पुलिस का कमिश्नर है। वहां एक लोकल गवर्नमेंट की पुलिस अलग होती है। उनको मालूम नहीं होगा कि क्लार्क ने लोकल गवर्नमेंट के बारे में क्या लिखा है। उनकी एक पुस्तक जो उस सम्बन्ध में है उसके पृष्ठ १३३ को देख लें उनको मालूम होगा कि जितनी लोकल गवर्नमेंट की पुलिस होती है उसके खर्चे का ५० परसेंट केन्द्रीय सरकार देती है। तो इस तरह से वहां पुलिस पर खर्चे अलग-अलग हैं। पता नहीं, उन्होंने कहां से ०.७८ परसेंट की बात कह दी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में हमारे कम्युनिस्ट भाई भी हैं जो पुलिस तथा अपराध के बारे में आलोचना कर दिया करते हैं। मैं उन बातों को छोड़ता हूं, क्योंकि मैं पुलिस के बारे में इस समय ज्यादा न कह कर बजट की और बातों के बारे में कहना चाहता हूं। पुलिस को गद्दार कह देना कम्यूनिस्टों की प्रणाली है, वे चाहते हैं कि पुलिस पैरेलाइज हो जाय और डेमारेलाइज हो, जिससे चारों ओर अव्यवस्था पैदा हो। लेकिन समाजवादी भाइयों को यह तनिक भी शोभा नहीं देता कि वे इंगलैण्ड की पुलिस से यहां की पुलिस का मुकाबला करें। वह ज़रा यह भी पढ़ कर देख लें कि जिस इंगलैण्ड की पुलिस की वह यहां बात करते हैं वहां २१९ आदमियों के पीछे एक पुलिस का आदमी है। यहां उत्तर प्रदेश में कानपुर में, जहां की पुलिस की संख्या सब से अधिक कही जाती है औसतन ५१६ आदमियों के पीछे एक पुलिस का आदमी है। पर हमारे इस पूरे प्रदेश में डेढ़ हजार आदमियों के पीछे १ पुलिसमैन आकर पड़ता है। ऐसे प्रदेश का इंगलैण्ड से मुकाबला करने चले हैं। जहां ४६१ पीछे एक क्राइम होता है, जब कि यहां २,०६९ पीछे एक क्राइम होता है। अगर वे कर सकते हैं तो मेरे इन आंकड़ों को गलत साबित कर दीजिये? २,०६९ की बात, मैं चुनौती दे कर कहता हूं कि उसे चाहिये कि जिस तरह से आधा भी कर दीजिये पर किसी भी युक्ति से इंगलैण्ड से अधिक साबित कीजिये।

कल स्वीडन की भी तारीफ कर दी गयी और ६,००० रुपया वहां के मजदूर की आमदनी बता दी गयी इस सदन में, जब कि आस्ट्रेलिया के मजदूरों की इनकम सब से अच्छी कही जाती है । और जिस स्वीडन की आपने प्रशंसा की जहां पर आमदनी और खर्चे के बारे में इतना अच्छा तारतम्य है, वहां अपराध की मात्रा इंगलैण्ड से भी बढ़ी है । वहां की रिपोर्ट देखने से पता लगेगा कि ३४१.४ एक लाख पीछे यानी २९३ व्यक्ति पीछे एक अपराध होता है । तो इन बातों को कहां तक समझाया जाय । कठिनाई यह होती है कि हम उन चीजों को बहुत दूर तक ले जाने की चेष्टा नहीं करते ।

मुझे तो आश्चर्य होता है कल के भाषण की बातों को सोच-सोच कर । पुलिस की बात तो हो गयी । मैं दो तीन बातें बजट के बारे में भी कहना चाहता हूं । हमारे मित्र बजट की महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं । माननीय बालेन्दुशाह जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बजट के भाषण में कई मार्के की बातें कहीं और मैं चाहता हूं कि सदन उन्हीं बातों की ओर जरा सोचने की चेष्टा करे । यह विचार हो सकता है कि गवर्नमेंट रिजर्व फंड के बारे में क्या कर रही है । कहा जाता है कि कैपिटल और अन्य एक्सपेंडीचर, कुछ चीजें ऐसी गड़बड़ हैं जिससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है । जहां तक पर कैपिटा आमदनी की बात है, हम सब जानते हैं । यह बात वित्त मंत्री भी जानते हैं और इसका उत्तर वे स्वयं दे देंगे पर अगर मेरे मन का आईना धुंधला नहीं है तो मैं भाई जयप्रकाश नारायण और अशोक मेहता को कुछ कहते सुन रहा हूं । वे कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना की बहुत सी चीजें अच्छी हैं और सब लोग उनमें सहयोग दें । अगर मेरे मन का आईना इतना गंदा नहीं हो गया है तो मुझे यह बातें साफ सुनाई पड़ रही हैं । मैं पूछता हूं राममनोहर लोहिया के हिमायतियों से कि प्वाइंट ट्वेंटी सिक्स के अपने प्रोग्राम को देखें, उसमें क्या कहा है । उसमें औद्योगिक प्रगति के बारे में भी तो कहा गया है । राष्ट्रपति के भाषण को सब ने सुना होगा जिसको आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी, जिसमें बतलाया गया है कि औद्योगिक प्रगति अपने देश में किस तरह से हो रही है । राष्ट्रपति ने कहा था, हमारे देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स १९५२ में १२९ था और १९५३ में १३४ हो गया था । एक-एक बात कैसे समझाई जा सकती है श्रीमन् । प्रगति हो रही है । प्रगति के लक्षण हैं । नहीं मानना चाहते हैं तो न मानिये । बुरा कहना चाहते हैं तो बुरा कहिये । लेकिन ईश्वर के लिए जो बात कहिये, सच तो कहिये । माननीय बालेन्दु शाह जी, चूंकि उनको पढ़ने का शौक है, माननीय राजनारायण जी से क्या कहूं.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत नामों पर माननीय सदस्य न आयें ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—हमारे इस बजट में ७७ करोड़ रुपये की इंडेटेडनेस स्पष्ट है, ३१ मार्च सन् १९५३ को । ३१ मार्च सन् १९५४ तक यह रकम ९५ करोड़ रुपये हो जायगी और ३१ मार्च सन् १९५५ तक यह रकम १९५ करोड़ रुपये हो जाती है । सोचने की बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में इतनी समाई है कि इस प्रकार के इन्डेटेडनेस को बर्दाश्त कर सके । यह खास तौर से विचार करने की बात बजट में होती है, इसके पीछे एक चीज और भी ध्यान में रखने की है । रेवेन्यू रिजर्व फंड की बात कही गई थी । ३८ करोड़ रुपया तो हमारे रेवेन्यू रिजर्व फंड में विभिन्न विभागों का है । २१ करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार को दूसरों से प्राप्त करना है जिसको उसने कर्जे के रूप में दिया था । साढ़े ११ करोड़ रुपया हमारे पास सिंकिंग फंड में है, कर्जे की अदायगी के लिये । हमारे असेट्स जो हैं इर्रीगेशन और इसी प्रकार के दूसरे महत्वपूर्ण वर्क्स को लेकर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इत्यादि को घटा कर यद्यपि

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को शामिल किया जाय तो कोई ग़लत नहीं कह सकता, इस प्रकार ८४ करोड़ रुपये के हमारे ये भी असेट्स हैं। १,५४,५०,००,००० रुपये के हमारे असेट्स हैं जब कि ३१ मार्च, सन् १९५४ को ९५ करोड़ रुपये का हमारा इन्डेटेडनेस है। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने भाइयों से कि इस प्रदेश के बजट को उठा कर देख लें और दूसरे प्रदेशों के बजटों को भी उठा कर देखें और यह बतावें कि इन्डेटेडनेस के मामले में, बहीखाते के मामले में हमारे प्रदेश की क्या परिस्थिति है। वह सब से आगे है अथवा नहीं। इस ७७ करोड़ रुपये की इन्डेटेडनेस को समझने की भी चेष्टा करनी चाहिये। ५६ करोड़ रुपया जमींदारी एबालिशन के बांड्स में रखा गया है जो सब नगद अदायगी नहीं की जा रही है और माननीय वित्त मंत्री मुझ से इस बात में जरूर सहमत होंगे कि यह एक बुक ट्रांजैक्शन है। इसलिये ७७ करोड़ रुपये को लेकर उसे भी सामने रखें तो कौन ऐसा है जो सच्चाई और ईमानदारी से इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि यह बजट एक बहुत ही ठोस बजट है। मैं एक बात और निवेदन करूं। पर्चेजिंग पावर की बात बहुत आसानी से कह दी जाती है। माननीय वित्त मंत्री इसका उत्तर देंगे ही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स की वसूली में कमी से और पर्चेजिंग पावर के प्रश्न से एक बहुत बड़ा अन्तर है। जब कि सिनेमा जाने वालों और थियेटर जाने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है लेकिन इंटरटेनमेंट टैक्स कम हो गया है। तो क्या कहीं हो सकता है कि बहुत सी चीजों में छूट दे दी गई हो लेकिन उनसे इन चीजों का अन्दाजा नहीं लगता है। अन्दाजा इन चीजों से लगता है कि कितना बिक्री हुई, कितनी आमदनी हुई और कितना खर्चा हुआ। मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि वह किसी एक महीने की बुलेटिन आफ स्टैटिक्स को उठा कर देखें तब उनको प्रगट होगा कि यह अनुमान गलत है और पर्चेजिंग पावर के घटने के विषय में बहुत कुछ कहने का फैशन हो गया है। यह चीज भ्रमपूर्ण है, गलत है। इसका अन्दाजा लगाना पड़ेगा कि वास्तव में परिस्थिति क्या है। पहली बात तो यह है कि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, उसकी वित्तीय नीति से है। दूसरी बात यह है कि हमको अपने उद्योगधंधों के विषय में जब तक हमारे प्रदेश की सरकार इस भ्रम में पड़ी रहेगी कि वह केवल अपनी योजना के द्वारा ही, पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही, या अपने उद्योगधंधों के द्वारा ही जनता की माली हालत को सुधार सकती है तब तक इस भ्रम के कारण वास्तविक रूप में जनता की माली हालत नहीं सुधार सकती है। इसके लिए एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। प्राइवेट उद्योगधंधों को, ऐसे कल-कारखानों को जिसमें वास्तव में लोग अपनी प्रतिभा को उपयोग में लायें उनको प्रोत्साहन देना होगा। तभी यह समस्या हल हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बड़ी तारीफ की जाती है। आज वहां पर इम्पालयमेंट के बारे में यह हाल है कि दस आदमी जो नौकर हैं उनमें से ९ आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और एक आदमी गवर्नमेंट में काम करता है जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में दस आदमियों के पीछे जो नौकरी करते हैं नौ आदमी गवर्नमेंट में काम करते हैं और एक आदमी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है। इस प्रदेश की कोई भी सरकार क्या इस प्रकार बेकारी की समस्या हल कर सकेगी जब तक प्राइवेट उद्योगधंधों में इतने बेकार आदमी न खपें।

बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि बजट पेश करने के बाद उनको दो दिन का अवकाश चाहिए। लेकिन उस पर राय कायम करने के लिये तथा अखबारों में देने के लिए एक मिनट के भी अवकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम आसानी से

कह दिया करते हैं कि इस बजट से जनता का क्या लाभ है। हमने केन्द्र से १९ करोड़ ८२ लाख रुपया कर्ज के रूप में लिया है। यह रुपया कहां चला जायगा। क्या यह रुपया वित्त मंत्री के पेट में जायगा? १ करोड़ ६५ लाख रुपया फर्टिलाइजर्स के लिए है। इससे किसके घर में खेती की जायगी?

बिजली की दर के बारे में बहुत कुछ कहा गया। क्या कभी किसी ने यह भी पता लगाया है कि बिजली की दर का कितना असर किन लोगों पर पड़ता है? सौ रुपया की आमदनी वाला आदमी दो तीन रुपये की बिजली खरीदता है। दो सौ से तीन सौ रुपये आमदनी का आदमी औसत, कम से कम मुझे बड़े बड़े शहरों का औसत मालूम है, दस सवा दस रुपये महीना है। वास्तव में अगर बोझा है तो पांच सौ रुपये से ऊपर वालों पर है जिसको करीब पचीस तीस रुपये महीना बिजली का देना पड़ता है। टैक्स के विरोधी कल कारखाने के वे लोग हैं जिनके हमारे प्रजा सोशलिस्ट भाई खिलाफ हैं और वही लोग इस बिजली के मामले को लेकर सबके काज को प्लीड करते हैं। जिस बिजली कर से, गरीब जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ता। केवल आठ आने या एक रुपया महीना पड़ता है लेकिन बड़े बड़ों पर २५, ३० रुपये महीना पड़ता है, वही लोग आकर बिजली कर का विरोध करते हैं। और उनके साथी हैं हमारे समाजवादी भाई।

कल मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ स्वायत्त शासन विभाग के बारे में सुनकर। कहा जाता है कि यह विभाग बहुत से काम अपने हाथ में लेता जा रहा है, श्रीमन्, मैं एक बात उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं जो लोग यह जानना चाहते हों कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन इंगलैण्ड में कैसे चलता है। एक छोटी सी पुस्तक है जेसेय की, उस पुस्तक को पढ़ें। मेरे मित्र मुस्करा रहे हैं। उन्होंने उसमें यह भी पढ़ा होगा कि अब इंगलैण्ड में और दूसरे देशों में इस बात पर जोर है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अब केन्द्रीयकरण होना चाहिए, विकेन्द्रीकरण नहीं।

श्रीमन्, २० मिनट में दो घंटे के भयंकर भाषण का उत्तर देना बहुत कठिन है। उनमें से कुछ बातों को मैंने सदन के सामने रखा और अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने सब से अनुरोध किया है कि इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में सम्मिलित हों। अध्यक्ष महोदय, यदि वे इसमें सम्मिलित हों तो हम उनका स्वागत करते हैं और अगर न भी सम्मिलित हों तो भी कोई चिन्ता की बात नहीं। परन्तु कांग्रेस का प्रत्येक सदस्य, यह सदन और सरकार का एक एक कर्मचारी इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए अपना खून पसीना एक कर देगा चाहे वे सम्मिलित हों या न हों। हमारा यही विश्वास है और हमारा यही मन्तव्य है।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को उनके बजट भाषण के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत ही सरल और सादी भाषा में हमारे सामने सन् १९५४–५५ का बजट पेश किया है और इस बात की सच्ची कोशिश की है कि वह हमको हमारे प्रदेश का एक सच्चा चित्र दे सकें। उनके बजट के भाषण पर विरोधी दल की तरफ से जो भाषण हुए उनको भी मैंने बड़े ध्यान से सुना। माननीय विरोधी दल के नेता ने इस बजट की रूपरेखा का वर्णन करते हुए कहा कि यह बजट तो वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं है बल्कि हमारी फ्रीडम्स को कुचलने वाला बजट है। फ्रीडम की व्याख्या तो उन्होंने नहीं की किन्तु यह अवश्य कहा कि यह सारी फ्रीडम्स का फेयरवेल है और उसमें प्रेस की फ्रीडम भी सम्मिलित है। मैं समझ नहीं पाया कि इस बजट से प्रेस की फ्रीडम कहां खत्म

[श्री नवल किशोर]

होती है। मैंने बहुत से अखबारों में बजट के सम्बन्ध में जो एडिटोरियल्स निकले उनको देखा, उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण तो बजट पर अवश्य पेश किये लेकिन मुझे किसी अखबार में यह देखने को नहीं मिला कि इस बजट से प्रेस की आजादी खतरे में पड़ गई है या पड़ सकती है।

इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि यह स्टेट्स की बजट है। मैं उनका ठीक अभिप्राय तो नहीं समझ सका और न इस विषय में ज्यादा दलीलों में ही जाना चाहता हूं क्योंकि विरोधी दल के नेता का अपना प्रिविलेज है वह जो चाहें कह सकते हैं। इसके बाद श्रीमन्, उन्होंने वेलफेयर स्टेट की भी काफी मजाक बनाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी साबित करने की कोशिश की कि यह कल्याणकारी राज्य नहीं है वह क्या साबित कर पाये यह तो वही जानें। श्रीमन्, मुझे इस विषय में सिर्फ यह कहना है कि यह दावा किसी का नहीं है कि उत्तर प्रदेश पूर्णरूप से कल्याणकारी राज्य बन चुका है। मेरा भी यही मत है कि अभी वह मंजिल दूर है। लेकिन इसमें भी सन्देह नहीं हो सकता कि हमारी कोशिश इस दिशा में है कि इस स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाया जाय और हम निरन्तर उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह हो सकता है कि जो हमारी गति हो या जो प्रगति हमने की है उस पर दो राय हों। यदि माननीय नेता विरोधी दल यह बताते कि हमारे प्रदेश में जो योजनायें चालू हैं उनकी स्पीड बहुत धीमी है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। या वह सिक्वेन्स आफ प्रायर्टीज के बारे में (priorities) कुछ बतलाते कि इसमें यह तब्दीली हो सकती है, कुछ योजनायें जो पहले आनी चाहिये थी बाद में रख दी गई हैं और जो पहले रख दी गई हैं वे बाद में आनी चाहिये थीं तो उनके भाषण से हमें भी व सरकार को भी कुछ लाभ होता। लेकिन श्रीमन्, यह कहना कि इस राज्य में कुछ नहीं हो रहा है, यह स्टेट्स को किस्म का बजट है और इसके अन्दर गरीबों की गरीबी बढ़ेगी और एक्सप्लायटेशन कायम रहेगा, मैं समझता हूं कि कहने को तो चाहे जो कुछ भी कह दिया जाय, लेकिन निष्पक्षता के साथ अगर इस आरोप को तौला जाय तो यह निराधार तथा व्यर्थ ही मालूम होगा। सच्चाई के साथ ऐसी खिलवाड़ वही कर सकते हैं।

इसके बाद उन्होंने सबसे पहले टैक्सेशन पर हमला किया। उन्होंने बतलाया कि ७, ८ किस्म के टैक्सेज हैं। मैं, श्रीमन्, सबका जिक्र तो नहीं करूंगा केवल दो तीन के बारे में कुछ कहूंगा। उन्होंने यह पूछा कि क्या वजह है कि हमने आबपाशी के रेट बढ़ा दिये हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने सन् ४६ के बजट के आंकड़े पेश किये जो ३० करोड़ का था। श्रीमन्, मैं भी उनके सामने कुछ आंकड़े पेश कर देना चाहता हूं। बजट के सन् ४६ के आंकड़ों से जो उन्होंने तुलना की थी तो मैं भी श्रीमन् आपकी आज्ञा से बजट भाषण से एक दो लाइन इस सम्बन्ध में पढ़ना चाहूंगा। सन् १९४५-४६ के बजट में सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य पर केपिटल एक्सपेंडीचर ४९ लाख रुपये का था जब कि अब वह १० करोड़ ५५ लाख हो गया है। सन् ४५-४६ में ५२ लाख रुपये पूंजी व्यय के रूप में बिजली योजनाओं के ऊपर खर्च होते थे जब कि अब वह बढ़कर १० करोड़ २४ लाख हो गये हैं। पहले उद्योग और विकास की योजनाओं पर कुछ खर्च नहीं होता था जब कि अब १ करोड़ १६ लाख रुपये उन पर खर्च होने जा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आबपाशी की योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है तो यह रुपया टैक्स से नहीं आयेगा तो कहां से आयेगा। जब हम चाहते हैं कि हर साल ७०० या ८०० नलकूप बन कर तैयार हो जायं तथा सारे प्रान्त में नलकूपों का एक जाल बिछ जाय तब उसके लिये

कहां से वह रुपया आयेगा। फिर श्रीमन्, आबपाशी का रेट तो सच्चे मानी में टैक्स कहा भी नहीं जा सकता है।

इसके बाद उन्होंने बिजली की दरों की भी बात कही। उसका जवाब मैं देना नहीं चाहता क्योंकि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने काफी प्रकाश उस सम्बन्ध में डाल दिया है।

इसके बाद सेल्स टैक्स के ऊपर बड़ी भारी टिप्पणी की। सेल्स टैक्स का जहां तक सम्बन्ध है और जहां तक मेरी मालूमात हैं हमारे प्रदेश में सेल्स टैक्स से ५ करोड़ से भी कम ही रुपये मिलते हैं। जब कि इससे छोटे प्रदेशों मद्रास और बम्बई में १४ और १८ करोड़ रुपया सेल्स टैक्स में आता है। हां, सेल्स टैक्स के असेसमेंट के तरीकों से हमारे व्यापारी वर्ग में जो असन्तोष है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिये और जो उनकी उचित कठिनाइयां हैं वह अवश्य दूर होनी चाहिये।

उन्होंने यह भी कहा कि वेलफेयर स्टेट की बात तो कही जाती है लेकिन यह नहीं बताया गया कि पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी घटी है। मुझे यह तो नहीं मालूम है कि पिछले साल से कुछ बढ़ी है या नहीं लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि सन् ४२ में यह वार्षिक पर कैपिटा आय २४२ रुपये थी और सन् १९५२–५३ में यह २५३ रु० हो गई। यह कहा जा सकता है कि वह कम बढ़ी है लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वह बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि लगान में छूट दी जाय और उन्होंने बताया कि कुछ ग्रेड्स में २ आने और कुछ केसेज में १ आना रुपये की छूट की बात उन्होंने कही थी। श्रीमन्, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज की स्थिति वही है जो उस समय थी जब कि कमेटी ने उक्त सिफारिशें की थीं। आज चाहे गल्ले के दाम कुछ गिर भी रहे हों फिर भी क्या यह सच नहीं है कि बीच में इनकी कीमतें दस गुना तक हो गई थीं और लगान एक पाई भी नहीं बढ़ाया गया था। रुपये के उस समय के मूल्यांकन में वह स्वयं ही दो आने के बराबर रह गया था और आज भी ३ आने या ४ आने से ज्यादा नहीं है—यदि यह घटना नहीं है तब क्या है?

हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात के लिये एक भी शब्द नहीं कहा कि पहले जहां यह प्रदेश लाखों मन गल्ला बाहर से मंगाता था अब वह सेल्फसफीशेंट हो गया है और कुछ समय बाद जब हमारी विकास योजनायें पूरी हो जायंगी तब हमारा उत्पादन इतना बढ़ जायगा कि हम बाहर भेजने लगेंगे। कपड़े के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा जब कि हमारी कपड़े की समस्या पूरी तौर से हल हो गई है और हम अपने पंचवर्षीय योजना में निश्चित टारगेट से भी बहुत आगे बढ़ गये हैं। मकानों के सिलसिले में भी एक शब्द नहीं कहा कि कितने हजार मकान अब तक बनाये गये हैं। स्वागत करने की बात यह भी है कि मध्यम वर्ग के लिये मकान बनाने के लिये एक कमेटी नियत की जायगी और उसकी सिफारिशों पर सरकार एक विशाल योजना तैयार करेगी।

इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन कायम करने की बात एक नया फीचर है। इसके लिये वित्त मंत्री और भी अधिक बधाई के पात्र हैं। इससे हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधों में और भी तेजी से प्रगति होगी। मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए यह कहूंगा कि जितनी विकास और प्रगति की योजनाएं इस प्रदेश में चल रही हैं उतनी किसी भी अन्य प्रदेश में नहीं हैं और यह हमारे लिए गर्व तथा गौरव की बात है। शिक्षा का भी जिक्र

[श्री नवल किशोर]

किया और उनकी टिप्पणी का मुख्य आधार यह था कि हमारे प्रदेश में २३ फीसदी ही बच्चे स्कूलों में जाते हैं जब कि कुछ और प्रदेशों में ९८ फीसदी तक जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे यहां क्वान्टिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिये बजाय क्वालिटी के। यह सिद्धान्त की बात है। कुछ लोग क्वान्टिटी को ज्यादा अच्छा समझते हैं और कुछ लोग क्वालिटी को। लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो क्वालिटी को ज्यादा पसन्द करते हैं। इस समय हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि आज के ग्रेजुएट को देख कर अफसोस होता है उसकी नालेज पर। बहुत से ग्रेजुएटों से तो पहले के मैट्रिक अच्छे हैं। उन्होंने बहुत से महानुभावों और शास्त्रियों को कोट किया लेकिन मैं केवल इस सिलसिले में उनका ध्यान सन्त विनोबा जी ने जो विचार एजूकेशन के बारे में व्यक्त किये हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। उनका विचार है कि यदि शिक्षा पद्धति में मूल तब्दीलियां नहीं होती हैं तो जो स्कूल और कालेजेज हैं उनको बन्द कर दिया जाना चाहिये। मैं इन विचारों से इत्तफाक करता हूं। श्रीमन्, जबकि शिक्षा पद्धति पर चारों तरफ भीषण टीका-टिप्पणी हो रही है तो पहले सरकार का ध्यान सिस्टम आफ एजूकेशन के बदलने की ओर जाना चाहिये न कि इस तरफ कि स्कूल्स बढ़ाये जायं या न बढ़ाये जायं। इस सिलसिले में भी जो नयी चीज की गयी है उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। वह यह है कि तीन हजार जूनियर हायर सेकेंड्री स्कूल्स जो देहातों में हैं उनमें कृषि शिक्षा का इन्तजाम जुलाई, ५४ से किया जा रहा है यह एक नयी चीज है। इन स्कूलों में आमतौर से देहाती जनता शिक्षा पाती है जिसका मुख्य कार्य कृषि ही है। अगर उनके बच्चे इस शिक्षा को पायेंगे तो उन पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और वे जब बड़े होंगे तो हमारे देश के अच्छे नागरिक बन सकेंगे तथा वैज्ञानिक ढंग से खेती करने में निपुण हो जायेंगे।

श्रीमान् जी, इसके बाद एक बात यह भी कही गयी कि पिछले वर्ष में एजूकेशन और मेडिकल की मदों से बहुत सा रुपया बचा कर पुलिस की मद में खर्च किया गया है। मैं यह तो नहीं कहता कि पुलिस का विभाग एक आदर्श स्थिति पर पहुंच गया है। उसमें आज भी कमियां हैं। परन्तु श्रीमन्, आज जो स्थिति है, जो आज के सरकमस्टेंसेज हैं तथा जो आज के ऐनवायरोमेंट्स हैं, उनको देखते हुये इस विभाग को मजबूती के साथ रखना अनिवार्य है।

इसके बाद उन्होंने यह भी शिकायत की कि ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी हो रहा है। श्रीमन्, इस प्वाइन्ट पर मैं भी किसी हद तक उनसे सहमत हूं। मैं भी यह महसूस करता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी हो रहा है और हाई आफीसर्स को जो तनख्वाहें हैं उनका यदि जन-साधारण की आय से मापदंड स्थापित किया जाय तो उसका जो रेशियो होगा वह १:१०० और किसी किसी केस में २०० वा ३०० तक होगा। मैं यह जरूर चाहता हूं कि इसको शीघ्र कम किया जाय। मुझे मालूम हुआ है कि इस सिलसिले में एक ऐकोनोमिक कमेटी भी बैठी हुई है, मुझे आशा है कि वह इन बातों पर विचार करेगी और जो अपव्यय होता है उसको भी दूर किया जायगा। ऐसा होना भी एक स्वागत की बात होगी। मुझे विश्वास है कि कमेटी अपने इस कार्य में सफल होगी और यह डिस्पैरिटिज भी शीघ्र दूर हो जायेंगी।

अन्त में मैं एक बात यह भी कह देना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने जो एक अपील विरोधी पार्टी से और अपने प्रान्त के सभी निवासियों से की है कि वे सरकार की इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में अपना सहयोग दें, इसकी ओर मैं विरोधी पार्टी के नेताजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन्होंने इस सिलसिले में प्वाइंट फोर्टीन प्लान का जिक्र किया है। प्वाइन्ट फोर्टीन की बात बाबू जयप्रकाश नारायण और माननीय पं० जवाहर लाल नेहरू के बीच में हुई थी वह हाइऐस्ट लेबिल की बात है। मैं उसका जिक्र इस सदन में क्या

करूं और क्या उसका जवाब दूं परन्तु जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि यदि हमारे फोर्टीन प्वाइन्ट मान लिये होते तब इस अपील की जरूरत ही न होती । सो मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि प्वाइन्ट फोर्टीन कोई मेगनाचार्टा हो गया है कि अगर वह न माना जाय तो किसी प्रकार का कोई सहयोग हो ही नहीं सकता । ऐसी दलील मैं मंजूर नहीं कर सकता । यदि हम ढूढें तो राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी रोजमर्रा के राष्ट्रीय व सामाजिक जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनमें हमारा सहयोग आपस में हो सकता है और सरकार और विरोधी पार्टी एक दूसरे के साथ कोआपरेट कर सकते हैं और जितनी डिफरेंसेज की बातें हैं उनको कम से कम भी किया जा सकता है । हमको प्वाइन्ट्स आफ एग्रीमेंट अधिक खोजने चाहिये । मुझे विश्वास है कि यदि हमें उनका सहयोग प्राप्त हो, यदि हम और वे सद्भावना से मिलकर काम करें तो हम अपने कल्याणकारी राज्य के ध्येय पर शीघ्र पहुंच सकेंगे तथा अपने देश की चतुर्मुखी उन्नति करने में सफल होंगे ।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले श्री बी० जी० राऊ, फाइनेंस सेक्रेटी, जिन्होंने इस बजट को तैयार करके हमारे सामने इस रूप में दिया है, उन्हें धन्यवाद देता हूं और उसके साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारी लोगों और साथ ही साथ माननीय वित्त मंत्री जी का भी जिन्होंने एक घंटा ५० मिनट में उस दिन बड़ी मेहनत के साथ अपने भाषण को पढ़ा और मुझे वास्तव में तरस आता था कि चाय पी पीकर उसे पढ़ भी रहे थे और.....

श्री अध्यक्ष—वह चाय नहीं थी ।

श्री मलखान सिंह—मैं अपने को करेक्ट कर लेता हूं वह सन्तरे का रस था । मुझे यह भी पता है, इसके लिये मैं उनको दोष नहीं दे सकता कि कहीं कहीं पर हिन्दी भाषा पूर्ण रूप से न जानने के कारण वाक्यों का सन्तुलन नहीं हो पाता था लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की और इसके लिये मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं ।

अब मैं आपके सामने जो बजट की मुख्य बातें हैं उनके बारे में आमतौर पर कुछ अपने विचार जाहिर करूंगा । साथ ही साथ श्री परिपूर्णानन्द जी तथा दूसरे लोग जो हमारे सामने बैठे हैं उनके सामने यह भी मैं दावा रखूंगा कि मैं जो कुछ भी बात कहूंगा उसमें कहीं पर असत्य की मात्रा कोई बतला दे तो मैं अपनी गल्ती को स्वीकार कर लूंगा । लेकिन अगर उन्हें सत्य बात मालूम पड़े तो उन्हें और सरकार को मेरी बात मान कर चलने के लिये तैयार होना चाहिये । एक बात बड़ी मुश्किल है और हम सभी जानते हैं कि एक सत्य बात कहीं पर कही जाय तो उसे शायद एकान्त में सुनने के लिये हम तैयार होते हैं, लेकिन अगर पब्लिक में वही सत्य बात कही जाय तो उसे सुनने के लिये अधिकतर लोग तैयार नहीं होते । मैं यह चाहता हूं कि कम से कम सरकार के अन्दर यह साहस होना चाहिये कि सत्य बात को सुने और उसके ऊपर आचरण करना भी सीखे ।

जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसके बारे में मुझे यही कहना है कि वह एक तरह से दिवालियेपन का नंगा रूप प्रत्यक्ष करता है । हमारी सरकार का सिद्धांत है कि साल ब साल कुछ घाटे का बजट पेश किया जाय । "ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्" इस नीति के अनुसार हमारी सरकार काम करती है कि कर्जा खूब कर लो लेकिन घी पीते जाओ । हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट स्पीच में स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश के रहने वालों के जीवन का स्तर यानी स्टैंडर्ड आफ लिविंग बहुत नीचा है, वे गरीब हैं । उनमें शिक्षा यानी तालीम की कमी है । उनकी खेती घटिया है और उनके यहां इतने उद्योग धंधे नहीं हैं जिनमें उन सब को काम मिल सके और जो कुछ उद्योग धंधे हैं वे भी कमजोर हैं । बीमार होने पर उनको इलाज में काफी साधन नहीं मिलते और बहुत से लोग बेरोजगारी के शिकार बने रहते हैं और ये हैं कौन ? काश्तकार, जिनकी बड़ी बहुमत या अक्सरियत है, मजदूर, दस्तकारी पेशा, तिजारतें करने वाले, पढ़ाने वाले

[श्री मलखान सिंह]

और दूसरा पेशा करने वाले वगैरह वगैरह। ये सब बातें हैं जो उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ स्वीकार की हैं लेकिन मैंने तमाम बजट को पढ़ा तो देखा कि उनके स्टैंडर्ड आफ लिविंग को ऊंचा करने के लिये या जो बेकार हैं उनको काम देने के लिये या जो अध्यापक हैं उनके आंसू पोंछने के लिये या जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड्स के अन्दर या सरकारी दफ्तरों, जैसे कलेक्टरेट या जजेज कोर्ट हैं, उनमें जो नीचे के वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं या चपरासी हैं या पुलिस वाले हैं, उनके वेतन के बारे में जरा भी कहीं पर धेला आठ आना या रुपया की बढ़ती इस बजट में नहीं पाता हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे गरीबों के स्टैंडर्ड आफ लिविंग के ऊंचा करने की कोई भी बात इस बजट में नहीं मिली। मैं यह भी साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस बजट स्पीच में ऐकोनोमिक ड्राइव की भी बड़ी प्रशंसा की गयी है कि बहुत सी जगहों पर खर्चे में कमी की गयी है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने माननीय मुख्य मंत्री का एक सर्क्यूलर पढ़ा जो जिलाधीशों के सामने आया था जिसमें यह था कि अपने अपने मदों में जो आप लोग मोटर वगैरा चलाते हैं, उसमें पेट्रोल के रूप में जितना भी खर्च करते हैं उसमें जितनी भी कमी कर सकें वह करनी चाहिये। यह तो वह सर्क्यूलर था परन्तु यह सब होते हुये भी हम देखते हैं कि जब हमारे मंत्री लोग जिलों में दौरा करने के लिये जाते हैं तो अगर वहां पर पुलिस की जीप आगे या पीछे न चले तो वे दौरे पर नहीं जा सकते हैं अगर उन्होंने जरा भी देर कर दी तो टेलीफोन होता है कि मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं। जीप क्यों नहीं आयी जब कि वे जानते हैं कि हर जगह उनका बहुमत है। हर जिले में कांग्रेस के एम० एल० एज० हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन के पास जीप है, वहां की कांग्रेस कमेटी के पास जीप है, यह सब होते हुये मंत्रियों को पुलिस गार्ड की जीप जरूर चाहिये और साथ ही यह भी कि उनके साथ एक आदमी सी० आई० डी० का रिवाल्वर लिये सादी ड्रेस में रहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां पर इन सब बातों में फिजूल खर्ची को रोक देना चाहिये वहां पर यह सब कायवाही दिखाने के लिये क्यों की जाती है। असल में अब वह जमाना नहीं रहा है कि वे आम लोगों के बीच में जायं और अपना रोब दिखायें। अगर वास्तव में सरकार अपने को वेलफेअर स्टेट कहती है और वह जनता की भलाई के लिये है तो गरीब लोगों के बीच में जाकर उनकी हालत को सुनना चाहिये। उनके दुख दर्द को सुनना चाहिये और उनकी विपदाओं को देखना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब कि यह तमाम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कप्तान या पुलिस वाले उनके साथ न हों। यह मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो कि सत्य से अलहदा हो। अब मैं समझता हूं कि अब गवर्नमेंट ऐसी स्थिति में आ गयी है कि यह जो बाहर का दिखावा है इस सबको छोड़कर जो मिनिमम खर्चा है उसी पर उसको आना चाहिये और उन्हें इस फिजूलखर्ची को रोक देना चाहिये तथा जोरों के साथ रोक देना चाहिये। मैं आपसे यह भी कह देना चाहता हूं कि इकोनोमिक ड्राइव के सिलसिले में मैं भी जानता हूं, आप सब लोग भी जानते हैं कि हरएक जिले में पुलिस के ३-३, ४-४ इंसपेक्टर्स होते हैं। मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आयी कि जहां पर थानों की संख्या बढ़ गयी है, शहरों में चौकियों पर भी थाने हो गये हैं, वहां पर इन्सपेक्टरों की अब क्या जरूरत है। इन्सपेक्टर्स, जितने भी ऐसे मुहकमें हैं उनमें बजाय सहायता के काम में दखलअन्दाजी ही करते हैं। मेरा सुझाव यह है कि पुलिस इन्सपेक्टरों को दूसरी जगह पर लगा देना चाहिये और इन्सपेक्टर जैसी जगह नहीं रहनी चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के सामने जो कैनाल मैजिस्ट्रेट्स रखे गये हैं जो गांव वालों के पानी के संबंध में मुकदमें करते हैं, उनके बारे में तजुर्बा यह है कि उनकी वजह से किसानों पर ज्यादा मुसीबत आती है इस बात को भी कहा गया है कि मुकदमे बहुत दूर दूर फेंके जाते हैं यानी २०–२०, ४०–४० मील तक फेंके जाते हैं। ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूं कि जब आपके कलेक्टोरेट में, हेडक्वार्टर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स की कमी नहीं, आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स की कमी नहीं है, डिप्टियों की कमी नहीं है और वे नहरों के भी मुकदमों को आसानी

से कर सकते हैं, उन पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, किसानों को जो हेडक्वार्टर्स पर आना पड़ता है और उससे जो खर्च होता है वह भी रुपया बचेगा। तो मेरा गवर्नमेंट के सामने यह भी एक सुझाव है कि नहर के जो डिप्टी हैं जिनको मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कि हमारे खर्चे को बढायें उनसे उनकों हटा करके किसानों के मुकदमें दूसरे अन्य मैजिस्ट्रेट लोगों के हाथों में दे देना चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि पश्चिमी जिलों में जैसे मेरठ, बुलन्दशहर और अलीगढ़ इन जिलों में सिंचाई विभाग में नहरों के साथ ही साथ ट्यूबवेल भी चल रहे हैं। वहां पर दोहरे दोहरे डिप्टी, दोहरे दोहरे ओवरसियर, दोहरे दोहरे असिस्टेंट इंजीनियर और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और इनका एक तांता लगा हुआ है। इस बजट में कभी इस बात की कोशिश नहीं की गई है कि ऐसे सब मुहकमों के कर्मचारियों को कम करके किसी तरह से खर्चा घटाया जाय। मैं यह भी बता देना चाहता हूं, केवल उदाहरण के तौर पर कि जहां नलकूपों की तारीफ की जा रही है कि प्रतिवर्ष ८००, ९०० नलकूप बन जाते हैं, मेरे जिले में ९६ ए० बी० एक नलकूप है जो दो वर्षों से बेकार पड़ा हुआ है। हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब गये थे उनके भी कान में बात कही गई लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। जिन लोगों को वहां से पानी मिलता था वे सब बेकार बैठे हैं। उन्होंने अपने कुओं को भी खत्म कर दिया और भी सिंचाई का सामान खत्म कर दिया था और अब उनकी निगाह लगी हुई है कि ट्यूबवेल ठीक किया जाय, लेकिन दो वर्ष हो गये हैं अभी तक ठीक नहीं हो सका है। यह सब ऐसी बातें हैं कि सिंचाई तो दूर रही लेकिन सिंचाई का टैक्स हम लोगों के ऊपर लादते चले जाते हैं।

अभी हमारे उधर के साथियों ने कहा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि इस सरकार ने इस साल कोई नया टैक्स लगाने का इरादा नहीं किया है लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पिछले दो तीन सालों में लोगों पर टैक्सेशन लाद दिया है जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में टैक्स, पंचायतों के टैक्स, अलावा अबवाब के और आबपाशी टैक्स के और इस तरह से किसानों की कमर तोड़ कर क्या आप हिम्मत रखते थे कि कोई नया टैक्स तजवीज करते। इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री ने दबे शब्दों में यह भी कहा है कि अगर हमारी पंचवर्षीय योजना के चलाने में रोड़ा अटका तब हम टैक्स की बात सोचेंगे। इसलिये मैं कह देना चाहता हूं कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जो बड़ी तारीफ की हो। जब आप पहले से ही बोझा लाद चुके हैं, पिछले दो तीन सालों में और आज यह कहते हैं कि अब हमको नया बोझा लादने के लिये नहीं जा रहे हैं और उस पर तालियां पीटी जायं, मैं समझता हूं कि यह कोई श्रेयस्कर बात नहीं है।

मैं साथ ही यह भी बता देना चाहता हूं कि मुहकमा हेल्थ की बड़ी खराब हालत है। चेचक की बीमारी से एक-एक गांव में, जिसकी आबादी एक हजार के करीब थी, दो-दो सौ तीन-तीन सौ बच्चे चेचक के शिकार हुये हैं और बहुत से कुटुम्ब तो ऐसे हैं कि जिनमें बच्चे ही नहीं रह गये हैं। आप का हेल्थ डिपार्टमेंट जितना खर्चा करता है और जितने आंकड़े कागज पर दिखलाये जाते हैं कि कितने टीके लगे और क्या होता है यह कुछ समझ में नहीं आता है। उसकी खराबियों को तो माननीय वित्त मंत्री जी ने भी माना है कि उसका ठीक ठीक इन्तजाम नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से जितना खर्चा होता है वह सब उसमें से काट देना चाहिये, जब तक कि यथार्थ में यह न देखा जाय कि गरीबों को और गांव के लोगों को ठीक-ठीक दवा वक्त पर मिल जाती है।

अभी-अभी हमारे भाई नवलकिशोर जी ने इस बात पर रोशनी डाली कि हमारी गवर्नमेंट शिक्षा के प्रति क्वालिटी का ज्यादा ख्याल कर रही है और क्वांटिटी का कम ख्याल कर रही है और इसकी विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने कुछ मुखालिफत की थी। मैं यह कह देना चाहता हूं कि आज यह जितनी चीजें हैं इनसे आप लोगों को ज्यादा दिन तक अन्धेरे में नहीं रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे महत्व की बात यह है कि आपको मासेज (जनता) को एजुकेशन जल्दी से जल्दी देनी चाहिये। आज भी किसान रोता है और यह कहता है कि कागज पर उसका निशान अंगूठा लगवा लिया गया। हमारे पास इस तरह के बहुत केसेज आते रहते हैं कि जब उनकी गर्दन कट जाती है तब वह कहते हैं कि उनको जिन्दा करो। इसलिये

[श्री मलखान सिंह]

मैं आपसे कहता हूं कि मासेज को 'अ' 'आ' 'इ' 'ई' और दस्तखत करने की शिक्षा देना सख्त जरूरी है। जब तक आप प्राइमरी शिक्षा मुफ्त और गांव गांव में नहीं कर देंगे तब तक आप की कोई स्कीम किसान के समझ में नहीं आ सकती है और न वह हिम्मत से खड़े होकर आपकी मदद कर सकता है। आप क्वालिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सिटीज को आप गरीबों का पैसा गवर्नमेंट के खजाने से देते हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर्जे में चल रही है और आप यहां से ग्रांट दे देते हैं। इन यूनिवर्सिटीज में गांव का किसान जिसके पास ५० बीघा खेत है उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिये नहीं जा सकता है। मैं एक बात कटाक्ष के नाते से नहीं लेकिन फैक्ट के नाते से कहूंगा कि जो बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले अफसर हैं या तो जो धनीमानी लोग हैं उन्हीं के लड़के जा करके यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जब मुकाबिले की बात आयेगी तो गरीबों के लड़कों की वैसी ही हालत होगी जैसी कि हरिजन भाइयों की रोज यहां पर होती है कि रोज वह रोया करते हैं कि हरिजन १८ फीसदी नहीं आये, उनको १८ फीसदी लिया जाय। यह जो रोज का रोना है यह जो रोज हमारे हरिजन भाइयों की तरफ से आंसू बहाये जाते हैं, यह हमेशा रहेगा जब तक कि शिक्षा का जो खर्चा है वह गरीबों के ऊपर से कम नहीं किया जायगा। आप कितना ही रो लें लेकिन आप कभी मुकाबिले में आ नहीं सकते उन लोगों के जो उच्च से उच्च शिक्षा पाने के लिये अपनी जेबों में पैसा रखते हैं।

मैं आपके सामने इस बात का थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि यह सब कुछ होते हुये भी यह कहा जाता है कि हमने ग्राम पंचायतों का चुनाव हटा करके ७० लाख रुपया बचाया। मुझे इसके ऊपर जोरों के साथ आवाज उठानी चाहिये कि गवर्नमेंट को यह अख्तियार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये कि चुनाव की मियाद समाप्त होने पर वह चुनाव न कराये। यह कोई कांस्टिट्यूशनल बात नहीं है बल्कि यह अशोभनीय बात है। फिरोजाबाद और अलीगढ़ की म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव अब तक हो जाने चाहिये थे। लेकिन वह अभी तक नहीं कराये गये हैं और यह शोभा की बात नहीं है।

अब जल्दी से आपके सामने कुछ बातें उदाहरण के तौर पर रखूंगा इसलिये कि यहां पर सदस्यों ने कल्याणकारी राज्य की बहुत बड़ी डींग हांकी है। मैं केवल नमूने के तौर पर आपके सामने, ५-६ बातें आंकड़ों के तौर पर रखूंगा। आशा है कि आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे। हमारे यहां हतीसा भगवन्तपुर, पी० ओ० हाथरस, जिला अलीगढ़ में मूलचन्द पंचायत का प्रधान है। वे एक नुमाइश में गये, वह नुमाइश जो देहातों में जिला मैजिस्ट्रेट की ओर से लगती है। मैं पत्र पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है कि मैं २,४०० रुपये की एक बैलों की जोड़ी लेकर गया और एक दूसरा काश्तकार गया जिसकी बैलों की जोड़ी १,४०० रुपये की थी। सब गांव वालों ने कहा कि मूलचन्द की सबसे नम्बर एक जोड़ी है और उसे पहले नम्बर का इनाम मिलना चाहिये लेकिन उसको नम्बर ४ कर दिया गया। उसने यह कह दिया कि मैं चौथे नम्बर का इनाम नहीं लेता, मुझे लोग नम्बर १ कहते हैं। तो डी० एम० इतने नाराज हो गये कि कुछ कहना नहीं और कुछ लोग, खासतौर से कांग्रेसी मेम्बर लोग कहने लगे कि जिला मैजिस्ट्रेट साहब नाराज हो गये हैं माफी मांग लो। उस बेचारे ने माफी भी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिये और चौथे नम्बर का ही इनाम दे दीजिये। लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं अपने हाथ से नहीं दूंगा और दूसरे से उसको चौथे नम्बर का इनाम दिलवाया। उसके कुछ दिन बाद संचालक, पंचायतराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की ओर से पत्र संख्या ४६४४-पी-५३, दिनांक २२-९-५३ में यह आज्ञा की गई कि तुम प्रधान पद पर रहने योग्य नहीं हो। वह कहता है कि मैं प्रधान की हैसियत से तो उस नुमाइश में गया ही नहीं था, गांव के एक किसान की हैसियत से गया था और वह बेचारा निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ये प्रश्न कटौती के वक्त में आप रख लीजियेगा। आपको फिर मौका दिया जायगा।

श्री मलखान सिंह—मुझे आशा है कि आप एक और बात मुझे रख लेने देंगे।

श्री अध्यक्ष—उससे नतीजा क्या होगा ?

श्री मलखान सिंह—मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं कि यह जो कहा जाता है कि एक कल्याणकारी राज्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो मैं आपके सामने यह कह रहा हूं कि यहाँ पर गरीबों की सुनने वाला इस कल्याणकारी राज्य में कोई नहीं है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से वित्त मन्त्री को उनके इस बजट के लिए बधाई देता हूं, केवल उस रूप से नहीं जैसा कि परिपाटी है किन्तु मैंने जान-बूझ कर कहा कि मैं हृदय से बधाई देता हूं, केवल इसलिये कि नहीं कि उन्होंने एक बजट रखा, स्पष्टवादिता के लिये भी। मैं सचमुच हैरान हूं, जब कि विरोधी पक्ष ने उस स्पष्टवादिता के क्या क्या अर्थ इस सदन के समक्ष रखे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस प्रदेश में गरीबी है, भुख मरी है, रोग है, अविद्या है, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जो बड़ी बड़ी योजनायें चल रही हैं उनसे इस प्रदेश पर कर्ज का भार बढ़ता जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि इस सब के लिये यह प्रदेश एक विपुल प्रयास में लगा हुआ है और अन्त में उन्होंने विरोधी पक्ष के भाइयों से एक मार्मिक अपील की है जिसमें उन्होंने चाहा कि वे उनके साथ कन्धा से कन्धा मिला कर इस प्रयास में सहयोग दें। मैंने इस वर्ष का जो बजट है उसका अध्ययन पूरे तौर पर किया या नहीं, शायद माननीय राजनारायण जी ने मुझसे अधिक किया है, लेकिन जो कुछ भी आंकड़े इस सदन के समक्ष आये वे जो भुखमरी, गरीबी, रोग और अविद्या हैं उसको दूर करने को विपुल प्रयास की एक कहानी मानों स्वयं कहते हैं। कैसे उन आंकड़ों को माननीय राजनारायण जी ने अपने दो घंटों के भाषण में भूलकर और उसी पुरानी परिपाटी के अनुसार पुरानी रटी हुई कहानियां, पुराने अभियोग, मालगुजारी की बढ़ोत्तरी, मिनिस्टर साहबान की तनख्वाह, मिनिस्टर साहबान के दौरे और १५० और शिकायतें इस सदन के समक्ष फिर से बजट के भाषण में रख दीं। यह इस सदन का सौभाग्य और सम्भवतः इतिहास का दुर्भाग्य है।

इस वर्ष माननीय वित्त मन्त्री ने जो आंकड़े रखे उनमें मोटे-तौर पर उन्होंने सिंचाई के सम्बन्ध में आंकड़े रख कर यह बताने का प्रयास किया कि रिहन्द, अर्जुन, अहरौरा, और चन्द्रप्रभा बांध इस वर्ष में पूरे यदि नहीं होंगे तो उन पर कार्य करने का प्रयास किया जायगा और बहुत कुछ कार्य उनपर होगा। उन्होंने बताया कि ४८० मील लम्बी नहरें बनाने की कोशिश की जायेगी और यह कि ८३० नलकूप इस वर्ष में इस प्रदेश को दिये जायेंगे।

जहां तक विद्युत का प्रश्न है उन्होंने कहा कि इस वर्ष ४० हजार नये किलोवाट्स दिये जायेंगे। उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में उन्होंने बतलाया कि जुलाई में मिर्जापुर की सीमेंट फैक्टरी ७,००० टन रोज सीमेंट बनाने लगेगी और उस पर सदन ११६ लाख रुपया इस वर्ष भी खर्च किया जायगा। शिक्षा योजना के सम्बन्ध में सदन के समक्ष रखा गया कि ३,००० नये जूनियर हाई स्कूलस में कृषि की शिक्षा होगी और उसके लिये ३,००० अध्यापक रखे जायेंगे, जिनमें २,००० इंटरमिडिएट और १,००० ग्रैजुएट्स होंगे। पी० डब्ल्यू० डी० के सम्बन्ध में जो सड़कों की बढ़ोत्तरी होने को है जैसे ७० मील लम्बी सीमेंट की सड़क ३०० मील से अधिक पक्की और कच्ची सड़क की बढ़ोत्तरी का भी जिक्र किया और सहकारिता के सम्बन्ध में भी इस सदन के समक्ष जिक्र किया और कहा कि करीब २० हजार नई सोसाईटीज और २०० नये बीज गोदाम इस वर्ष इस प्रदेश में बनेगें।

मैंने, श्रीमन्, इन आंकड़ों की ओर सदन का ध्यान दोबारा दिलाने का इसलिये प्रयास किया कि वह इसकी छाया में इस प्रगति की कहानी को समझ सकें। उन्होंने जब सचमुच में क्रय शक्ति का जिक्र किया कि ऐसा मालूम होता है कि शहर में बाकई क्रय शक्ति कम हो

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

गई है और कोई भी ईमानदार आदमी इससे इन्कार नहीं कर सकेगा कि मध्य वर्ग के लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। जहां तक भूख और गरीबी का ताल्लुक है कौन नहीं जानता कि इस प्रदेश की प्रत्येक मील ३०० से ऊपर आदमियों का दबाव है और नहीं जानता कि इस प्रदेश में २२०० व्यक्ति रोज मरते हैं ३५०० पैदा होकर १३०० व्यक्तियों का दबाव प्रतिदिन होता है। कौन नहीं जानता कि इस प्रदेश में जन संख्या के ७२ प्रतिशत आदमी कृषि व्यवसाय करते हैं। आखिर इस सबके लिये कौन सा अमोघ शस्त्र माननीय राजनारायण जी ने रखा मैं नहीं जान पाया। यदि यह मान लिया जाय कि वाकई क्रय शक्ति में कमी आई और भूख और गरीबी को जल्दी समाप्त करने का प्रयास या आश्वासन जो हमने दिया था और वह शीघ्रता से पूरा नहीं हो रहा है, आखिर फिर उपाय क्या है? मेरे मित्र की बहुत बड़ी विवेचना और आलोचना है या कोई ठोस कार्य है। जो नया बजट है उसमें कोई खास चीज है या नहीं? मैं उसको व्यक्तियों के ऊपर ही सोचने के लिए छोड़ देता हूं और अपने मित्र को समझाने के लिये कि वह यह समझें कि किस तरह से इस देश की विपुल गरीबी को दूर किया जा सकता है।

जैसा मैंने कहा श्रीमन्, इस प्रदेश में ७२ प्रतिशत लोग कृषि व्यवसाय को करते हैं। उनके लिये दो चीजें हैं। जल और विद्युत। जल के लिये तो जैसा कि मैंने कहा ४५-४६ में कहां ४९ लाख और अब १५४ लाख का बजट है यानी आबपाशी द्वारा प्रयास किया जाय कि इस प्रधान कृषि प्रदेश में लोगों को जल मिल सके और उधर यह प्रयास किया जाय कि छोटे मोटे बिजली के कारखानों को ३०० इस वर्ष जो नये पावर हाउस बने उनके द्वारा विद्युत शक्ति मिल सके, जिससे केवल कृषि ही नहीं बल्कि छोटे-मोटे कल-कारखानों को भी और जो कि कुटीर-उद्योग है उसको भी ज्यादा बिजली मिल सके और उनके कार्य में भी प्रगति हो। एक तरफ यह विपुल प्रयास है श्रीमन्, और दूसरी तरफ मेरे मित्र का आवेदन है, शिकायत है इस सदन के समक्ष। मैं विश्लेषण उन शिकायतों का श्रीमन् के समक्ष रखता हूं और आपके द्वारा इस सदन के समक्ष। मेरे मित्र कहते हैं कि जमींदारी अबालीशन कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि आप यहां लगान कम करिये। मेरे मित्र का कहना है कि आबपाशी आपने ड्योढ़ी कर रखी है, कहीं कहीं दुगुनी है, इसे घटाइये। मैं केवल अपने मित्र से यह प्रार्थना करूंगा श्रीमन् कि कृपा कर सन् १९५४ को और सन् १९४२ को एक स्थान पर न रखिये। क्या मेरे मित्र नहीं जानते कि आज सन् १९४२ और ४१ के रुपये का मूल्य ४ आने है? क्या उनको मालूम नहीं है कि कृषक रुपया लेता है इस ४ आने के मूल्य से और वह दो रुपये की जगह आज लेता है बीस रुपया या ढाई रुपये की जगह १८ रुपया या और कुछ अधिक और वह देता है एक रुपये के स्थान पर चार आने। श्रीमन्, यानी जो लगान था पहले उस लगान का आज वह चौथाई देता है। और इसी प्रकार से मेरे मित्र मुझे क्षमा करें, सम्भव है कि मेरे हिसाब में कुछ गल्ती हो, आबपाशी वह देता है एक रुपये के स्थान पर छः आने या सात आने और मेरे मित्र को शिकायत है कि किसी प्रकार से यह लगान और आबपाशी और कम हो।

उधर मेरे मित्र बार-बार गांधी जी का जिक्र करते हैं, जो कि इस राष्ट्र के पूज्य पिता थे, जिनकी प्रेरणा से आज का यह बजट ओतप्रोत है, जिनकी प्रेरणा इस देश को ही नहीं संसार को भी प्रदान हुई और जोकि युगों युगों तक प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। उनका जिक्र हमारे मित्र बार-बार करते हैं और कहते हैं कि मिनिस्टरों के लिए उन्होंने कहा था कि उनकी पांच सौ रुपया तनख्वाह होनी चाहिये। कब कहा था? जरा मेरे मित्र बताएं। आप १९४७ का जिक्र करते हैं। मैं उससे पहले का जिक्र करता हूं। सन् १९४७ में क्या कहा वह भी मुझे स्मरण है और उसके पूर्व उन्होंने क्या कहा सन् १९३७ में जबकि सबसे पहले कांग्रेस की मिनिस्टरी बनी थी वह भी जानता हूं। उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर की तनख्वाह ५०० रुपया हो। वह ५०० रुपया जोकि सन् १९३७ के थे आज उसका मूल्य २,००० रुपया है और मिनिस्टर इनकम टैक्स फ्री केवल १,२०० रुपया पाता है। तो मेरे मित्र का कौन सा विरोधाभास

है, कौनसी चीज है जो वह सदनके सामने रखते हैं ? इसको वह स्वयं ही जानें । इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा यह जो टैक्सों के सम्बन्ध में और माननीय मलखान सिंह जी ने अभी अभी पंचायत टैक्स का, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टैक्स का जिक्र किया । कल बहुत से टैक्सों का जिक्र किया और मैं स्वीकार करता हूं श्रीमन्, कि टैक्सों की बढ़ोत्तरी हो यह किसी भी राष्ट्र के लिये सुखदायी नहीं है । टैक्स लगाये जायं, यह किसी भी व्यक्ति के लिये सुखदायी नहीं है । इनकम टैक्स या सेल टैक्स किसी भी टैक्स की बढ़ती मुझे या माननीय राजनारायण किसी को अच्छी नहीं लगती । लेकिन क्या टैक्स के बिना कोई राज्य चलाया जा सकेगा और आखिर कौन सा मार्ग है ? एक तरफ तो आपके सामने भुखमरी का वीभत्स दृश्य है और इधर उसके लिए आपके पास कोई उपाय है, कोई प्रयास है ? आखिर क्या है, आप चाहते क्या हैं ? आप चाहते हैं कि जो टैक्स सन् १९३७ में था वही टैक्स बना रहे और विकास का कार्य होता रहे । तो आखिर आपका मंशा क्या है ? आप क्या इस सदन के सामने रखना चाहते हैं ? यह कहा गया कि टैक्स न लगाइये और सारे कार्य करिये । इसके लिए कोई इलाज आपके पास हो कि टैक्स भी न लगे और सब काम भी हो जायं तो मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि वह अपना स्थान छोड़ दें और माननीय राजनारायण को वह स्थान दे दें । लेकिन क्या यह मेरे मित्र कर सकेंगे ? वह भूलते हैं । बार-बार मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता । वह भूलते हैं माननीय कृपलानी जी की उस वाणी को जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अगर राज्य आप हमें देते हैं तो हम उसमें इससे ६ गुना टैक्स लगायेंगे और आज मेरे मित्र यह कहने जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने टैक्स ड्योढ़ा, दुना कर दिया । इससे बढ़कर कौन सी बड़ी विडम्बना होगी , कौन सा इससे बड़ा राजनैतिक अनाचार होगा और आखिर वह कौन सी राजनीति है जिसके पीछे वह पड़े हैं और जिसका जिक्र बार बार वह करते हैं ? कहीं सोशलिस्ट पार्टी, कहीं के० एम० पी० पी०, कहीं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कहीं वह यूनाइटेड फ्रंट ट्रावनकोरकोचीन में उन लोगों के साथ जिनके ऊपर कि यहां हमारे माननीय मित्र बहुत बार गाली गलौज कर चुके हैं, उन्हीं कम्यूनिस्टों के साथ में जिनके नाम पर कई बार आपके माथे पर रेखायें खिच आई हैं, उन्हीं कम्यूनिस्टों के साथ आपका गठबन्धन । मैं पूंछता हूं कि यह कौन सा गठबन्धन है ? .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह किसी पार्टी के सम्बन्ध में विचार करने का अवसर नहीं है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मैं उसी नीति के सम्बन्ध में कह रहा था । आखिर वह कौन सी नीति है जिसके द्वारा कि आप हमारी आलोचना करते हैं ? कौन सी नीतियां हैं, कितनी नीतियां आपने बना ली हैं जिनके द्वारा आप आलोचना करते हैं ? मैं केवल इतना कहकर श्रीमन्, चाहूंगा कि बहुत सी बातों के सम्बन्ध में मेरे मित्र विचार करें और विचार करके उनके सम्बन्ध में आगे बढ़ने का प्रयास करें । माननीय वित्त मन्त्री जी ने मेरे मित्रों से यह अपील की कि वह उनके साथ सहयोग दें । मैं कैसे कहूं ? इस हृदय में यह आया कि उनकी अपील के लिये उन्हें धन्यवाद दूं, बधाई दूं और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह अपील की । लेकिन कौन से लोगों से उन्होंने अपील की यह वह स्वयं विचार कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि यह अपील व्यर्थ है । मैं जानता हूं कि इस देश का राजनीतिक वातावरण तो, मुझे क्षमा किया जाय यदि मैं उसे इस सदन के समक्ष रख दूं तो बुरा लगेगा लेकिन है सत्य । एक फिल्म थी मुझे ठीक स्मरण नहीं, लेकिन शायद उसका नाम मिस्टर सम्पत था । उसमें एक दृश्य है, एक रिक्शा कुली बाजार में गिर गया एक मित्र आये और कहा कि बहुत बुरा हुआ, म असेम्बली में सवाल करूंगा, तो वह कौन असेम्बली में सवाल करता है और कौन उसकी मदद करता है । वह असेम्बली में सवाल करने वाले जो साहब हैं वह आज इस राजनीति पर अवलम्बित हैं । मैं कुछ ज्यादा इसके विषय में राजनीतिक विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपील तो उन लोगों से की है जो रिक्शे वाले की मृत्यु पर सवाल पूंछना चाहते हैं, उसकी सहायता नहीं करना चाहते । अपील तो

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

उन्होंने की है उनसे, जिन्होंने कि वाकई में इस देश में यह चाहा है कि भुखमरी हो ? जिन्होंने कि सचमुच में इस देश के अन्दर यह चाहा है कि यदि भुखमरी हो तो कांग्रेस सरकार के माथे पर एक काला टीका लगे और जिन्होंने सचमुच कोई सुझाव नहीं दिया है, न कल ही कोई सुझाव इस सदन में रखा है और न आज ही ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---आप रख दीजिए ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरी ओर से तो रख दिया गया और उस पर आप विचार करेंगे लेकिन फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री की यह अपील बिलकुल मिस्प्लेस्ड है। माननीय बालेन्दुशाह जी की बातों को मैंने पढ़ा और मुझे दुख नहीं हुआ । कुछ अच्छा भी लगा । मैंने समझा कि कोई सज्जन यह चाहते हैं कि सचमुच इस प्रान्त की बढ़ी हुई कर्जदारी को ठीक ढंग पर लाया जाय । मैं उनको धन्यवाद देता हूं । परन्तु वे माननीय वित्त मन्त्री जी के अंग्रेजी भाषण के पृष्ठ संख्या ७ को देखें ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि उनका एक ही भाषण है जो हिन्दी में हुआ है ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे पास दुर्भाग्य से अंग्रेजी की प्रति है ।

श्री अध्यक्ष---अगर आप सिर्फ अंग्रेजी जानते होते, हिन्दी न जानते होते तो मैं मान लेता ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे पास दुर्भाग्य से अंग्रेजी की प्रति है ।

श्री अध्यक्ष---तो आप हिन्दी की प्रति लेकर उसमें से पढ़िये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैं समझता हूं कि मेरा समय भी हो आया और मुझे इस सम्बन्ध में और जो बातें थोड़ी सी कहनी थीं शायद मैं न कह पाऊं । केवल मैं इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री ने जो इस सदन से अपील की है, मेरी दृष्टि में गरीबी भूख और कमी को समाप्त करके इस देश में विकास की मंजिल की एक सीढ़ी पकड़ने की आवश्यकता है । मेरे मित्र चाहे जिस दृष्टि से लें । दुर्भाग्य से मेरे सामने हिन्दू महासभा के अनन्त प्रतीक जाज्वल्यमान प्रतीक श्री ज्वाला प्रसाद जी नहीं हैं । मैं नहीं जानता कि मैं उनसे क्या कहा कहता जब मैंने यह देखा कि उन्होंने यह कहा कि प्रशासकीय व्यय के सामने इस प्रदेश में शिक्षा और सहकारिता पर कम खर्च हुआ है । मुझे सचमुच बड़ा आश्चर्य हुआ मैंने उन आंकड़ों को देखने का प्रयास किया मैंने शिक्षा और सहकारिता के व्यय के सम्बन्ध में अभी कहा, इस प्रदेश में शिक्षा में एक नया प्रयोग आरम्भ हुआ है और सम्भव है कि सारा भारतवर्ष उस प्रयोग को अपनाये । जहां तक सहकारिता का सम्बन्ध है सहकारिता के सम्बन्ध में यह भी शायद मेरे मित्रों को स्मरण हो इसके बजट में तीन लाख से अधिक रुपया है । इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, इस बजट को मेरे माननीय मित्रों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार से देखा है । किसी ने दिवालिये के रूप में इस प्रदेश को देखा है और किसी ने बजट को प्रस्तुत बजट को, कल्याणकारी समझा है । लेकिन मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से इसको कल्याणकारी हो रूप में देखता हूं । मेरे सामने इस प्रदेश का जीता जागता कल्याणकारी नमूना दिखायी देता है इस प्रान्त का पूर्वी भाग । पश्चिमी भाग के भाइयों के सहयोग से और इस सरकार की कृपा से आज इस प्रदेश के पूर्वी हिस्से की आर्थिक स्थिति सम्हाली जा रही है । जिस जगह पर भुखमरी, अकाल, बाढ़ से लोग पीड़ित होकर

भरा करते थे, आज वहां पर हम नलकूपों, नहरों और बांधों का एक व्यापक जाल सा बिछा हुआ देखते हैं। इस प्रयास का नतीजा यह हो सकता है और अनुमान भी किया जा सकता है कि प्रान्त के पूर्वी भाग भुखमरी और बेकारी दूर होगी उनके पेट में अन्न पहुंचेगा, बदन पर वस्त्र पहुंचेगें। इसी के सहारे और बल पर शिक्षा की तरफ भी अपनी प्रगति को बढ़ायेगें। मैंने आज से कई वर्ष पहले यहां के बजट की आमदनी और खर्चे का जो आंकड़ा रहा है उस भी देखा है। सन् १९३७ में जब यहां कांग्रेस सरकार आयी तो सम्भवतः इस प्रान्त में ११ करोड़ रुपये का बजट था। और अब ८ गुना वह रकम-बढ़ गई है। गर्ज कि ८१ करोड़ रुपये को हम इस प्रान्त के विकास में खर्च करने जा रहे हैं। तब भी यह कहा जाय कि यह कल्याणकारी बजट नहीं है, यह वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो मैं समझूंगा कि इस तरीके से कोई सच्चाई का स्पष्टीकरण नहीं हो पायेगा। विरोधी-जनों का उचित सा विचार मालूम नहीं होता। सरकार ने पूर्वी जिलों में जिसका एक नमूना बस्ती जिला है वहां पर एक लाख नहीं, दो लाख नहीं, ३४, ३४ लाख रुपये को खर्च करके बानगंगा की नहर के प्रसार में लगा दिया है और बांसी स्थित राप्ती नदी के पुल पर डेढ़लाख रुपया खर्च करने को तैयार हैं ऐसे ही ४ करोड़ रुपये वह रेहन्द डैम पर भी खर्च करने जा रही है। इतना ही नहीं उसके सामने अहरौरा और अर्जुन डैम जैसी विकासवादी योजनायें हैं जिनसे हम अपने देश की गुर्बत को हटा सकते हैं। तब भी यह कहा जाय कि इससे हमारे प्रदेश का कल्याण नहीं होगा मैं समझूंगा कि ऐसा कह कर सच्चाई से दूर हटकर सदस्यों को भ्रम में डालने का प्रयत्न किया जाता है जो सर्वथा अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में व्यंग के साथ यह भी कहा गया है कि यह खर्चा जो किया जाता है वह कौमियत के नाम पर किया जाता है। ठीक तो है। आखिरकार पुलिस तो कोई कौम से अलग है नहीं। जब हम अपने घर पर आनन्द से सोते हैं और अपने गांव के घरबार और एक एक खेत की रखवाली भी न करते हों उस स्थान जब पुलिस ही का सहारा हो तो पुलिस पर खर्च करना क्यों खलता है। हमारे घर के नौनिहाल हो तो पुलिस में काम करते हैं। अगर हम उन पर कुछ रुपया खर्च करते ह तो वह कौमियत पर खर्च नहीं हुआ तो किस पर हुआ? राष्ट्र से वे कोई अलग तो हैं नहीं। अगर उन पर कुछ थोड़ी सी रकम ज्यादा खर्च कर दी जाय तो यह कहा जाय की बेकार में वह धन अथवा रुपया खर्च होता है। यह कोई उचित दलील नहीं है। जब हम यह अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे प्रान्त के अगल बगल सीमा पर अराजकता फैली हुई है, जैसे नैपाल में एग्रेरियन टबुल है, जहां पर जमीदारों की फसल को किसान और कथित नेता दिन दहाड़े लुटवा लेते हैं उसी सीमा से लगे हुये हमारे प्रदेश के कुछ इलाके हैं बस्ती, गोरखपुर, गोंडा, बहराइच जिलों के निकटवर्ती जितने स्थान हैं वहां पर खुल्लम खुल्ला चोरी और डकैती होती है। तो यह सब देख कर यह भय होता है कि कहीं वह अराजकता हमारे प्रदेश में भी खिसक न आये और कहीं इस प्रकार विषाक्तमय वातावरण यहां भी पैदा न हो जाय। ऐसी परिस्थिति में यदि हमारी सरकार चन्द लाख और पुलिस पर खर्च कर दे तो उस पर कौमियत की दुहाई दी जाय यह कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। विरोधी दल के नेता यह चाहते हैं कि हमारे प्रान्त में अराजकता फैले और पुलिस द्वारा जो रोकथाम होती है उसको न किया जाय, तब उनकी समझ में कल्याणकारी राज्य होगा। मैं समझता हू कि पुलिस पर जो व्यय हो रहा है, उचित खर्च है। वह होना चाहिये ताकि यहां का नागरिक जीवन शान्तिमय हो और इस प्रदेश के निवासी अमनो अमान से जिन्दगी बसर करते हुये सुखी रहें।

इसी के साथ-साथ उनका यह भी कहना है कि यहां पर जो पंचायतें हैं उन पर भी ठीक खर्च नहीं किया जा रहा है। वह तो डेमोक्रेसी के हिमायती हैं। आखिरकार वह क्या चाहते हैं। क्या ऊपर से ही राज्य किया जाय अर्थात् एकतंत्र राज्य स्थापित किया जाय। पंचायतों

[श्री रामकुमार शास्त्री]

को इसीलिये स्थापित किया गया है कि नीचे के वर्ग को लेकर सुव्यस्थित रूप से हर एक को आराम पहुंचे और जहां न्याय की जरूरत हो वहां न्याय कराया जाय और जो न्याय के रोकने वाले हों उन्हें समुचित दंड दिया जाय। इसी वास्ते आवश्यकतानुसार रुपया इस मद में खर्च करने के लिये रखा गया है। इससे ग्रामीण जनता को सर्वतोमुखी लाभ होगा। इसके साथ साथ कल्याणकारी राज्य का हमारे सामने यह भी जीता जागता नमूना है कि बेकारी दूर करने के लिये सरकार ने छोटे छोटे उद्योग-धन्धों के पनपने वाले कार्यों में ३ करोड़ रुपया योजना की शक्ल देकर रखा है जिसे वह खर्च करने जा रही है। ये रोजगार बेकार लोगों को दिया जावेगा जिससे उनकी तरह तरह की कठिनाइयां दूर होगीं।

श्री अध्यक्ष---क्या आप अपना पूरा समय लेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री---जी हां।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता मे सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामकुमार शास्त्री---उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान बजट के सिलसिले में यह जिक्र कर रहा था कि अपने मुल्क की बेकारी दूर करने के लिये इस बजट में कौन से साधन उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ कुटीर उद्योग धंधों के फलने और फूलने के लिये जनप्रिय सरकार ने स्टेट इंडस्ट्रियल ऐंड फाइनेंस कार्पोरेशन कायम करने की व्यवस्था की है और इसके साथ ही साथ हैंडलूम की इंडस्ट्री को भी पनपने का भी जिक्र बजट में किया गया है। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ यह निवेदन करना पड़ता है कि जहां पर नलकूपों और नहरों के द्वारा हमारे पूर्वी जिलों में तरक्की करने के लिये सरकार ने सुविधा पहुंचायी है वहां पर उद्योग विभाग के मंत्री महोदय ने बस्ती जिले को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। यह हमारा दुर्भाग्य है। उन्होंने एक पुस्तिका भी छपवा कर सदन के सामने सदस्यों के सामने भिजवाई है और उसका वितरण किया है। यदि उसमें दिये हुए मानचित्र का अवलोकन किया जाय, उसके नक्शे को देखा जाय तो यह मालूम हो जायगा कि प्रान्त में किस प्रकार से उद्योग धंधे चल रहे हैं। अगर उस मानचित्र में बस्ती जिले और सहारनपुर तथा उसके समीपवर्ती मेरठ आदि जिलों को देखा जाय दो उसकी तुलना में बस्ती जिले के मानचित्र में केवल एक चिह्न ही किसी साधारण उद्योग धंधे का दिखाई देता है। बस्ती जिले में पाटरी की इंडस्ट्री की व्यवस्था चिल्हिया स्थान में की गई थी लेकिन दुर्भाग्य से वह भी हमारे सामने नहीं रही। वहां के लोग कुछ इस ओर प्रयास करना चाहते हैं। किन्तु सरकार की मदद के बग़ैर सफलता मिलना कठिन ही नहीं, असम्भव है। बस्ती में करघों के भी उद्योग धंधे थे। वे उन्नति के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं, पतितावस्था में हैं। मैं इस अवसर पर माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सरकार बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने के लिये उद्योग धंधों का जाल बिछाना चाहती है तो बस्ती जिले को उन्हें नहीं भूलना चाहिये। क्योंकि बस्ती जिले से उनका काफी सम्पर्क है। जिला बस्ती दुर्भाग्य से काफी पिछड़ा हुआ है। अभी थोड़े ही दिन हुये कि उनके हाथ में यह विभाग आया है। उनसे पूर्व इस विभाग की जिम्मेदारी रखने वाले मंत्री महोदय की है कि बस्ती उपेक्षित रहा। हमें पूर्ण आशा है कि हमारे जिले बस्ती को वर्तमान मंत्री जी से पूरा पूरा लाभ पहुंचेगा।

अब थोड़ी सी चर्चा प्रेस के बारे में करना चाहता हूं। इस प्रान्त के प्रेस ने जितने कार्य हमारे हो रहे हैं, जितनी योजनाएं हैं उनमें मदद करने में कोई कोर कसर बाकी

नहीं रखा है । अभी हाल ही जहां पर नहरों की योजना चालू की थी और जहां बांध आदि बांधे जा रहे हैं, वहां पर दल बल के साथ हमारे प्रेस के भाई गये और उसके काफी प्रचार करने की कोशिश की। जनतंत्रात्मक राज्य में प्रेस के द्वारा लोगों में प्रचार हो सकता है और उनके बाद लोग यहां पर मांग करते हैं, बाहर भी मांग करते हैं कि इस जिले में यह हो और उस जिले में यह हो। अभी थोड़े दिन हुये यहां पर प्रेस की प्रवृत्ति के बारे में कुछ चर्चा हुई थी। हमारा दुर्भाग्य है कि जिनसे हमारी योजनाओं में पूरी मदद मिल सकती है उनके कुछ लेखों पर ऐसी आलोचना सदन में हुई कि सरकार ने उनकी स्वतंत्रता का हनन किया है। जो हो, बात कुछ और ही ढंग की थी। इसके समझने बूझने में गलतफहमी हुई जिसके लिये हमें दुःख है। हम आशा करते हैं कि इस तरह की बातों की कोई पुनरावृत्ति अब इस सदन में न हो पायेगी और प्रेस हमारे सहायक होंगे। प्रजातंत्रात्मक राज्य में फ्रीडम आफ स्पीच होनी चाहिये। यह बात सही है उन्होंने अच्छे से अच्छे आलोचनात्मक अग्रलेख निकाले हैं और उसमें गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी और आलोचना भी होती है परन्तु किसी प्रकार की रुकावट सरकार की तरफ से नहीं हुई। उसके बाद भी यह कहना उचित नहीं होगा कि हम प्रेस के अधिकारों को रोकते हैं, अथवा स्वतंत्रता में बाधक हैं।

मैं अब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में जिस प्रकार कार्य संचालन उसको पुष्पित और पल्लवित बनाने के लिये हो रहा है उसकी तरफ मुझे इस सदन का ध्यान आकर्षित करना है। सरकार ने करोड़ों रुपया प्रदेश के कोने कोने में जो पिछड़े हुए हैं भेजने के लिये दिया है और उसके लिये मैं सरकार की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जो रुपया यहां से जिलों में वितरण करने के लिये भेजा जाता है उसका जिस ढंग से जिस मितव्ययिता से और जैसी यहां की माली हालत है उसको देखते हुये वितरण होना चाहिये उस तरह से वितरति नहीं होता और इसलिये उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। पंचवर्षीय योजना को तो छोड़ दीजिये हमारे पूर्वी जिले में तरह तरह की दिक्कतें दुर्भिक्ष के कारण हो रही थीं और सरकार ने यहां से प्रत्येक जिले के लिये दो हजार और चार हजार रुपया ग्रेट्चुइटस रिलीफ के लिये, फ्लड एफेक्टेड एरियाज में भेजने के लिये दिया था। उसके लिये हम सरकार के आभारी हैं लेकिन वह समय से वितरण नहीं हुआ। वह कुसमय में और कुस्थान पर वितरित हुआ और काफी दिनों तक वह रकम दबी रही। मैं सरकार की नीयत पर दोषारोपण इसके लिये नहीं करता। परन्तु जिन एजेन्सीज के द्वारा वह इस कार्य को चला रही है उसमें यह दोष अब तक कायम हैं और उसको हमको निकालना है जब तक हम उस दोष को निकालते नहीं हैं तब तक जो कलंक हमारे सिर पर है उससे हमारा पिंड छूटने वाला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जिम्मे इतने काम हैं कि उनका कहना ही नहीं है। जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि जब सब-इंस्पेक्टर पुलिस ही सारा काम करता है तो बीच में इंस्पेक्टर की क्या आवश्यकता है ? यही दलील कमिश्नरों के लिये सदन में दी गई थी कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही सारा काम कर लेता है तो फिर इस द्रविड़ प्राणायाम की क्या आवश्यकता है। तो सरकार ने कमिश्नरों के बहुत से स्थानों को हटा दिया और केवल दो तीन स्थानों पर कमिश्नर रह गये हैं और समय आते आते वह भी न रहेंगे। लेकिन कलेक्टरों के सिर पर इतनी जिम्मेदारी डाली गई है कि वह भार से दबा जा रहा है और जितनी कार्यक्षमता और कार्यकुशलता से कार्य करना चाहिये वह कर नहीं पाते हैं। इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

प्लानिंग के लिये हमने प्लानिंग आफिसर मुकर्रर किया है। मुझे इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी के उस भाषण का स्मरण आता है जो उन्होंने बख्शी के तालाब

[श्री रामकुमार शास्त्री]

में दिया था। विभिन्न विभागों की आलोचना करते हुये उन्होंने कहा था कि ये विभाग जैसी हम आशा करते थे कि काफी काम करेंगे, नहीं करते। सहयोग समिति विभाग के बारे में उन्होंने कहा था कि यह विभाग शिथिल होकर अलग पड़ा हुआ रहता है। यही बात आज भी है कि प्लानिंग विभाग आज विभिन्न विभागों, जैसे, पी० डब्ल्यू० डी०, कोआपरेटिव, कृषि आदि से अलग सा पड़ा हुआ है और विभिन्न विभाग के जो हेड्स हैं वे बजाय इसके कि मिल कर काम करें, इसके काम में रोड़े अटकाते हैं और इस वजह से जो रुपया हम भेजते हैं उनका सदुपयोग पूर्णतया नहीं होता। हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं किन्तु आपस में कोआर्डिनेशन न होने की वजह से, आपसी सहयोग न होने के कारण हमारी योजनायें पुष्पित और पल्लवित नहीं हो पा रही हैं।

पहली बात तो यह कि हमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के भार को हल्का करना चाहिये। वह अधिक भार होने के कारण किसी भी काम को पूरा और ठीक से नहीं देख पाता और फिर अगर कोई अतिथि पहुंच जाते हैं तो काफी वक्त उसका स्वागत में लग जाता है। ऐसे वक्त को उस पंचवर्षीय योजना को पूर्ण करने में लगाना चाहिये, जिससे बेरोजगारी हट सके तथा प्रदेश की स्थिति सम्भले। दुर्भाग्यवश जिलाधीश बहुत कम वक्त जरूरी बातों में दे पाता है। इसलिये उसकी सहायता के वास्ते कोआर्डिनेशन सहयोग के साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना को पूर्ण करने वाली सरकार का यह परमधर्म है कि उस तरफ विशेष दृष्टि डाल कर समुचित उपाय शीघ्रातिशीघ्र ढूंढ़े।

आज सरकार ने विकास की ओर प्रगति की है और काफी प्रगति की है। वे ही लोग जिन्हें पांडु रोग हो गया है वही भले कह सकते हैं कि ११ करोड़ रुपये खर्च करने में और ८० तथा ८१ करोड़ रुपये खर्च करने में कोई अन्तर नहीं है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि सरकार की प्रदेश की सेवायें पिछड़ी हुई हैं।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज इस प्रकार के बजट को लाकर इस सूबे को कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर करने में, बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने में सहायता दी है। इसके लिये वे हर तरह से प्रसंशा के पात्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष---अब समय १५ मिनट का हो गया है।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---मैं तो सुबह के टाइम में भी खड़ी हुई थी। मेरे लिये तो २० मिनट का समय होना चाहिये। उस वक्त मेरा अधिकार नहीं हो सका था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल से हमारे बजट पर वाद-विवाद चल रहा है। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को इस बजट के लिये धन्यवाद देती हूं और इस बजट का स्वागत करती हूं। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने बतलाया कि किसी देश के बजट को सामने रखते हुए एक दर्पण की उपमा दी जाती है, यह सही है कि हमारे प्रदेश के लिये जो आगामी वर्ष के लिए बजट पेश हुआ है वह एक बहुत ही अत्यधिक विकसित और पूर्णरूपेण वेलफेयर स्टेट का आश्वासनमय दर्पण है। मेरी समझ में एक बात यह नहीं आती कि मेरे विरोधी भाइयों द्वारा ऐसी अच्छी चीज पर भी क्यों इतना सिर्फ विरोधमात्र के लिये विरोध किया जाता है। गत वर्ष उन्होंने इस भवन में जो बजट पेश किया गया था उस बजट को रद्दी की टोकरी में फेंक देने के लिये कहा था। यहां तक तो इस साल उनके शब्दों में और भावों में बहुत ही परिवर्तन

पाया जाता है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने कोई रद्दी की चीज न बता कर नमस्कार किया है। हमारी संस्कृति के नाते से भी किसी अच्छी चीज को नमस्कार करके स्वागत किया जाता है। हमारे विरोधी भाई अपने आपको सिर्फ विरोधी पार्टी का समझ कर विरोध करना आरम्भ कर देते हैं, यह वैसी ही कोई अच्छी बात नहीं जंचती। इस तरह से उनके वादविवाद करने से उनका स्तर नीचे होता चला जाता है। यह मैं अपने हृदय से अपनी सरकार की ओर से आश्वासन के रूप में कह सकती हूं कि अगर वह कोई तथ्य की चीज सामने रखेंगे तो उन पर भी उतना ही अमल किया जायगा जितना कि सरकारी बेंच की ओर से कहे गये सुझाव पर किया जाता है।

हमारी पंचवर्षीय योजना जिस पर हमारे भाइयों द्वारा काफी बहस हो चुकी है उस पर भी उन्होंने वादविवाद मात्र का ही दृष्टिकोण रखा है। उस पर मैं समझती हूं कि आज हमसे क्या, आप जनता से जाकर पूछिये कि क्या अच्छे काम किये गये हैं और जनता ने उसका कितना स्वागत किया है और उसमें जनता का हमें सहयोग भी मिला है। मैं फिर उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि यह पंचवर्षीय योजना तो सरकार की तरफ से जनता के सामने प्रस्तुत की गई है और वह वक्त भी जल्दी ही आने वाला है जब कि सरकार के सामने जनता द्वारा उसकी अपनी योजना प्रस्तुत की जायगी। तब उनके पास ऐसे वक्त पर क्या कोई विरोधमात्र के लिये विचार रह जाता है? उस वक्त उनके पास कहने के लिये क्या रह जायगा? कोई अच्छी चीज चाहे इस पार्टी की है, चाहे उस पार्टी की है और चाहे किसी की भी है तो, हमें उसके लिये यह नहीं कहना चाहिये कि यह चीज अच्छी नहीं है और अगर हम इसको करते तो अच्छी हो जाती, वह करते हैं तो बुरी है। यह कोई अच्छी बात जाहिर नहीं होती है और नहीं ऐसा करने से आप जिनका रात दिन जिक्र किया करते हैं कि जनता के कल्याण का काम करने आये हैं उनके लिये ही आप सदन के इतने समय को व्यर्थ दुरुपयोग करके कोई अच्छे सुझाव दे पाते हैं। और अधिक न कहते हुये मैं उनसे भविष्य के लिये प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी चीज सदन के सामने पेश करें जो कि कोई काट न सके, अकाट्य हो, मानने काबिल हो और तथ्य की हो।

हमारे सामने जो बजट आया है उसकी पंच वर्षीय योजना जान है। बजट को देखने से एक स्पष्ट झलक आंखों के सामने आ जाती है और हृदय पंचवर्षीय योजना से प्रभावित होकर यह विश्वास कर लेता है कि जो आश्वासन इसमें दिया गया है वह शीघ्र ही चरितार्थ करके हम जनता के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे।

इतना सब कुछ होते हुये मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं। यह सब कुछ जितना भी इसमें रखा गया है वह सब बहुत ही सुन्दर है। लेकिन मैं महिलाओं के कार्य के लिये इसमें बहुत कम धन पाती हूं। गत वर्ष हमारे माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में महिलाओं के सहायता कार्य के लिये १ लाख रुपया रखा गया था। इस साल वह एक लाख रुपया मैं कटौती में पाती हूं। उस १ लाख रुपये से जो कार्य महिला संघ ने किये, यदि मैं उनको बयान करूं तो काफी समय सदन का ले लूंगी। मैं इतना ही कह देना उपयुक्त समझती हूं कि उस १ लाख रुपये से हमने कई कार्य किये। आज इस भवन में कुम्भ मेले का भी जिक्र आया। हमारे भाइयों ने सरकार पर दोषारोपण किया। हमारे महिला संघ ने वालंटियर के रूप में वहां पर काफी कार्य किये। क्या मैं विरोधी पार्टी के माननीय सदस्यों से पूछ सकती हूं कि क्या विरोधी पार्टी के वालंटियर भी वहां कार्य करने गये थे और जो पीड़ित लोग थे उनकी सेवायें की थीं? खैर, यह तो उनके सोचने की बात है। यह जो अभी हाल में लखनऊ में प्रदर्शनी हुई थी उसमें महिला सहायक संघ ने इन्हीं कार्यों के लिये करीब एक डेढ़ लाख रुपये

[श्रीमती चन्द्रवती]

का धन संचय किया है। स्त्रियां तो सदैव अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागृत रहती हैं और वे पुरुषों को भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत करती रहती हैं ताकि वे कहीं पर पथ विचलित न हो जायं।

यह सही है कि विधवा आश्रम के लिये इस बजट में २० हजार रुपया रखा गया है और मैं यह मानती हूं कि यह एक बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। लेकिन यह बजट में जो अनुदान रखा गया है वह बहुत ही कम है। इस बात को मैं मानती हूं कि आगामी वर्ष के लिये ५० हजार रुपये कर दिये गये हैं। लेकिन यह भी बहुत ही न्यून है।

अब इसके बाद पंचवर्षीय योजना के बारे में अधिक न कह कर कुछ थोड़े से जो कि हम लोगों से सम्बन्धित हैं, सुझाव देना चाहती हूं। सबसे पहले हमारे सामने उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का ही प्रश्न आता है। यदि भारतीय जन संख्या को देखें तो उसमें भी हम लोग आधे से ज्यादा संख्या में पायी जाती हैं। हमारी शिक्षा के ऊपर ही इस बजट में ले लीजिये कि कितना रुपया व्यय के लिये रखा गया है। मैं समझती हूं कि अगर इससे और अधिक रुपया रखा जाता तो वह सदुपयोग में कहा जा सकता है। अब एक प्रश्न आता है जिले वाइज लड़कियों के स्कूल खोले जाने का, इंटर और बी० ए० क्लासेज की व्यवस्था करने का। उसमें भी मैं पाती हूं कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ही अधिकता दी जाती है। मैं अपने अनुभव द्वारा इस सदन में सच कह सकती हूं कि मेरे दो साल लगातार, सतत प्रयत्न करने के बाद भी अपने जिले की लड़कियों के लिये इंटरमिडियेट क्लासेज में स्थापित न करा सकी। यह मेरा दुर्भाग्य कहिये या यह कहिये कि यह सच हो जाती है कि लड़कियों के प्रश्न को ऐसा सोच लिया जाता है कि वह पीछे हो जायगा। जब कि बिजनौर में लड़कों के लिये इंटरमिजियेट क्लासेज खोले गये हैं तो मैं नहीं सोच सकती कि क्या वजह है कि लड़कियों के लिये उस जिले में क्यों नहीं खोले गये। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा जिला होते हुये भी लड़कियों के इंटरमिजियेट की व्यवस्था भी न हो सकी। इससे अधिक उदाहरणार्थ मैं और क्या कह सकती हूं। इसमें मैं अपना एक और सुझाव माननीय शिक्षा मंत्री के सामने रखना चाहती हूं कि इस साल महिला अध्यापिकाओं के लिये निवास स्थान की व्यवस्था हटा दी है तो उनके लिये यह व्यवस्था होनी ही चाहिये। अगर एक अध्यापिका स्थानापन्न हो कर दूसरी जगह जाती है तो यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसको एक नयी जगह पर रहने के लिये प्रबन्ध करने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिये जहां पर बोर्डिंग हाउसेज होते हैं वहां पर उनके रहने के लिये स्थान जरूर होना चाहिये।

अब मैं जन-स्वास्थ्य के प्रश्न को लेती हूं। इसमें आप देख लीजिये कि इस बजट में स्त्रियों के प्रति कितना रुपया रखा गया है। मैं स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री को सुझाव के रूप में यह पेश करती हूं कि यह रुपया अगर और अधिक संख्या में रखा जाता तो अच्छा होता। अब एक प्रश्न मैं आपके सामने रखती हूं कि जिलों में, शहरों में, नगरों में तो अस्पताल पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं, लेकिन आज अगर देहात में जाकर आप देखिये कि कितने अस्पताल कितने गांवों के बीच में आपको मिलेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारी बहुत सी बहनों की जानें केवल जच्चा बच्चा के एक प्रश्न में ही चली जाती हैं और उनकी वह कीमती जानें जो कि पुरुषों के मुकाबिले में उतनी ही मूल्यवान हो सकती हैं, कुत्तों की नाईं चली जाती हैं। मैं अपना सुझाव स्वास्थ्य मंत्री के सामने यह रखना चाहती हूं कि वह बिलेजेज में कुछ ऐसे सेंटर्स खोलें कि जो वहां की दाइयां होती हैं उनको वहां ट्रेनिंग दी जाय और ट्रेनिंग पाकर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वह जच्चा-बच्चा का कार्य करें। इसके लिये

आपको थोड़ा सा सुझाव और भी देना उचित समझती हूं। आज अगर हमारी पंचवर्षीय योजना में आप जनशक्ति का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको स्त्रियों के लिये भी यह सोचना पड़ेगा कि उनकी शक्ति का कैसे उपयोग करें। इसी में मैं यह सुझाव रखना चाहती हूं कि जच्चा-बच्चा से संबंधित कुछ फिल्में अगर पंचायत समितियों के प्रबन्ध के द्वारा देहातों में दिखलायी जायं तो उनसे बहुत लाभ हो सकता है। जो कार्य हम प्रौढ़ शिक्षा की योजना से पूरा नहीं कर सके वह कार्य हम इन फिल्मों द्वारा कर सकते हैं। अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान दूसरी तरफ दिलाना चाहती हूं कि अब यह बड़ी खुशी की बात है कि रिहन्द डैम बनने जा रहा है और हमारे प्रदेश में काफी मात्रा में बिजली पैदा होने जा रही है। मैं यहां पर माननीय वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहती हूं कि शहरों में तो काफी बिजली दी जा चुकी है इसलिये अब देहातों में पहुंचाना शुरू करें। मैं समझती हूं कि यह हमारी पंचवर्षीय योजना में भी सहायक होगी और यह प्रगतिशील होगी। हमारे भाई जो देहात में इसे देख तक नहीं पाते वह भी हमारे सहायक होंगे। इतना सब कुछ होते हुये भी मैं अभी बहुत कुछ कहना चाहती थी किन्तु समय न होने के कारण मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं और वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहती हूं कि वह मनुष्यों को हवा में उड़ाना सिखाना चाहते हैं तो वहां पर स्त्रियों को भी वह न भूलें। उड़ाने वाली शिक्षा से स्त्रियां वंचित न रखी जायं। इसमें महिलाओं के लिये प्रतियोगितायें रखी जायं और उनके लिये भी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाय। आखिर में मैं उनको पुनः हार्दिक धन्यवाद देती हूं।

वक्ताओं के लिए निर्धारित समय में कमी करने का प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोलने वालों के लिये अब १० मिनट का समय मुकर्रर कर दिया जाय।

अनेक सदस्य—हम इसका विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि हाउस की यह राय है कि समय में कोई कमी न की जाय।

१९५४–५५ के आय–व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

†**श्री सुरेश प्रकाश सिंह** (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, बहुत दिन हुये अंग्रेजों के जमाने में १९२४ में उस समय के फाइनेन्स सेक्रेटरी ने बजट पर भाषण देते हुये कहा था कि—

"Budget is an aweful thing to prepare, it is more aweful to explain and most aweful of all to understand."

[आय–व्ययक का तैयार करना एक भीषण चीज है, उसकी व्याख्या करना और भी भीषण है और उसका समझना तो सबसे भीषण है।]

श्रीमन्, मेरे जैसे एक लेमैन के लिये यह भयंकर प्रतीत होता है। इसलिये मुझे श्रीमान् क्षमा करेंगे और भवन के माननीय सदस्य भी क्षमा करेंगे यदि मैं उन आंकड़ों की भूलभुलैया में न पड़ूं क्योंकि एक मर्तबा फंसकर मैं निकल नहीं सकूंगा और खास कर जब कि हमारे वित्त मंत्री जैसे कुशल और योग्य आंकड़े बाज यहां मौजूद हैं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

श्रीमन् , यह एक संसदीय परम्परा है कि जिस समय बजट प्रस्तुत किया जाता है उस समय राज्य के वित्त मंत्री को बधाइयां दी जाती हैं। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि परम्परा के नाते ही नहीं वरन् हार्दिक बधाई देता हूं।

बजट की बधाई पर मैं पीछे आऊंगा। कम से कम जिस कुशलता, योग्यता और जिस श्रम से उन्होंने इस बजट को बनाया है और उनके डिपार्टमेंट ने बना कर प्रस्तुत किया है, उसको देखते हुये वह बधाई के अधिकारी अवश्य हैं। मैं इतना ही नहीं बजट पर भी उनको बधाई देता हूं। श्रीमन्, जब हम इस बजट को एक ब्राड आउटलुक से देखते हैं तो यह देखते हैं कि बहुत सी कठिनाइयां और ड्राबैक्स के होते हुये भी, हमारे सामने, प्रदेश के सामने और हमारी सरकार के सामने, हम किसी प्रदेश से पीछे नहीं हैं।

श्रीमन्, हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि सदियों से एक दासता की जंजीर में जकड़ा भारतवर्ष अभी सात ही साल हुये स्वतंत्र हुआ है। उस स्वतंत्रता की जो कीमत हमें पाकिस्तान के रूप में चुकानी पड़ी वह हर एक माननीय सदस्य को विदित है और पाकिस्तान के फलस्वरूप और इस नयी सरकार, इस अनभिज्ञ सरकार के ऊपर जो शरणार्थियों की समस्या आ गई है वह भी हम में से हर एक सदस्य यहां जानता है। इतना ही नहीं एक और दृष्टिकोण से जब हम अपने उत्तर प्रदेश के शासन को और इस बजट को देखते हैं तब भी मैं यह पाता हूं कि वह हमारे धन्यवाद और बधाई के अधिकारी हैं और वह चीज यह है कि जिस समय श्रीमन्, वे मंत्रीगण जो उस ओर अगली बेंचों पर बैठे हैं, जिस समय और लोग अपने कारोबार और धंधों को सीखते हैं और जानना शुरू करते हैं उस समय वह स्वतंत्रता के संग्राम में लड़ाई लड़ रहे थे और उसके फलस्वरूप जेलों में सड़ रहे थे। तो इसलिये जब एकाएक भारत स्वतंत्र हुआ तो क्षमा कीजिये, उन लोगों के सर पर भार आ पड़ा, ऐसे लोगों पर आ पड़ा जो शासन में अनभिज्ञ थे, जो जानते नहीं थे कि हुकूमत कैसे की जाती है। इस दृष्टिकोण से भी मैं समझता हूं कि वह हमारे बधाई के अधिकारी हैं।

श्रीमन्, अपने ५ साल के विधान परिषद् और दो साल के यहां के भवन के अनुभव में मैंने कई बार उस ओर से, सरकारी बेंचों से यह आरोप सुना है विरोधी दल के लिये कि विरोधी दल तो केवल विरोध लिये विरोध के करता है, कोई रचनात्मक आलोचना नहीं करता। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह कहूंगा कि यह आरोप केवल इसलिये है कि वह विरोधी दल की कठि- नाइयों को नहीं समझते। मैं यह कहूंगा कि अभाग्यवश हमारी सरकार समय देने में हर चीज में बड़ी कंजूस है। चाहे कोई विधेयक हो, कोई संकल्प हो, बजट हो हमारे पास इतना कम समय मिलता है कि विरोधी दल का तो सारा समय आलोचना में ही लगा देना पड़ता है और प्रशंसा के लिये हमें उधर के लिये छोड़ देना पड़ता है।

श्रीमन्, इस बजट में मैंने तीन मुख्य बातें देखी हैं उन पर बहुत कुछ जिक्र भी हो चुका है। मैं फिर आपसे क्षमा मागूंगा कि आंकड़ों में न जाऊंगा और न डालटन और स्टैफर्ड क्रिप्स की ही बातें करूंगा, क्योंकि यदि ऐसा करते हुये माननीय श्री राजनारायण और श्री परिपूर्णानन्द के बीच में पड़ गया तो मेरी धज्जियां उड़ जायंगी। मैं तो टैक्स, ऋण और अपने रिजर्व फंड्स से रुपया बराबर लेना, इन तीन मुख्य बातों पर कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक टैक्स का सवाल है, मैं जानता हूं कि इस साल हमारे बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। मैं यह भी जानता हूं श्रीमन्, कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि जब तक पंचवर्षीय योजना खतरे में जाती दिखाई नहीं देगी तब तक और नये टैक्स नहीं लगाये जायेंगे। यह भी मैं जानता हूं कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं "इन दि सेम ब्रेथ" उन्होंने यह भी कहा है कि एक बड़े इम्पारटेंट दल की राय है

अपने देश में कि अभी उत्तर प्रदेश में और टैक्स लगाने की गुंजाइश है। यह तो उन्होंने नहीं कहा कि माननीय वित्त मंत्री उससे सहमत हैं या नहीं, परन्तु मेरी समझ में संकेत उस ओर अवश्य है कि वह उससे सहमत है। मैं जानता हूं कि कोई भी सरकार बिना जनता पर टैक्स लगाये हुये कोई विकास योजना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। मैं जानता हूं कि टैक्स लगा कर विकास योजना पर खर्च करने के मानी ही यह होते हैं कि हमारे देश का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा हो। परंतु श्रीमन् मैं यह अवश्य कहूंगा कि टैक्सों में और विकास योजनाओं में कुछ तो संबंध होना चाहिये और टैक्स विकास योजना एक तरफ और इकोनामिक स्टैबिलिटी में भी तो कुछ न कुछ संबंध होना चाहिये। मैं यह जानता हूं कि पाई-पाई जो जनता का टैक्स द्वारा वसूल होता है वह जनता की भलाई के लिये पाई-पाई सरकार लगा देती है, फिर भी मैं इतना अवश्य कहूंगा कि इकनामिक स्टैबिलिटी की ओर भी हमको ध्यान रखना चाहिये।

आप ही यह देखें कि अभी हमारे ऊपर इस साल के अन्त तक करीब १९५ करोड़ रुपये का कर्जा होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक ले मैन हूं और एक ले मैन की हैसियत से इस फिगर को देख कर, १९५ करोड़ की फीगर को देख कर मैं तो घबरा उठा। लोग कहते हैं कि विलायत में और-और जगहों पर इतने नेशनल डेबट्स होते हैं कि वह एक एस्ट्रानामिकल फिगर हो जाती है। परन्तु मैं तो जिस वजह से घबरा उठा श्रीमन्, वह इसमें है। सन् १९२९ में जब कि अंग्रेजों का जमाना था हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी इधर बैठे थे। उन्होंने उस समय २६ करोड़ के ऋण पर घबरा कर जो कुछ कहा था वह आपकी आज्ञा से मैं सुना देना चाहता हूं —

"The financial position of these Provinces as has been revealed by the Finnance department is disquietening and unsatisfactory. We find that today this province stands indebted to the extent of 26 crores of rupees. This is a huge amount which is enough perhaps to frighten a layman, if not an expert.....

It ought to have abandoned all its extraordinary expenditure on unproductive items and also restricted its expenditure, I should say extraordinary expenditure on productive items to the lowest amount."

उस समय श्रीमन्, माननीय वित्त मन्त्री ने उस समय की सरकार को यह सलाह दी थी क्योंकि २६ करोड़ इतना भारी कर्ज लदा हुआ है, इसलिये अनप्रोडक्टिव स्कीम्स को खत्म कर दें। (अनेक सदस्य—उस समय बजट कितने का था?) बजट कितने का था यह भी अभी बतलाता हूं लेकिन इतना मैं बतला दूं कि वह सरप्लस बजट था। चाहे जितने का भी रहा हो पर था सरप्लस बजट। एक बात और सुना दूं, उस समय माननीय वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि २६ करोड़ के कर्जे के लिये अनप्रोडक्टिव स्कीम्स में खर्च करना बन्द कर दो श्रीमन्, तो क्या मैं बहुत कुछ गलत हो ऊंगा जब यहां पर खड़ा होकर आज माननीय वित्त मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूं कि १९५ करोड़ के कर्जे को देखते हुये अपने यहां भी अनप्रोडक्टिव एक, दो, तीन या चार जितनी भी स्कीम्स हों उनको बन्द कर दिया जाय। यह ठीक नहीं है, श्रीमन्, कि जब हमारे ऊपर इतना कर्जा लदा हो तो प्राहिबीशन जैसी या और भी बहुत सी इस तरह की अनप्रोडक्टिव स्कीम्स हैं जिनको मैं कह सकता हूं लेकिन इतना समय नहीं है, उनको जारी किया जाय।

श्रीमन्, कहा यह जाता है कि १९५ करोड़ रुपये का जो कर्जा है असल में वह १९५ करोड़ का नहीं है। उसमें से यह निकाल दिया जाय, वह निकाल दिया जाय और असेट्स देखे जायं तो हमारी फाइनेंशल पोजीशन कोई ऐसी खराब नहीं है। मैं कुछ हद तक मानता हूं श्रीमन्, कि १९५ करोड़ का कर्जा असली कर्जा नहीं है। इसमें से ७५ करोड़ जमींदारी एबालीशन के बांड्स निकाल दें, कुछ इधर से निकाल दें और कुछ उधर से निकाल दें तब भी ९५ करोड़ या १०० करोड़ रुपये के करीब रह ही जाता है और जिनके लिये कहा जाता है कि हमारे पास असेट्स बहुत हैं। श्रीमन्, यह देखना है कि क्या वह असेट्स ऐसे हैं जैसे कि सुरेश प्रकाश के

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

असेट्स हों। जमींदारी चली जा रही है, ४ लाख का कर्जा है, अगर और कुछ न हुआ तो उनकी कोठी नीलाम हो जायेगी। तो क्या सरकार इस तरह से रिहंड डैम वगैरह नीलाम करवायेगी, इस कर्जे को देने के लिये? इन सबसे तो आगे चलकर लाभ होगा, इनसे तो बाद में आमदनी बढ़ेगी। परन्तु श्रीमन्, खेद के साथ कहना चाहता हूं कि इन असेट्स से इससे पहले कि हमको कुछ आमदनी होने लगे शायद हमको कर्ज लेकर इनको पूरा करना पड़ेगा। इतना ही नहीं श्रीमन्, मैं तो यह कहूंगा और दुख के साथ कहूंगा और शायद दोहरा या तिहरा रहा हूं कि सरकार की अपनी योजनाओं के इम्पलीमंटेशन को देखते हुये मुझे डर लगता है कि न मालूम कितने वर्ष लग जायं जब कि कैपिटल एसेट्स आमदनी देने लगेंगे। मेरे पास बहुत समय नहीं है लेकिन मैं आपके द्वारा इतना अवश्य कहूंगा कि जब तक विकास की योजनाओं का ठीक इम्पलीमेंटेशन नहीं होगा तब तक किसी गरीब जनता को लाभ नहीं हो सकता। विकास के द्वारा नहरें बनायी जाती हैं लेकिन नहरों के बारे में आम शिकायत यह है कि इनसे समय पर पानी नहीं मिलता। विकास के द्वारा अस्पताल बनाये जाते हैं लेकिन अस्पतालों में गरीबों का कोई पुरसांहाल नहीं। गरीब काश्तकार की भलाई के लिये कहा जाता है कि जमींदारी का नाश किया गया। लेकिन जहां पर एक शोषक था, अब सरकार की मशीनरी के अनन्त शोषक हैं। मैं फिर यह कैसे मान लूं जैसे कि सरकार की योजनाओं का इम्पलीमेंटेशन है, उससे हमारे गरीब भारतवर्ष की कोई भलाई होगी। मुझे तो बहुत शक है।

अन्त में मैं माननीय मंत्रियों को यह सुझाव दूंगा कि अगर वे यह जानना चाहते हैं कि उनकी योजनाओं का सरकार की नीति के अनकूल इम्पलीमेंटेशन हो रहा है या नहीं तो वह कौंसिल भवन में बैठकर या लखनऊ में बैठकर या सीतापुर या शाहजहांपुर जैसे शहरों में जाकर जहां वे अफसरों से घिरे रहते हैं, यदि वह जानना चाहेंगे तो जनता की क्या हालत है तो यह असंभव है। यदि वह जनता की हालत देखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। अगर वह जनता के दुःख की कहानी सुनना चाहते हैं तो उन्हें अपने कानों से सुनना पड़ेगा। मुझे क्षमा किया जाय। एक मिनट और लूंगा और उनके सरकारी कर्मचारियों की हालत जब मैं देखता हूं तो मुझे याद आता है जब कि गौतम बुद्ध प्रिंस सिद्धार्थ थे तो तमाम सारी कोशिशें की गयी थीं कि उनको किसी तरह से मानसिक चिन्ता या वेदना न हो। इसी तरह से यहां पर मिनिस्टर दौरे पर जाते हैं तो हमारे सरकारी कर्मचारियों की यह कोशिश रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि उनके सामने कोई ऐसी बात आ जाय जिससे उनको कोई मानसिक चिन्ता हो जाय। श्रीमन्, अन्त में मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्रीजी से उनकी अपील के बारे में कहूंगा। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ही नहीं, मेरा दल ही नहीं, शायद विरोधी दल के वे लोग भी पूरे तौर से उनका साथ देने के लिये तैयार हैं। इस पंचवर्षीय योजना में भारतवर्ष का बच्चा-बच्चा उनका साथ देने के लिये तैयार है, लेकिन जहां प्रशंसा का अवसर है वहां प्रशंसा के साथ और जहां आलोचना का अवसर है वहां आलोचना के साथ।

*श्री मुहम्मद फारूक चिश्ती (जिला देवरिया)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को तहेदिल से मुबारकबाद देता हूं। वाकई इस बजट के पढ़ने के बाद और उनकी स्पीच सुनने के बाद सिर्फ यह राय कायम हो जायगी कि इससे बेहतर बजट मौजूदा हालत में, मुल्क की बेहतरी के लिये और पेश नहीं किया जा सकता था। हमारे फाजिल लीडर आफ अपोजीशन ने उसको आइटमवाइज, कैटेगोरिकली कंडेम करने की कोशिश की है। मैं यह अर्ज करूंगा कि इस बजट को हमारे फाजिल लीडर आफ अपोजीशन ने अनइम्प्लायमेंट स्टारवेशन और कंआस की तरफ एम करते हुये बतलाया है। ऐसा करने में मैं यह अर्ज करूंगा कि जब इसको उन्होंने आइटम वाइज कंडम किया है, इसके मानी यह हुये कि अपनी इस कोशिश में मिनिस्टर मौसूफ यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बड़ी काबलियत का इजहार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है, यानी वह अपने एम पर नहीं फेल नहीं हुये हैं। कदि किसी आइटम को डलौर आफ अपोजीशन ने कंडम न किया होता तो इसके यह मानी होते कि वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब फेल कर गये अपनी कोशिश में कि स्टारवेशन, अनएम्पलायमेंट और कंआस इस सूबे से दूर हो। लेकिन वह कहीं भी फेल नहीं हुये बकौल माननीय राजनारायण जी के और इस तौर से उनकी काबलियत मुसल्लिमा है।

अब हमें देखना यह है कि वाकई फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट को पेश करके हमको कहां पहुंचा दिया। बड़ा शोरगुल टैक्सेशन और अबवाब पर था। आपने अपना इतना वक्त इस पर सर्फ किया कि माननीय द्वारिका प्रसाद मौर्य जी को यह कहना पड़ा कि कोई नया टैक्सेशन इम्पोज हुआ है जो उस पर इतना वक्त सर्फ किया जा रहा है? आखिर हमें यह भी देखना है कि टैक्सेशन के क्या असरात होते हैं। हमारे फाजिल लीडर आफ अपोजीशन की पूरी तकरीर सेल्फ कांट्रेडिक्टरी है। टैक्सेशन तो एक खुशहाली की निशानी है। अमीरों से रुपया लेकर गरीबों पर सर्फ कर देना इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। चुनान्चे खुद राजनारायण जी ने अपनी तकरीर में कह दिया कि फलां टैक्स कम हो गया जिस पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। सेल्स टैक्स और एन्टरटेनमेंट टैक्स कम हो गया है। इससे उन्होंने यह जाहिर किया कि मुल्क की हालत खराब होती जाती है। असल में टैक्स इंडिकेटर हैं मुल्क की खुशहाली का और उसकी गरीबी का। उमरा से टैक्स लेकर उसको आम जनता पर खर्च कर देना। इससे अच्छी स्कीम और कोई नहीं हो सकती और अगर यह देख लिया जाय तो यह बहुत अच्छा है।

अब अबवाब के मुताल्लिक मेरे लायक दोस्त ने यह फरमाया कि उनके दोस्त जमींदार लोग यह टैक्स नहीं लिया करते थे और यह गवर्नमेंट इतना जुल्म करती है और इस गवर्नमेंट ने तो उसकी वसूली भी शुरू कर दी है। अबवाब एक बहुत छोटी सी रकम है। वह छोटी हो या बड़ी, लेकिन जमींदार उसको लेकर खुद खर्च नहीं कर सकते थे। उस रकम को पब्लिक पर खर्च करना होता है। चुनान्चे वह पब्लिक से रुपया लेकर उन्हीं पर खर्च करते इसकी जमींदारों को परवा नहीं हो सकती थी। अगर यह सरकार एक रुपया के साथ एक पैसा और मिला कर, जो जायज है वसूल करना, जनता के कामों में खर्च करती है तो इससे हमारे अपोजीशन को क्यों तकलीफ होती है? इससे तो उल्टी खुशी होनी चाहिये कि इस सरकार ने जायज रकम की वसूलयाबी को नजरन्दाज न करके उसे वसूल करके अपनी सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश की है। पुलिस के खरचे के मुताल्लिक बहुत जोर दिया गया है कि इस पर बहुत ज्यादा सर्फा हो रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमें मजबूरन पुलिस पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। यह स्थिति कैसे पैदा होती है इसका मेरे लायक दोस्त लीडर आफ अपोजीशन खुद गौर करके वजह ढूंढें और समझ लें कि यह जरूरत क्यों पैदा हुई। हमारी सरकार हरगिज इसकी ख्वाहिशमन्द नहीं है कि इतना रुपया पुलिस पर सर्फ किया जाय। बल्कि उसकी स्कीम्स जैसा कि बजट के देखने से मालूम होता है यह हैं कि विलेज डिफेंस फ़ोर्सेज़ बनाई जावें और लोग अपने गांव की हिफाजत खुद कर लें। लेकिन हालात मौजूदा से जाहिर होता है कि हमारे साहेबा ने अपोजीशन जो हमारे लिये ब्लैसिंग होनी चाहिये थी उनकी छोटी छोटी बातों को देखा जाय तो पता चलेगा कि वह यह नहीं चाहते कि सरकार कोई तरक्की का कदम उठावे, बल्कि वह यह चाहते हैं कि पब्लिक को डिसैटिसफैक्शन हो और वह यह समझे कि यह जालिम सरकार अबवाब वसूल करती है जो जमींदारान भी नहीं लेते थे। आम जनता अब ऐसी नहीं रही है सन् १९५४ में कि इन बहकावों में आ जावे। चुनान्चे इस खर्च पर जो जनता के लिये ही किया जा रहा है, इस पर एतराज करना, इसका ज्यादा बतलाना, मेरी समझ में नहीं आता कि इसके क्या मानी हैं। लायक लीडर अपोजीशन ने कोई ऐसा बजट बना कर पेश नहीं किया है कि वाकई अगर वह इस बजट से अच्छा होता तो मैं इस हाउस से दरख्वास्त करता कि उसको कबूल कर ले। सैल्फ-कंट्रैडिक्शन उनकी स्पीच में हर कदम

[श्री मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती]

पर है। एक तरफ तो टैक्सेशन को मना किया जाता है, आमदनी के जरिये बढ़ाने के लिये मना किया जाता है और दूसरी तरफ तालीम मुफ्त देने की सिफारिश की जाती है। कहा जाता है कि दवाइयां हर शख्श को मुफ्त दी जायं हालांकि सरकार की तरफ से इसकी कोशिश की जा रही है और इस बजट में न सिर्फ इसकी गुंजाइश ही है बल्कि इसके इंतजामात भी मौजूद हैं कि तालीम ज्यादा से ज्यादा दी जाय, दवाइयां हर शख्श को मुफ्त बहम पहुंचाई जायं। लेकिन मुखालिफ पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि एक तरफ तो टैक्स वसूल किया जाय और दूसरी तरफ मुतफर्रिक तौर पर यह कहना कि यह इखराजात होने चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि ये दोनों चीजें कैसे जोड़ी जा सकती हैं और किस तरह से एक साथ रखी जा सकती हैं।

जहां तक पुलिस के इखराजात के मुताल्लिक उनका कहना है, वाकया यह है कि जब तक मुल्क में अमन और चैन न हो तब तक कोई भी स्कीम कामयाब नहीं हो सकती। तालीम के लिये पुलिस की जरूरत है, अच्छी पैदावार के लिये पुलिस की जरूरत है, इन्तजाम के लिये पुलिस की जरूरत है। गरजे कि इसका ताल्लुक हर मुहकमे से है और जिन्दगी के हर शोबे से है। इसलिये यह सोचना कि इस मुहकमे का ताल्लुक और किसी मुहकमे से नहीं है, गलत है। केन के मुहकमे के लिये पुलिस की जरूरत होती है। फिसादों को रोकने के लिये पुलिस की जरूरत होती है, गैर जरूरी फिसादात और सिर्फ बदअमनी पैदा करने के लिये जो फसादात होते हैं उनको रोकने के लिये पुलिस की जरूरत होती है। अपोजीशन का फर्ज तो यह था कि वह फसादात को रोके और मुल्क में अमन कायम करे और फिर इस सदन में पेश करे कि हमने यह किया और यह कि गवर्नमेंट ने पावर में होते हुये ऐसा नहीं किया। लेकिन बजाय इसके उनके सामने तो यह नक्शा है कि वे गवर्नमेंट की किसी स्कीम को चलते हुये नहीं देखना चाहते। विलेज डिफेंस फोर्सेज अगर वाकई हर तरीके से कामयाब हो जायं तो वाकया यह है कि पुलिस के अखराजात घट जायं लेकिन वे लोग घटने भी दें तो? बहरहाल हमें अपनी सरकार से यह उम्मीद है कि बावजूद अपोजीशन के लोगों को भड़काने के, गैर जरूरी फसादात के बावजूद, जनता से इस बात के कहने के कि हम पर बेजा टैक्स लगाया जा रहा है, विलेज डिफेंस फोर्स कायम होगा और हम लोग इसको कामयाब करके एक मिसाल दुनिया के सामने पेश करेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने सन् ५४–५५ के बजट को उपस्थित करते हुये जो अपना भाषण दिया है उसमें हमारे प्रदेश की पिछले वर्षों की प्रगति, उसकी आने वाले वर्षों की हालत तथा हमें क्या क्या करना है उसका पूरा-पूरा परिचय दिया गया है तो भी विरोधियों ने कभी-कभी धन्यवाद देने के बावजूद भी कई बातों की तरफ शंकायें उपस्थित की हैं। मैं श्रीमन्, उन बड़ी बातों पर लंबी-चौड़ी बातें करने का हक तो नहीं रखता मगर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय राजनारायण जी ने जो बुनियादी शंकायें उपस्थित की थीं उनमें सर्व प्रथम यह थी कि क्या यह बजट कल्याणकारी राज्य का बजट है? उन्होंने यह कहा था कि यह बजट फेअर वेल बजट है, किसी वेलफेयर स्टेट के लिये। जुम्लों में जुम्बिश हो सकती है और वह अच्छी भी मालूम हो सकती है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह बिलकुल गलत है कि इस आशय से जुम्लों के बेजोड़ पैमाने पर वाकयात नापे जायं। जिस किसी ने भी इस बजट को अच्छी तरह से देखा होगा तो उससे यही मालूम हुआ होगा कि यह बजट किसी भी अंडर डेवलेप्ड कन्ट्री के सर्वोदय की ओर जाने के प्रयास का नतीजा है, इसलिये मैं उसको अंडर डेवलेप्ड कंट्री के प्लानिंग पीरियड का प्लांड बजट कह कर पुकारता हूं।

जहां तक इस बात पर उन्होंने शंका की और हमारे सामने कुछ बातें बतलायीं कि अब तो इस देश में शुद्ध पुलिस का राज्य चलने वाला है और अखबारों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तुम भी, विरोधी दल की तरह ही कुचले जाने वाले हो, ऐसी इस बजट की प्रतिक्रिया होने वाली है, तो मैं उत्तर में यही कहना चाहता हूं कि शायद किसी भी जमाने में, किसी देश में भी

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जितनी इज्जत और कद्र आज हमारे देश में हमारे संविधान के अन्तर्गत हुई है और होती रहती है न उतना अमूमन होना सम्भव है, न उतना कभी कहीं हो ही सकता था। मैंने सुना है कि लंदन के हाइड पार्क में लोग अपनी-अपनी बकवास करने के लिये ४, ६, १० बेंचें किराये पर ले लिया करते हैं, और वहां यह कार्य हफ्ते में एक या दो ही दिन हो सकता है, लेकिन यहां पर तो बेंचों को किराये पर लेने की जरूरत नहीं है, गाड़ी पर चले जाइये, जगह मौजूद है, होटलों में चले जाइये जगह मौजूद है और वहां पर सब की बातें सब तरह की सुनते जाइये। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो इस मात्रा में हमारे प्रदेश में बढ़ गयी है कि मैं ऐसा समझता हूं कि यदि हमें अपनी स्वतंत्रता को जीवित रखना है, यदि हमारे देश के प्रगतिवाद को जिन्दा रखना है, यदि हमें अपने देश के जनस्वातंत्र्य की सचमुच रक्षा करनी है तो इन बकवास करने वालों को स्वतंत्रता का अपहरण निश्चय ही करना चाहिये जो हमारी बड़ी मुश्किल से पाई हुई स्वतंत्रता का खातमा किया चाहते हैं। मैं आपके द्वारा उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं कि केन ग्रोवर्स की हड़ताल का नाम लिया जाता है, चाहे उसे समाजवादी किसी भी नाम से पुकारें लेकिन वास्तव में वह समाजवादी कार्यकर्ताओं की ही सरकार के यंत्र के विरुद्ध हड़ताल है। वह किसी केन ग्रोवर्स की हड़ताल नहीं है, उसका किसी गन्ना उत्पादक से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो गन्ना उत्पादक है वह तो कहता है कि मेरे पैर में कांटा नहीं है लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पैर में कांटा है और वह तुम्हें दिखलाई नहीं पड़ता है और मैं चीरफाड़ कर तुम्हारे पैर में से उस कांटे को निकालूंगा। आज इस तरह की भावनायें विरोधियों की हैं। विरोधी दल के माननीय नेता श्री राज नारायण जी तो यहां पर मुझे दुख है कि उपस्थित नहीं हैं, वे तो कह कर चले गये लेकिन उनके डिप्टी को मैं कुछ आंकड़े आपके जरिये पढ़ कर सुनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि हमारे देश से तो शिक्षा का लोप होता जा रहा है। शायद माननीय राज नारायण जी और मेरे पढ़ने के बाद हो सकता है कि शिक्षा का लोप होता जा रहा हो लेकिन मैं उन्हें एक पुस्तक जो ऐसी भाषा में है जिसको हम और वे सभी समझते हैं, पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि अगर सिर्फ शिक्षा पर व्यय के आंकड़े को ही देखा जाय तो सन् ४५–४६ में जहां २,५७,४६,००० रु० था वहां सन् ५३–५४ में ८,५४,७४,२०० रु० हुआ है और प्रति वर्ष कोई वर्ष भी ऐसा नहीं है जब कि लाखों रुपये की मात्रा में वह खर्च शिक्षा के ऊपर बढ़ता न जा रहा हो। यही नहीं कि शिक्षा के ऊपर खर्चा बढ़ा बल्कि शिक्षा प्रणालियों में जो भिन्न-भिन्न उपायों से परिवर्तन किये गये हैं, शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने की जो चेष्टा की गयी है अगर उसके ऊपर नजर डाली जाय तो उन्हें दिखलाई पड़ेगा कि उत्पादन को बढ़ाने में हमारे विद्यार्थियों ने बड़ी मदद की है। हजारों लाखों की तादाद में विद्यार्थियों ने खेती के काम, नेवार बुनने के काम और दूसरे उद्योग धंधे के बहुत से कामों में मदद पहुंचायी है, जो हमारे रोज के आर्थिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले काम हैं उनमें कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको उन्होंने अपनाया न हो। साथ ही श्रीमन्, कहा गया है कि यह हमारे वेलफेयर स्टेट का जो बजट है, हमारी सरकारी नौकरियों पर खर्च कम होना चाहिये। विरोधी दल के कहने के मुताबिक पढ़ने-लिखने पर भी शिक्षा पर कम खर्च होना चाहिये, विकास के काम पर कम खर्च होना चाहिये, अन्न के उत्पादन पर कम खर्च होना चाहिये, यानी उत्पादन कम हो जायगा तो क्या देश में बेकारी न रहेगी? तो मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े मैं विरोधी दल के सामने पेश करने वाला हूं यद्यपि वे आंकड़ों से घबराते हैं लेकिन वे आंकड़े ऐसे हैं जो लगते हैं तो छोड़ते नहीं है। वे बड़े मजबूत आंकड़े हैं। और वे उन आंकड़ों को देखने की कोशिश करें। और तब ही उनकी समझ में आ जायेगा कि हमारे प्रदेश ने कितनी प्रगति की है। हमारे प्रदेश का मुकाबला ट्रावंकोर और कोचीन से करना बिल्कुल गलत बात है। हमें अपनी जनसंख्या और अपने क्षेत्रफल को भी देखना होगा और उन साधनों को भी देखना होगा जो प्रकृति ने हमें दिये हैं और जिन पर आधारित है हमारे प्रदेश और देश की आर्थिक व्यवस्था। श्रीमन्, उनको देखते हुये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक १९४६–४७ में हमारे प्रान्त में २३० हजार टन गल्ला बाहर से मंगा कर

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना]

इस प्रदेश के लोगों को खिलाना पड़ा था वहां ५०-५१ में सिर्फ ४७ हजार टन गल्ला मंगाना पड़ा और भुखमरी के उस भयंकर और उग्र रूप से हमने मुकाबिला किया और जीता।, श्रीमन् अगर सन् १९४७ में हमारे प्रदेश में जो उत्पादन हुआ चाहे वह कपड़ा हो, चाहे शकर हो, चाहे कांच के बरतन हों, चाहे लोहे का सामान हो, उन सब के मूल्य की अगर टोटल करने की कोशिश की जाय और उसी से पढ़ कर मैं उन्हें सुनाता हूं जिसका नाम माननीय राजनारायण जी ने कल लिया था "रिसर्च इन उत्तर प्रदेश", तो श्रीमन्, जहां सन् १९४८-४९ में हमारे प्रदेश की पैदावार ८४५.३४ करोड़ रुपये की थी वहां सन् १९५० में वह ९००.८४ करोड़ रुपये की हो गई। अगर इस प्रकार से देखें तो हमने करीब सौ करोड़ रुपये का उत्पादन सन् १९४८-४९ के मुकाबिले में सन् १९५०-५१ तक में बढ़ाया।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी देश में उत्पादन का इस जोरदार मात्रा में बढ़ जाना किसी प्रदेश की गरीबी का द्योतक है। अगर कोई अर्थशास्त्री इस तरह की बात कहता है तो वह उसके लिये मुबारक है। अगर कोई अर्थशास्त्री ऐसे राज्य को बुरा राज्य कहे तो कहे लेकिन हमारे लिये तो वह कल्याणकारी राज्य है और अगर ऐसे अर्थ शास्त्री को ही विरोधी दल के लोगों ने पढ़ा है तो उनसे कोई न्यायसंगत बात सुनने की आशा करना बड़ा दुश्वार होगा। अगर हमारे प्रदेश के उन करोड़ों रुपये का विवरण जिसे हमारे वित्त मंत्री ने सूक्ष्म रूप से उक्त भाषण में किया था, देखा जाय तो सन् १९४६-४७ के बाद हमने कितने नये गांव बसाये, कितनी नई भूमि तोड़ी इसका भी ख्याल करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ तराई के इलाके के आंकड़े देखें तो वहां ही ४५ हजार एकड़ नई भूमि इस दौरान में तोड़ी गई, ३३ नये गांव बसाये गये, १६ सौ के करीब नये घर बनाये गये, ७५ मील लम्बी सड़क बनाई गयी और ४० ट्यूबवेल सिर्फ तराई के इलाके में लगाये गये। हस्तिनापुर, द्रुपुर. और दूसरी जगहों पर बड़ी-बड़ी, लम्बे-चौड़े पैमाने पर सुख-समृद्धि के साधन जुटाये गये। किसानों के घरों पर जा जा कर उनके घरों को बदलने का प्रयास किया गया। एक बड़ी आशंका श्रीमन् हमारे बालेन्दुशाह जी ने प्रकट की और सुरेश प्रकाश जी की ओर से भी इस रूप में आई कि इतना रुपया जो प्लानिंग पर खर्च हो रहा है क्या वह अभी ही करना जरूर है ? क्या वह खर्च सूबे के लिये काबिले बरदाश्त है ? उन्हें इस पर आपत्ति नहीं है कि काम होना चाहिये, लेकिन उनके सामने प्रश्न यह है कि हम इन कामों को धीरे-धीरे करें या जल्दी करें और कब करें। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यू० पी० को फाइव ईयर्स प्लान के अन्तर्गत १३० करोड़ रुपया खर्च करना है और यदि हम उसको पूरा खर्च भी कर दें तो हमें देखना है कि इस प्रदेश के रहने वालों की जरूरतें कहां तक और कितनी पूरी होंगी। श्रीमन्, अगर पर कैपिटा इन्कम के मापदण्ड से हम इसको देखें तो मालूम होगा कि इस १३० करोड़ रुपये को खर्च करने के बाद, वित्त मंत्री अगर इसके अन्दर खर्च को सम्हाले रहें, तो भी कई गुना कई बार खर्च होने के बाद इस प्रकार के चार प्लान निकल जाने के बाद, हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम २२ साल के बाद दुगुनी होने पर आयेगी। मैं एक और तरफ भी माननीय राजनारायण जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर वह चाहें तो हमारे प्रदेश की जो आर्थिक आय है उसे भी देखें। मुझे बड़ा दुःख हुआ और खेद हुआ कि उन्होंने ऐसी बातें कहीं जो वास्तविकता के विपरीत हैं और किताबों में उन्होंने सिर्फ उतनी बातें देखीं जितनी उन्हें पसन्द आईं, जो कहने में शायद कुछ लोगों को अच्छी मालूम होती हों और जिनकी चर्चा ज्यादा होने की गुंजायश थी-- पर जो मापदंड है सचाई का, उससे जांच करें तो उन्हें यही मालूम होगा कि हमारे प्रदेश में पर कैपिटा इनकम ४६-४७ में १७६.८ रुपया थी और

हमारे प्रयास के बाद वही ५०–५१ में २५५.७ रुपया हो गई है। इस तरह से हमारे देश की और हमारे प्रदेश की आर्थिक आय (पर कैपिटा इनकम) बढ़ी है। हमने खाद्यान्न अधिक पैदा किये। उत्पादन के क्षेत्र में सभी चीजों का उत्पादन हमारा बढ़ा। हमने रोजगार को बढ़ाया। हम मानते हैं श्रीमन्, और किसी को भी यह कहने में गुरेज नहीं होगा कि आज हमारे प्रदेश में बेकारी है। इस बात को माननीय वित्त मंत्री जी ने भी माना है। लेकिन यह शिकायत हो सकती है कि वित्त मंत्री जी ने उसको कुछ ऐसा ढांचा दे दिया, शब्दों के हेर फेर में कि बेकारी हर मुल्क में होती है और बेकारी का होना कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं है। मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि यह वास्तविकता का रूप था और स्वरूप था जो उन्होंने हमारे सामने रखने का प्रयास किया। यह तो एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सेचुरेशन पर, कम्प्लीट सेचुरेशन पर एम्पलायमेंट आता नहीं कुछ न कुछ फर्क रह जाता है क्योंकि अगर हर आदमी को इम्प्लायमेंट मिल भी जाय तब गेनफुल इम्प्लायमेंट का प्रश्न आता है। और जब गेनफुल इम्प्लायमेंट हो जाय तब कहीं उस समस्या का एक हल निकलता है। लेकिन जहां पर इस बेकारी की समस्या की जिम्मेदारी सरकार पर आती है वहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हम दूसरी बार बजट के अवसर पर इस भवन में आयें तो मैं अपने विरोधी दल से पूछूंगा कि उन्होंने हमारे कौन कौन से कारोबार को कितना कितना बढ़ाया। मैं केवल चमड़े के कारोबार की ही ओर उनका ध्यान आकर्षित करता हूं। हमारे हर जिले में चमड़ा बहुत खराब जाता है (हंसी)। यह हंसने की बात नहीं है। शायद वे धर्म से घबड़ाते हैं। हमारे प्रदेश में इस समय चमड़ा नष्ट प्रायः होता चला जा रहा है। चमड़े के कारोबार से उन लोगों के लिये जो कि चमड़े का काम करते हैं उनकी सम्पत्ति बढ़ाने के लिये क्या आप सहकारी संस्थाओं द्वारा इस प्रदेश की इनकम को बढ़ाने के लिये प्रयास नहीं कर सकते? मैं इन बातों को भी विरोधी दल की ओर से सुनना चाहूंगा। ताकि स्पष्ट हो जाये कि विरोधी दल बातें ही नहीं करता, कुछ काम भी जानता है वर्ना तो ऐसा प्रतीत होगा कि विरोधी दल केवल बुराइयों के करने की क्षमता रखता है। अतः जब वह कहें खराब है और सब खराब है, तो यही माना जायगा कि अपने ढंग से वह मजबूर हैं।

श्रीमन्, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे विरोधी नेता की सारी बजट सम्बन्धी तकरीर हमारे देश की उन बुढ़िया माताओं की तरह से हुई है जिनको कि हर मौके पर रोना ही आता है। मुझे उनके साथ हमदर्दी है और उसके लिये मुझे कोई खास दुःख नहीं है।

अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार के विभागों में भी एक बीमारी लगी हुई है कि हर विभाग अब अपना अलग एक प्रेस खोलना चाहता है और उसके लिये माननीय वित्त मंत्री जी के पास रुपया भी निकल आता है। जैसे ऐग्रीकल्चर का छापाखाना खोलो, कोआपरेटिव का छापखाना खोलो और शायद इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का भी छापाखाना खोलो, इस सब के लिये माननीय वित्त मंत्री जी के विभाग से रुपया मिल जाता है। तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यापार में, व्यक्तिगत क्षेत्र में रुपया लगा हुआ है उससे निकाल करके उसे आप दूसरे क्षेत्र में लगाइये। यदि आपने मशीनें खरीदी भी हैं तो उन्हें बेंच डालिये, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐशबाग में सेनोटोरियम नहीं खोलना है, वहां काम काफी होता है। अगर एक बार देर में बजट आया तो क्या हुआ। इन शब्दों के साथ में सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार अपने एक्सपेन्डीचर ऐसे क्षेत्र में न करें जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत पूंजी लग सकती है ताकि सरकारी रुपया आर्थिक

[श्री हमवती नन्दन बहुगुना]

हरकत (Economic Activity) को कम करने के बजाय बढ़ावे और देश की पूंजी व्यर्थ न जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के ऊपर पक्ष और विपक्ष से इतने व्याख्यान हो चुके हैं कि इस पर और प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने खड़े होने की जुरअत इस लिये की कि एक पहलू पर मैं भी अपने विचारों को व्यक्त कर दूं। उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने वित्त मंत्री जी का, सरकार को और इस विभागके कर्मचारियों को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया। खास कर वित्त मंत्री महोदय को तो मैं अभी तक इतना ही जानता था कि आप एक अच्छे पाक मुसलमान, रोजा नमाज के पाबन्द, अच्छे वकील, सुलझी तबियत के राजनीतिज्ञ, उत्तम वक्ता और बहुत मेहमानवाज हैं और अंग्रेजों के जमाने में आजादी की लड़ाई में ही नहीं बल्कि मुसलिम लीग के तूफान में भी पहाड़ की तरह से अटल रहे लेकिन पार साल का बजट पढ़ करके ऐसा मालूम होता है कि आप अर्थ शास्त्री भी हैं, फाइनेंस को भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिये तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

अब तो सवाल यह पैदा होता है कि जब बजट बहुत अच्छा है, उम्दा है, हर तरह से अच्छा है, तो फिर मुखालिफत क्यों होती है। विरोधी दल के नेता साहब दो घंटे तक व्याख्यान देकर इसकी मुखालिफत क्यों करते हैं, यह सवाल बहुत आसानी से सामने आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि जहां खजाना होगा, उसको लेने वाले भी पैदा होंगे, मौका लगेगा तो तलवार से लेंगे और नहीं मौका लगेगा तो वोट ले लेने की कोशिश करेंगे। ज ां शक्ति होगी वहां उसको लेने वाले भी पैदा होंगे, । जहां ताकत होगी उसको हथियाने वाले भी पैदा होंगे। शक्ति में जहां खूबी है वहां इतनी खराबी भी है। इस हथियाने के दो तरीके हैं, एक तो जायज और दूसरा नाजायज। कुछ लोग तो जान बूझ कर ग़लती करते हैं, समझते हैं कि हमारा रास्ता ग़लत है, ठीक नहीं है, मगर वह जानते हैं कि अगर हम गलत काम नहीं करेंगे तो कुछ पा ही नहीं सकते, यह मजबूरी है। कुछ लोगों को ग़लत फहमी होती है। अच्छे हैं, ईमानदार हैं, मगर वह ग़लती से ग़लत काम कर बैठते हैं। तो जो लोग जान बूझ कर ग़लती करते हैं उनको तो समझाया नहीं जा सकता, उनके लिये तर्क पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन जिनको ग़लत फहमी हुई है, उनको जवाब दिया जा सकता है।

अब मैं कुछ बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार अच्छे काम कर रही है मगर उर्दू अखबारों में क्या छपता है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अलीगढ़ कनवेंशन हुआ था, क्या क्या लेक्चर वहां हुए थे, क्या नक्शे बन रहे हैं, क्या स्कीमें बन रही हैं, क्या तैयारी हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुसलिम लीग ने फिर जन्म ले लिया है, ओवर लुक करने में नुकसान हो जायगा। इसी लखनऊ में सुलह की गयी थी सन् १९१६ में, ओवर लुक किया गया था, ग़लत बात मान ली गयी थी, और फिर उसका नतीजा हुआ मुल्क का बटवारा। आप उर्दू अखबारों को पढ़ें, देखें, तो आप को मालूम होगा कि फिर वही स्कीम बन रही है कम्युनैलिज्म फैलाने की। वहां से अखबार रोज छप कर आते हैं, आपके यहां पढ़े जाते हैं, और फिर रख दिये जाते हैं। पता नहीं क्या कुछ लोग समझते हैं कि यह आग आपसे आप बुझ जायगी। हुजूर बनाना मुश्किल होता है, लेकिन बिगाड़ना मुश्किल नहीं होता है। ओवर लुक करने में नुकसान हो जायगा। मानता हूं कि इल्मी साहब गिरफ्तार हुए हैं और वह

इस वक्त जेलखाने ही की हवा खा रहे हैं। लेकिन उनकी स्कीम बन चुकी है, उनका नक्शा बन चुका है, अब वह शहीद होने के लिये बन्द कर दिये गये हैं और इससे उनका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मेरी गुजारिश यह है कि जिस वक्त कोई ग़लत बात की जाय तो उसका जवाब फौरन दे दिया जाय, उसकी उपेक्षा करने में नुकसान होगा। यह वही लोग हैं जो पुराने लीगी हैं इसके अतिरिक्त कल तक जो हमारे साथ कांग्रेस में कंधे से कंधा मिला कर अंग्रेजों से लड़े हैं, जेलखाने में रहे हैं, वह भी आज क्या करते हैं। साथ बैठते हैं तो दूसरी बात करते हैं और अलग बैठ जाते हैं तो दूसरी बातें करने लगते हैं। अभी एक डेप्यूटेशन गया है और राष्ट्रपति से मिला है, मांग पेश हुई है कि हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर हिन्दी लादी जा रही है। उर्दू में दरख्वास्त देने का मौका मिलना चाहिये। मैं आपसे अर्ज कर देता हूं कि वह प्रचार वहीं नहीं रुकेगा। उसके बाद मुकदमा फेडरल कोर्ट में दायर होगा और फिर सत्याग्रह होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जुल्म कर रही है, सख्ती कर रही है। क्या उर्दू को मिटाना चाहती है? हरगिज नहीं किन्तु एक तबके में जरबदस्त प्रचार हो रहा है कि हमारी सभ्यता और तहजीब मिटाई जा रही है। हिन्दू कहते हैं कि कांग्रेस सरकार मुसलिम परस्त है और मुसलमान कहते हैं कि हिन्दू राज है हमें कौन पूछता है।

"जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफ़िर जाना
और काफ़िर हैं समझते कि मुसलमां हूँ मैं।"

अगर सरकार पक्षपात करेगी तो मुखालिफत होगी, ग़लत काम करेगी तो शिकायत होगी लेकिन जब सेक्युलर गवर्नमेंट है, इन्साफ़ करती है तो शिकायत कैसी? खास कर उनकी शिकायत, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वह भी शिकायत करते हैं, इसकी उपेक्षा बड़ी खतरनाक होती है।

इस कांग्रेस सरकार के आने के पहले ही सब से पहले हरिजन भाइयों के लिये महात्मा गांधी ने आन्दोलन किया। उन्होंने कहा कि यह जुल्म है, भाई सब बराबर हैं। यह क्या ज्यादती है कि हमारे बर्तन कुत्ता बिल्ली छू लें तो अशुद्ध न हों और अगर भाई छू लें तो अशुद्ध हो जायं। प्रचार हुआ। कांग्रेस मैन सामने आये, अपनी बिरादरी से बाहर हुए, उनकी मुखालिफत हुई लेकिन कांग्रेस भाइयों ने नहीं माना और अपमान की परवाह छोड़ कर आन्दोलन करते रहे तथा कांग्रेस गवर्नमेंट ने आने के बाद हरिजनों को काफी नौकरियां दीं, हमारे आनरेबिल मिनिस्टर बैठे हैं, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बैठे हैं, मेम्बर बैठे हैं। लेकिन हुजूरवाला सदन में सवाल क्या होते हैं? व्याख्यान क्या होते हैं। एक हरिजन साहब जो कांग्रेस में थे किन्तु निकाल दिये गये। इस वक्त दारुलशफ़ा में उनका क्लास लगता है, ट्रेनिंग होती है, प्रोपेगेंडा होता है और आपको पता भी शायद नहीं उनके पड़ोसी साहब कहते थे कि इस कमरे के पास बैठना हराम हो जाता है। मैं इत्तफाक करता हूं कि आज भी छुआछूत देहातों में है, आज भी ज्यादती होती है, नफ़रत होती, लेकिन हुजूरवाला वह चीज कानून बना कर ही तो दूर नहीं की जा सकती है। सदियों से जिसका संस्कार बन गया है वह सिर्फ कानून बना कर ही दूर नहीं की जा सकती है, उसके लिये जनता में प्रचार की जरूरत है। मैं मानता हूं कि सब वर्णों में छूत की बीमारी है। यह तो जरा देखें कि करपात्री जी ऐसे विद्वान् जो संयासी हैं वह कहते हैं कि हरिजनों को मंदिर में नहीं जाने देंगे। क्या बात है। जो भगवान् रामचन्द्र शबरी के जूठे बेर खाये, जो भगवान रामचन्द्र जी गिद्ध को गोद में ले लें, जो शंकर भगवान् जनता की भलाई के लिये सब से पहले जहर पी लें उनके लिये कहा जाय कि तुम उनके दर्शन नहीं कर सकते हो। यह कहां का न्याय है मगर यह बात हमारे कुछ संयासीवृन्द करते हैं।

[श्री सीताराम शुक्ल]

क्यों करते हैं, क्या सरकार हरिजनों का उत्थान नहीं चाहती है ? नहीं, चाहती है। तो हुजूरवाला जरूरत है प्रचार करने की। चुप रहने में नुकसान हो जायगा। ग़लत प्रचार अगर एक तरफ से होता रहेगा और आप चुप रहेंगे तो उसका असर बुरा पड़ सकता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

इसके साथ ही एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आज भी आपके बहुत से भाई कांग्रेस वर्कर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान लड़ाई है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई के जमाने में अपनी जान लड़ायी है, जिन्होंने तय किया था कि :—

सर फ़रोशी की तमन्ना आज मेरे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए क़ातिल में है।

जिनका ख्याल था कि हमारी जिन्दगी में स्वराज्य नहीं होगा, जिनका ख्याल था कि हमें तो गोली मार दी जायगी और हमारी जायदाद जब्त हो जायगी, स्वराज्य तो बच्चे देखेंगे लेकिन आज आजादी मिलने के बाद पोलिटिकल सफ़रर्स की हालत अच्छी नहीं है। आज भी जहां हमारे कुछ देशभक्त लोग हवाई जहाज से उड़ते हैं वहां अनेक देशभक्त नंगे पैर चलते हैं, उनके पैर में जूता नहीं है। पहले उनको चन्दा मिल जाता था, जब जेल जाते थे तो उनके बच्चों के खाने पीने का इन्तजाम लोग कर दिया करते थे, लेकिन आज पब्लिक कहती है कि अब तो स्वराज्य हो गया, तुम्हारा राज्य है, अब तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है और हमारे नेता लोग कहते हैं कि सैक्रीफ़ाइस करो। किन्तु त्याग का समय और हद होती है। हद से अधिक कोई काम कैसे हो सकता है। इसलिये इस तरफ जरा ध्यान दीजिये। अगर यह तबका जो हमारे साथ लड़ता रहा, जेलों में भी और बाहर भी, अगर वह तकलीफ़ में रहा तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आप कुर्सियों पर बैठते हैं तो उनकी दिक्कतों की याद आती है कि नहीं और यदि आती है तो तकलीफ़ होती है कि नहीं और यदि होती है तो क्या सबूत। हमारे बहुत से साथी इस जाड़े के महीने में एक चादर ओढ़ कर सोते हैं। कहा यह जाता है कि हमने जमीनें दी हैं, नौकरियां दी हैं। लेकिन हुजूरवाला, मैं यह कहना चाहता हूं कि नौकरी देने के बाद उसको राजनीति से अलग हो जाना पड़ता है, वह पोलीटिक्स से रिटायर हो जाता है। इसी तरह से खेती करने के बाद भी उसको राजनीति से अलग होना पड़ता है और पोलीटिकल आदमी बहिश्त में भी राजनीति को छोड़ कर जाना पसन्द नहीं करता। राजनीति में काम करते हुए जो कुछ मदद की जा सकती है उसे करना चाहिये। वह देखता है कि स्वराज्य मिलने के बाद भी उसके देश के ग़रीब भाई परेशानी में हैं तो वह अपने आराम पर ठोकर मार देता है और जनता की सेवा में लग जाता है उसने यही सीखा है कि :—

"न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं, नपुनर्भवम्
कामये दुःख तप्तानाम् पुनर्वं, प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्।"

न तो उसको स्वर्ग चाहिये, न राज्य चाहिये और न मोक्ष ही चाहिये। सिर्फ दुखियों के दुःख को दूर करना चाहिये। मेरी गुजारिश है कि उनको सहायता दीजिये। उनको पेंशन दीजिये और सूचना विभाग में उनसे काम लीजिये और आनन्द कीजिये। अन्त में मैं अपने विरोधी भाइयों से निवेदन करता हूं कि समय की पुकार को सुनिये।

मेरे दोस्त ने कहा है कि हमें उनकी परवाह नहीं है वह हमारे साथ आयें या न आयें, हम पंच-वर्षीय योजना पूरी करेंगे। किन्तु मेरी प्रार्थना है कि हमारे विरोधी

साथी जो नौजवान हैं वह भी मुल्क की भलाई चाहते हैं और हम भी चाहते हैं लेकिन दोनों के रास्ते विभिन्न हैं। तब एक साथ क्यों नहीं आ सकते। एक बड़ा मकान था, गिर पड़ा (लाल रोशनी हो गई है, इसलिये अब खत्म करता हूं) कोई कुछ ले गया और कोई कुछ ले गया। एक पत्थर पड़ा हुआ था उसमें हीरा जड़ा हुआ था। औरतें उस पर पैर रगड़ती थीं। एक जौहरी ने देखा किन्तु सोचा कि यदि हीरे को हाथ से उठाया जाय तो शायद लोग शुबहा करें और लोग न ले जाने दें इसलिये उसने पैर से ठोकर मार कर हीरा को अलग कर दिया और पैर ही से उठा लिया। घर आकर उसने अपनी स्त्री से कहा कि आज तो किस्मत खुल गई यह हीरा मिल गया। उसकी स्त्री ने देख कर कहा कि यह तो कांच का टुकड़ा है, कटा हुआ है, हीरा कहां है तो हीरे ने कहा कि जब औरतें हमें पैर से रगड़ती थीं तो वह पहचानती नहीं थीं तब मुझे कोई चिन्ता नहीं थी लेकिन जब जौहरी ने मुझे देखा और यह जानते हुए भी मुझे पैर से छुआ तो मैंने समझा कि हीरे की क़दर अब दुनिया में नहीं रही इसीलिये अपनी जान दे दी।

"जौ चेरी ऐड़ी दियो भई नहीं कुछ पीर,
जानि जौहरी पग दियो, फाटि गयो हियो हीर।"

इसलिये वह लोग यदि अच्छे काम में साथ न दें जो कि अपना कर्तव्य ऐश करने में समझते हैं तब तो कोई शिकायत नहीं किन्तु जब देशभक्त लोग देश के उत्थान में सहायक नहीं होते तो तकलीफ होती है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि चुनाव के समय दलबन्दी कर लीजिये किन्तु चुनाव समाप्त हो जाने के बाद राष्ट्र के उत्थान में एक साथ काम कीजिये।

मैं आपसे एक बात और अर्ज करता हूं और अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं। हम में ही कमजोरी है जो तुम्हारी टोपी लाल है। मुहब्बत होती तो यह नहीं होता। मुहब्बत से तो हिन्दू मुसलमान और मुसलमान हिन्दू हो जाता है। तब गैर कांग्रेसी भाई कांग्रेसी क्यों नहीं बन जाते ? सोशलिस्ट पार्टी को देखिये उन्होंने कृपलानी जी को अपना सभापति बना कर अपनी ओर मिला लिया। पार्टीबन्दी तोड़ने के लिये गांधी जी ने कांग्रेस की चार आना मेम्बरी भी छोड़ दी। रूस में भसकाया नाम की एक लड़की थी जो कम्युनिस्ट दल में थी और बहुत सुन्दरी थी। उस पर दल के दो नेता आसक्त हो गये। उसके कारण पार्टी में फूट पड़ने लगी। सवाल हुआ कि अगर वह एक के साथ शादी करेगी तो दूसरी पार्टी के लोग नाराज होंगे, फल स्वरूप पार्टी का काम खराब होगा। इसलिये उसने अपने चेहरे पर तेजाब डाल लिया। पूछने पर उसने कहा कि मेरा खूबसूरत चेहरा मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला था। इसलिए मैंने अपना चेहरा काला कर लिया। जब पार्टी के बचाने के लिये चेहरा काला किया जा सकता है तो आप भी अपने देश की गरीबी को दूर करने के लिये अपने मुल्क को मजबूत बनाने के लिये दलबन्दी से ऊपर उठ कर पंचवर्षीय योजना को पूरा करने में सहायक बन जाइये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बतलाऊं, चाहता था कि माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूं। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी का बधाई का बोझ इतना बढ़ गया है और वित्त मंत्री जी बहुत ही कमजोर हैं। अगर मैं भी उनको बधाई का बोझ देने लगूं तो शायद वह दब जायं। इसलिये कुछ कहना नहीं चाहता हूं। परन्तु फिर भी जैसा कि श्री परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि हमारी संस्कृति का तकाजा है कि मैं उनको बजट के लिये बधाई दूं इसलिये कि उन्होंने जो पारसाल का डैफोसिट बजट था उसे सरप्लस बजट में परिणत करके दिखाया।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

पारसाल वह कहते थे कि हमारा तो घाटे का बजट है, लेकिन जब हमने इस साल देखा कि वह घाटे का बजट सरप्लस में परिणत हो गया और करोड़ों की बचत हो गयी तो हमने कहा इस साल तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो गयी। पर उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख इस बात का है कि हर साल हमारा डेफिसिट बजट होता है, साल के अन्त तक वह सरप्लस हो जाता है। इसलिये नहीं कि हमारे सरकारी विभागों में कुछ रुपयों के खर्चे में कमी हुई हो, इसलिये नहीं कि जहां पर करोड़ों रुपया खर्च होता है वहां कम आदमी रख करके कम खर्च किया हो और उससे कमी हुई हो, बल्कि इसलिये होती है कि जितने भी हमारे देश के तरक्की के काम हैं, जितने डेवलपमेंट वर्क्स हैं वे सारे रोक दिये जाते हैं और रुपया बचाया जाता है, इस बजट को सरप्लस दिखाने के लिये या डेफिसिट को कम करने के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, मार्च के महीने में बजट पास होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर ९ महीने उसके बाद जनवरी में जितने नये एक्सपेंडीचर होते हैं, उनकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव कहिये या टेक्नीकल सेंक्शन हमारे पास पहुंचती है। जनवरी के महीने में कहा जाता है कि जो रुपया खर्च नहीं हुआ वह खर्च किया जाय। दो महीने में सारा रुपया खर्च करना होता है। अगर ग़लत खर्च किया जाय तो उसके लिये एकाउंटेंट जनरल है, फाइनेंस कमेटी है, पब्लिक एकाउंट्स कमेटी बैठी है, वह क्रिटिसाइज करेगी, लिहाजा वह खर्च ही नहीं किया जाता। नतीजा यह होता है कि डेवलपमेंट वर्क्स का रुपया बचत में आ जाता है। आखिर इस ८, ९ महीने के अन्दर सरकार क्या करती है, क्या बात है, क्या कारण है कि हमारे इस सदन से जो रुपया पास होता है उसे खर्च नहीं किया जाता है?

दो किस्म की सेविंग्ज होती हैं। एक तो जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम हैं उनमें बचत हो जाय और दूसरे यह कि जहां पर १० क्लर्कों से काम लिया जाता है वहां ८ से काम लेकर सौ रुपये में ५० रुपया खर्च किया जाय। लेकिन यह नहीं किया जाता। होता यह है कि तकावी लोन्स में ही रुपया बचा लिया जाता है। मैंने सदन में ही बतलाया था कि हमारे कुमायूं में ६ लाख रुपया कैनाल्स के लिये रखा गया था, वह रुपया हमारा खर्च नहीं हो पाया और यह महीना आखरी चल रहा है। हमें यह डर है कि अगर वह ठीक तरह से खर्च नहीं होगा तो लैप्स हो जायगा। हमारी पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट अगर पहले पेश हो गयी होती तो यहां पर बहुत सी टेक्नीकल बातें रखी जातीं जिनसे सरकार फायदा उठाती, लेकिन उसके लिए भी वक्त आ रहा है कि सरकार उससे फायदा उठाये। मैं बहुत ज्यादा इस समय टेक्नीकलिटीज में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे उसके लिये फिर मौका मिलेगा। मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी को बधाई देना चाहता हूं उनके आज के भाषण के लिये, इसलिए कि उन्होंने इनडेटेडनेस की बात कही, जैसा कि माननीय सुरेश प्रकाश जी ने भी कहा कि १ अरब, ९५ करोड़ का हमारा कर्जा है, इनडेटेडनेस है, हम कर्जदार हैं। वह कहते हैं कि इतने हमारे पास असेट्स पड़े हुए हैं, उनके होते हुए अगर हम कर्जदार हैं तो फिक्र की बात नहीं है। हमारे पास बिल्डिंग्स हैं तो कौन सी बड़ी भारी बात है? अगर किसी प्राइवेट इण्डिविजुअल का कर्जा हो तो कहा जा सकता है कि वह एक बिल्डिंग को बेच कर दूसरी बिल्डिंग का कर्जा वसूल कर लेगा, मगर माननीय परिपूर्णानन्द जी की क्या यह राय है कि इस बिल्डिंग को बेच दें उस कर्ज़े को पूरा करने के लिये? अगर यह राय है तो दूसरी बात है, नहीं तो यह कर्जा देना ही पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि कर्जा न किया जाय। डेवलपमेंट का जहां तक ताल्लुक है, मैं तो कहता हूं कि उसके लिये जो भी किया जाय उसके लिए तैयार हूं, लेकिन यह कहना कि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है इतना कर्जा

होते हुए, तो हो सकता है कि उनका यह ख्याल है कि अगर हम अपने असेट्स को ज्यादा दिखा देंगे तो गवर्नमेंट आफ इंडिया हमे जितना रुपया देती है उससे ज्यादा दे देगी, लेकिन कब तक? उसकी भी हद होनी चाहिये। वह भी तभी तक हमें सहायता देगी जब तक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। उन्होंने बहुत से आंकड़े भी दिये। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, मेरा तो निश्चित मत है कि सरकार के और परिपूर्णानन्द जी के सारे आंकड़े गलत हैं और मदनमोहन उपाध्याय के भी सब आंकड़े गलत हैं। आंकड़ों के झगड़े में मैं पड़ना नहीं चाहता। लेकिन इसकी भी मैं तारीफ करता हूं माननीय परिपूर्णानन्द जी की मेमोरी बहुत तेज है। ऐसे-ऐसे आंकड़े जबानी गिना देते हैं बगैर कागज से पढ़े हुए कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके लिये मैं उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा इस बात के लिये जो कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार के पास और बहुत काम हैं। अनइम्प्लायमेंट को दूर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को भी मौका देना चाहिए। उनका प्रस्ताव बड़ा सुन्दर है पर मैं उसमें एक संशोधन करना चाहता हूं। कहीं वह प्राइवेट सेक्टर का मतलब कैपिटलिस्ट सेक्टर न समझ लें। मैं उसमें यह संशोधन करना चाहता हूं कि वह कोआपरेटिव सेक्टर्स हों। सब लोग उसमें मिल कर कोआपरेटिव तरीकों से रुपया इकट्ठा करके उसको चलायें। अगर ऐसा हो जाय तो प्राइवेट सेक्टर्स को मौका देने का जो माननीय परिपूर्णानन्द जी का प्रस्ताव है मैं उसकी कद्र करता हूं पर मेरे इस संशोधन के साथ उस पर विचार किया जाय और मैं समझता हूं कि सरकार उस पर विचार करेगी।

मैंने मौरिसन साहब की स्पीच तो नहीं पढ़ी लेकिन मेरे लिये तो माननीय परिपूर्णानन्द जी का भाषण ही मौरिसन साहब के भाषण से कम नहीं है। माननीय लक्ष्मीरमण जी ने बहुत सी बातें कह डालीं, कहा कि साहब आपने कहां अपील कर दी, किससे अपील कर दी जो कि सुनते नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखीर में उस पर आना चाहता था पर जब अपील की बात आ गई है तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं पर अपील की आवश्यकता ही क्या थी? हमारे कारनामे बतायेंगे, हमारे काम बतायेंगे अगर हम अच्छा काम करेंगे तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि देश की भलाई न चाहती हो और भलाई के काम में हाथ न बटायेगी। क्या हमारे साथियों ने इस काम में हाथ नहीं बटाया, क्या हमने रचनात्मक कार्यों के अन्दर हाथ नहीं बटाया, अपने जिलों में रचनात्मक कार्य नहीं किया, क्या सोशलिस्ट पार्टी का जो कैनवोकेशन इलाहाबाद में हुआ था उसमें यह भाषण नहीं हुआ था कि भले ही हम पंचवर्षीय योजना से पूर्ण रूप से सहमत न हों लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको हम करेंगे और अगर सरकार खुद सही काम करेगी तो कोई भी ऐसा आदमी इस देश के अन्दर नहीं है जो यह कह सके यह काम गलत हो रहा है, इसे हमें नहीं करना चाहिये। हमने काम किया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जो काम हमने विकास के सम्बन्ध में किया है वह इसलिए नहीं कि हमने सरकार के ऊपर मेहरबानी की है। इसलिये किया है कि हम अपने देश को ऊंचा उठाने की कोशिश करना चाहते हैं। इसलिये हमने उन कामों को किया है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से पूंछना चाहता हूं कि वह यह बतावें कि उन्होंने क्या काम किया है? भाषण लोगों ने बहुत दे डाले। लक्ष्मीरमण जी ने न जाने कितनी बातें कह डालीं। उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि क्या जरूरत है इस तरह के भाषणों की, "मैं बधाई देता हूं," "मैं धन्यवाद देता हूं", क्या जरूरत है इस तरह की बातों को कह कर सदन का समय नष्ट करने की। मेरा यह विश्वास है कि इस प्रांत के जितने एम० एल० ए० यहां पर बैठे हुए हैं सबके जिलों की हालत खराब है, सबमें गरीबी है, सब के यहां दिक्कतें हैं लेकिन किसी ने आज नहीं कहा कि हमारे यहां दिक्कत है, सबने यही कहा कि हमारे यहां बड़ा आराम है, बड़ी

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

अच्छी हालत है, और सरकार को बधाई दी। मैं बदकिस्मती से यहां ऐसा हूं कि जो यह कह रहा हूं कि मेरे यहां गरीबी बहुत है। मैं कोशिश कर रहा हूं गरीबी को दूर करने के लिये और भलाई के काम में रुपया खर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यही कोशिश हर माननीय सदस्य करे तो बहुत कुछ लाभ प्रदेश का हो सकता है। लेकिन यह कह देना कि राजनारायण जी ने ऐसा विरोध किया और यह किया वह किया, टैक्स न लगाने के लिये कहा, इन सब बातों से कोई लाभ नहीं हो सकता।

लक्ष्मीरमण जी ने कहा कि हम कहते हैं कि बग़ैर टैक्स के काम करो, बग़ैर टैक्स के सरकार कैसे चलाई जा सकती है? कौन नहीं जानता कि बग़ैर टैक्स के सरकार नहीं चल सकती। मैं जानता हूं और सब जानते हैं कि सरकार दानखाते पर नहीं चलती है। बग़ैर रुपयों के काम नहीं चल सकता। पर इसके लिये और भी रास्ते हो सकते हैं। ढूंढ़े जा सकते हैं, जो करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है उस पर रोक लगाई जा सकती है। बहुत सी पालिसीज ऐसी हैं जिन्हें कि सरकार सिर्फ अपनी प्रैस्टिज को ऊंचा रखने के लिये चला रही है। प्राहीबीशन की ही बात लीजिये मैं चाहता हूं कि शराबबन्दी हो लेकिन जिस तरह से आज शराबबन्दी को चला रहे हैं ११ जिलों के अन्दर तो शराबबन्दी है और बाकी जगह खोल रखी है उससे तो कोई लाभ नहीं हो रहा है। वहां के लोग शराब भी पी रहे हैं। अगर यह सारे प्रान्त में शराबबन्दी होती तो उससे कुछ फायदा होता, लेकिन सारे प्रान्त में शराबबन्दी के न होने से एक गलत चीज हो रही है और हमारी रेवेन्यू भी कम हो रही है। और नतीजा यह हो रहा है कि हमारी प्राहिबिशन की स्कीम भी फेल रही है। हमने इस साल देखा कि एक्साइज ड्यूटी में कई लाख की कमी हुई है और खर्चा बढ़ गया है। मैं तो चाहूंगा कि सरकार झूंठी, प्रैस्टिज में न पड़े, उसको क्यों यह कहने में शर्म मालूम होती है कि उसकी प्राहिबिशन की पालिसी फेल हो गयी है। इसको खत्म करें और इससे जो आमदनी होगी उसको विकास के कार्यों पर खर्च करें। रोडवेज को ले लिया जाय। मैं साबित करूंगा कि रोडवेज की स्कीम बिल्कुल गलत है; अनप्राफिटेबिल है। इससे देश को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज नहीं तो पांच साल के बाद सरकार स्वीकार करेगी कि हमारी यह स्कीम गलत थी। यह कहना कि टैक्स के बिना गवर्नमेंट नहीं चल सकती मैं कहता हूं कि बहुत सी गवर्नमेंट की स्कीमें गलत चल रही हैं। उनको तोड़ कर रुपया बचाया जा सकता है।

मैं आशा करता था कि बजट में बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये कोई स्कीम होगी। सिर्फ एक लाख रुपया पढ़े लिखे बेकारों को जमीन देकर बसाने के लिये रखा गया है। एक तरफ क्लर्कों का रिट्रेंचमेंट किया जा रहा है और दूसरी तरफ नये-नये विभाग खोल कर उनमें नये-नये लोग रखे जा रहे हैं। इस तरह से क्या बेकारी की समस्या दूर होने वाली है। अभी तक कोई भी कदम सरकार की तरफ से बेकारी को दूर करने के लिये नहीं उठाया गया है जिसके लिये मुझे बड़ा दुःख है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं लेकिन कहीं यह न हो मेरे भाई मुझे ग़लत समझ लें। एक मिनिस्टर के पास सिर्फ ट्रान्सपोर्ट विभाग है। देश के किसी सूबे में ट्रांसपोर्ट विभाग अकेले एक मिनिस्टर के पास नहीं है। सेक्रेटेरिएट का एक अंडर सेक्रेटरी इस काम को चला लेता है। हमारे बहुत से डिप्टी मिनिस्टर भी शायद महसूस करते हों कि उनके पास भी कोई काम नहीं है। मुझे दुःख इस बात का है कि उनके बदकिस्मत स्टेनोग्राफर्स शायद कुछ दिनों में अपनी शार्टहैंड भी भूल जायंगे क्योंकि काम नहीं है। काम हो तो काम करें। मैं तो कहूंगा कि रीजनवाइज डिप्टी मिनिस्टर्स बांट दिये जायं। और एक-एक एरिया मिनिस्टर को सौंप दिया जाय,

क्योंकि ज्वाइंट रिस्पौंसिबिलिटी तो है ही और सरकारी अफसरों से और एम० एल० एज० से भी पूछा जाय कि उन्होंने अपने इलाके में कितना काम किया है। तभी वह डिप्टी मिनिस्टर साहब कुछ काम कर सकेंगे। नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी दिक्कत पड़ जाती है कि अगर एक सड़क बनवानी हुई तो ओवरसियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जिक्युटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर, और फिर चीफ मिनिस्टर और इसी तरीके के फिर उतरना पड़ेगा। इतनी परेशानी और मुसीबत होती है कि काम नहीं चल सकता है।

मैं माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को अवश्य धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी पानी की समस्या को हल करने के लिये उन्होंने पूरा प्रयत्न किया है। हमारे पहाड़ों पर पानी कैसे पहुंचाया जाय उसको हल करने में हमारे सिंचाई मंत्री ने हमारा साथ दिया है। यह हमारे पहाड़ी इलाके में कैनाल सिस्टम में क्रान्ति पैदा कर देगा। इसके लिये हम उनको धन्यवाद देते हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को फिर बधाई कहिये जो कुछ कहिए उनके अच्छे कामों के लिये देता हूं। और जो खराब काम इस बजट में रखे गये हैं उसके लिए मैं सरकार का न आज साथ दे सकता हूं और न आगे देने वाला हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपध्याय महोदय, मैं सर्व प्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि इन दो वर्षों के अन्दर यह मुझे प्रथम अवसर मिला कि बजट के जनरल डिबेट के अवसर पर मैं भाषण दे सकूं। मैं आज अपने विरोधी दल के साथियों को बतलाना चाहता हूं कि किस कंडीशन में हमने देश के शासन को अपने हाथों में लिया। सन् ४७ में जब देश की बागडोर हमारे हाथों में आई उस समय देश में नंगा नाच हो रहा था। भुखमरी फैली हुई थी। हिन्दू मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था और क्या-क्या बातें नहीं हो रही थीं। इन सब बातों का हमें सामना करना था। इस गवर्नमेंट ने बड़े मुश्किल के वक्तों में शासन को संभाला। मैं श्री सुरेश प्रकाश जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने सही बात कही।

मैं आपकी इजाजत से हाउस को यह बतलाऊंगा कि हमारे प्रान्त का असली नक्शा क्या है। मैं कोई धन्यवाद देने नहीं आया हूं, बल्कि सूबे की स्थिति पर कुछ प्रकाश डालने के लिये खड़ा हुआ हूं। सही मानी में आज जनता का राज्य है। हमारे विरोधी दल के सदस्यों ने कहा कि यह है, वह है, क्या नहीं कहा, लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और प्रेक्टिकल रूप में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे हैं। १६ करोड़ वोटर्स के वोटस् के साथ, अमनो अमान के साथ इलेक्शन जीत कर फिर हमने सूबे की बागडोर संभाली। जैसा श्री मदन मोहन उपाध्याय ने कहा कि वह कोआपरेट करने को तैयार हैं, कोआपरेट करेंगे तो देश का कल्याण होगा। आज दुनिया में क्या हो रहा है। सब लोग जानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान में मिलीटरी पेक्ट हुआ है, वह खतरे से खाली नहीं है। खाली रिजोल्यूशन पास करने से देश को नहीं बचा सकेंगे। हमें चाहिये कि हम लोग मिल कर कन्धे से कन्धा मिला कर काम करें और देश मजबूत बनायें तभी देश की रक्षा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं विरोधी दल को गालियां देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं निवेदन करता हूं कि ईमानदारी के साथ फेयर क्रिटिसिज्म किया जाय, उनके क्रिटिसिज्म को वेलकम करूंगा। हर गवर्नमेंट में स्ट्रांग अपोजीशन होना चाहिये लेकिन इस गवर्नमेंट का जो अपोजिशन है वह वीक है। मुझे इसका दुख है। आज अगर हमारे अपोजीशन के लीडर आचार्य नरेन्द्र देव होते तो वाकई इस गवर्नमेंट को पता चलता कि अपोजीशन लीडर बहुत बढ़िया है। मुझे दुख है कि आज इस मौके पर गेंदा सिंह जी और नारायण दत्त जी नहीं हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है और मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि जिस गन्ने की स्ट्राइक में

[श्री शिवनारायण]

उन्होंने हिस्सा लिया है हर मन गन्ने के ऊपर सवा चार सेर चीनी होती है, जिसकी कीमत ६० आने होती है और सरकार जो कीमत गन्ने की काश्तकार को दे रही है वह किसानों के लिये कम है। किसान ही इस सरकार की जान हैं और अगर सरकार ने उनकी पीठ पर हाथ नहीं रक्खा तो फिर सन् ५७ में जब किसानों के हाथ में पावर आयेगी उस वक्त क्या होगा, इस पर सरकार को विचार करना है।

आज हमारे प्रान्त में नमक की दिक्कत है। मेरे जिले में खास तौर से दिक्कत है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

मैं अपने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चकबन्दी का कानून १ अप्रैल को पास कर लिया और अपने जिले में जहां जाइये किसान डिमांड करते हैं कि चकबन्दी कानून कब आ रहा है। उनसे कहा जाता है कि हमने पास कर दिया है और आने ही वाला है। इस बजट स्पीच में कहा गया है कि २० जिलों में इस साल लागू कर दिया जायगा और प्रेसीडेंट की उसके लिये इजाजत भी शायद मिल गयी है।

जितनी बातें यहां कही जा रही हैं सरकार का कर्तव्य है कि उनको ध्यान में रक्खे और उन पर गौर करे। हमारा कर्तव्य तो यही है कि हम सही बातें सरकार के सामने रक्खें। जितनी दिक्कतें और मुसीबतें हैं उन्हें सरकार को बतलायें। किसानों की दशा आज शोचनीय है। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम सरकार के सामने सही नक्शा रक्खें। मैंने देखा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बातें हुईं। लड़कों ने तार काटे। विरोधी दल के लोग भी यहां उस दिन मौजूद थे। मैं गया और मैंने देखा कि किस तरह से विरोधी दल के लोग हमारे बच्चों को अपने पोलीटिकल गेम के लिये बिगाड़ रहे थे। अगर हमने एम० ए० पास किया होता तो हम और कहीं होते। आज सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने हरिजनों और मुसलमानों पर लांछन लगाया। हमारे भाई सीताराम जी ने मुसलमानों और हरिजनों के लिये कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि १० या १८ परसैन्ट जो है उसे तोड़ दीजिये। खोल दीजिये मैदान और जो फ़र्स्ट आवे उसे ले लीजिये। हम कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने के लिये तैयार हैं। हमने राणा प्रताप के साथ हल्दीघाट के मैदान में तलवार खींची है। हम किसी उच्च वर्ग वाले से नीचे नहीं हैं। अगर आप स्वर्ग में रहेंगे तो हम भी स्वर्ग में रहेंगे और आप नरक में हैं तो हम नरक में रहेंगे।

शिक्षा के लिये कहा गया कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द के जमाने में यह हुआ और वह हुआ। लेकिन आज हमारी गवर्नमेंट ने सैकड़ों टीचर्स के लिये डिमांड किया है गांवों के लिये। मेरी ही कांस्टीट्यूऐंसी में इसी लखनऊ युनिवर्सिटी का एक एम०एस०सी० कम्यूनिटी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है जो गलियों में खाक छान रहा है।

(इस समय ४ बज कर १३ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं एक बात माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि हमारे बस्ती जिले फ़र्जी इन्दराजात हैं जिनके लिये वह एक एडीशनल मैजिस्ट्रेट दे दें ताकि काम ठीक हो सके। २० हजार दरख्वास्तें पड़ी हैं और मैं आशा करता हूं कि इस पर विचार किया जायगा। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे बस्ती जिले में हास्पिटल बनाने का इन्तजाम किया और बांसीवाले पुल बन रहे हैं। लेकिन खलीलाबाद तहसील में दो जगह हैं। मुफ़लिसपुर और बालूसासन जहां बाढ़ से बहुत तबाही होती है, सरकार ने १० और १५ लाख बस्ती के कम्युनिटी प्रोजैक्ट के लिये दिया है। बाणगंगा का नया काम खोला जारहा है जिसकी हमारे सिंचाई मंत्री ने ओपनिंग सैरीमनी की और हमने उनका स्वागत किया। जो पैसा सरकार हमारे लिये खर्चेगी हम उसको जिन्दगी भर नहीं भूलेंगे।

पुलिस के लिये कहा गया। लेकिन पुलिस हमारे यहां कम है। हर थाने में १२ सिपाही हैं जो कम से कम डेढ़लाख आदमियों को देखते हैं और हथेली पर जान लेकर निकलते हैं। केवल पुलिस ही नहीं, जो रिश्वत देते हैं वे भी डिमोरेलाइजेशन के जिम्मेदार हैं। ब्रिटेन की मिसाल दी जाती है लेकिन वहां की और हिन्दोस्तान की पुलिस में क्या अन्तर है। अभी उनकी मोरेलिटी उनका स्टैंडर्ड आफ मोरेलिटी बहुत ऊंचा नहीं हुआ है लेकिन उनको सिर्फ गालियां देने से काम नहीं चल सकता। जरूरत इस बात की है कि उनको ट्रेन किया जाय, सही मानों में और सही ढंग से उनको चलाया जाय। जितने भी अफसर हैं ये सब गवर्नमेंट के नौकर हैं उनको भी यह बातें बतायी जायं। हम जानते हैं कि लोगों को उनसे शिकायत है लेकिन केवल शिकायतों से काम नहीं चल सकता। हमारे भाई बालेन्दु शाह जी ने कहा कि यह सरकार विदेशियों से गठबंधन करना चाहती है। अमेरिकनों के हाथ देश को बेचना चाहती है। इसका नमूना तो यहां देखने को मिल गया कि पाकिस्तान का अमेरिका से मिलिटरी पैक्ट हुआ लेकिन जवाहरलाल जी ने साफ फटकार बता दी। हमारे यहां अगर एक इंजीनियर है तो क्या हुआ हमारे यहां तो सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, चमार हैं, सभी लोग हैं उसी प्रकार से वे लोग भी हैं। पाकिस्तान में नये प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिये कितने ही आदमी गोलियों के शिकार हुए लेकिन हमारे यहां सही मानों में डैमोक्रेसी चल रही है इसीलिये तो लोग आज हमारी तरफ नजर लगाये हुए हैं। उसका सबूत कोरिया में हमारी फौजें अभी तक मौजूद हैं। अमरीका और रूस अपना झगड़ा मिटाना चाहते थे तो हम माध्यम हुए हैं।

हमारे भाई लोग सिंचाई के लिये कह रहे हैं। सिंचाई तो सब जगह साफ दिखाई पड़ती है, पंचवर्षीय योजना का नमूना हमारे सामने है जहां देखिये ट्यूब वेल्स खड़े दिखायी देते हैं। किसानों को उनसे पानी मिल रहा है। भागीरथ ने जब तपस्या की थी तो गंगा जी वह लाये थे किन्तु हमारे कमलापति जी ने तपस्या की तो वे पाताल तोड़ कर पानी ले आये और सैकड़ों ट्यूबवेल्स लगवा दिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान स्वास्थ्य विभाग की ओर भी दिलाना चाहता हूं। स्वास्थ्य विभाग के जरिये बहुत काम हो रहा है। हमारे यहां घेघे की बहुत बीमारी है उसका और अच्छा प्रबंध होना चाहिये तथा वहां पर डाक्टरों और कंपाउंडरों के रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिये। आशा है सरकार इस ओर अवश्य ध्यान दे रही होगी।

इसके बाद मैं सड़क विभाग की तरफ नजर डालना चाहता हूं। मैं लुंबनी पवित्र स्थान को देखकर आया हूं। वहां के इंचार्ज को मैंने कहा था कि मैं उनका मैसेज सरकार को कनवे करूंगा। वहा पर बाहर से बहुत से विदेशी आते हैं। वहा की सड़क की हालत बहुत खराब है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह वहां के लिये एक सुन्दर सड़क बनवा दे ताकि हमारी इज्जत चमकती रहे। अन्त में मैं पुनः अपने अर्थ मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि जिन्होंने ११ करोड़ के बजाय ८१ करोड़ का बजट पेश करके इस प्रान्त को कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश की है लेकिन फिर विरोधी दल खुश नहीं हो रहा है। सन् ५७ में अगर कोई झोपड़ी भी बनवा देता था तो फख्र से कहता था कि यह फाईनेंस मिनिस्टर ने बनवाई है, हम यह काम कर रहे हैं। बढ़ते चलो बहादुरों, बढ़ते चलो बहादुरो, यह समय है जब कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा प्रान्त और हम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह से हमारा आगे मार्च होता रहे, यही हमारी मनोकामना है।

श्री नरदेव शास्त्री—(जिला देहरादून)—अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल तथा इधर के वक्ताओं के भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुने। अब मैं यह अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा इतना बड़ा प्रदेश है उसमें जिस गंभीरता से विचार होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है और बीच

[श्री नरदेव शास्त्री]

बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जिनसे सदन का समय व्यर्थ नष्ट होता है और एक विषय पर भलीभांति विचार नहीं हो पाता। राज्य चक्र को ७ विभागों में बांटा जा सकता है, यथा—राजा, प्रजा मंत्रिमंडल, कोष, बल, गुप्तचर और सुहृद। इन सात बातों से राज चक्र चलता है। इस बजट का संबंध कोष से है इसलिये इसी पर अधिक विचार करना पड़ता है। जिस राज्य का कोष क्षीण होगा वह राज्य दुर्बल होगा और जिस राज्य का कोष अधिक होगा वह राज्य सबल होगा। इसलिये इस बजट को देखने से मालूम होता है कि हमारे प्रदेश का बजट प्रति वर्ष बढ़ता ही चला जाता है। वह बजट तभी सफल हो सकता है जब कि उसकी प्रजा के लिये उसका सदुपयोग हो। शायद मैं पहला ही पंडित शास्त्री हूं जो इस प्रश्न पर बोल रहा हूं। हमारे शास्त्र के अनुसार कहा गया है राजा अच्छा वही है जो प्रजा की आमदनी का एक चौथाई हिस्सा ले, एक मत तो यह है। एक दूसरा मत धर्मशास्त्र के अनुसार यह है कि राजा १/६ हिस्सा ले सकता है और कर भी लगा सकता है। "सहस्यगुणत्सष्टु—मादत्ते हि रसं रविः" सूर्य किरणें पानी को रोज खींचता है किन्तु इसलिये खींचता है कि वह हजार गुणा देवे। राजा टैक्स लगा सकता है और उस टैक्स को लगा कर यदि वह प्रजा को बहुत भारी लाभ पहुंचता है तो वह टैक्स भी ठीक है चाणक्य ने कहा है "सर्वेभ्यः कोषेभ्यः प्रकृतिकोपो बलीयान्" यानी सारे संसार में जितने कोप हैं उनमें प्रकृति का कोप, प्रजा का कोप बड़ा बलवान है। प्रजा के कोप की तुलना किसी से नहीं हो सकती है। इसलिये बजट को बनाते समय, और बजट का ठीक संचालन करते समय, टैक्स लगाते समय, शासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्रजा का नहीं कोप कहो जाय। आज जो इतनी बड़ी बड़ी योजनायें हो रही हैं उनके लिये मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि कहा गया है "साहसे श्री प्रतिवसति" अर्थात् साहस ही में श्री का बास होता है लेकिन वह साहस ऐसा नहीं होना चाहिये जो दुस्साहस ही हो जाय। जहां तक व्यापार की बात है सरकार को हर व्यापार को अपने हाथ में नहीं ले लेना चाहिये। अगर हर व्यापार को सरकार अपने पास ही रखे तो प्रजा के पास पैसा कहां रहेगा और आप टैक्स कहां से वसूल करेंगे। मैं कहता हूं कि जो परिवहन विभाग है इसको अपने पास रखने की क्या आवश्यकता है। प्रजा को ही मोटर आदि चलाने देते। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट जो है उसमें दृष्टि भेद भी है। एक बार मैं एक राजा के महल में गया तो मैंने वहां एक चित्र देखा तो मैंने समझा कि वह सिंह का चित्र है और आगे चला कोने में देखा तो मालूम हुआ कि यह ऊंट का चित्र है और जब दूसरी तरफ जाकर देखा तो मालूम हुआ कि यह व्याघ्र का चित्र है। अर्थात् एक ही चित्र स्थान बदलने से तीन प्रकार का दिखाई दिया। मैं बतलाना चाहता हूं कि उसी प्रकार से यह बजट है जो उधर बैठने वालों को और तरह से दिखलाई देता है, और इधर बैठने वालों को और तरह से दिखलाई देता है और बाहर वालों को और तरह से दिखलाई देता है। इसलिये स्थान भेद से दृष्टि भेद होता है। जो विरोधी हैं वे बिलकुल उसी बात पर तुले हैं कि वे सरकार की एक बात की भी प्रशंसा नहीं करते हैं। यह देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इधर वालों को जब सरकार का कोई दोष भी दिखलाई देता है तो भी वे मेज पीटते हैं।

अब मैं इस बजट को संतुलित दृष्टि से, एक समालोचक की दृष्टि से देखना चाहता हूं। जहां तक शिक्षा का संबंध है चाणक्य के कहा है "सुखस्य मूलम्: धर्मः, धर्मस्य मूलम् अर्थः अर्थस्य मूलम् राज्यम्, राजस्य मूलम् विनयः"। तो जिस राज्य में सही शिक्षा होगी उस राज्य नैतिक स्तर ऊंचा हो सकता है। मेरा तो कहना यह है कि जितनी सैकड़ों योजनायें हैं उनको छोड़कर पहले आप अपने लड़कों को ही ठीक करें तो मेरे ख्याल में हमारा राज्य बहुत ऊंचा उठ सकता है। आज कल जिस तरह की शिक्षा दी जाती है उसको तो सभी लोग जानते ही हैं। उससे हमारा नैतिक स्तर कभी ऊंचा नहीं उठ सकता है। मैंने आपको बतलाया था कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सारे कोपों से प्रकृति का कोप बलवान है तो आज हमें यह देखना है कि आज प्रजा के अन्दर इतना असंतोष क्यों बढ़ता जा रहा है। वे किसान जिनके लिये

जमींदारी का विनाश किया गया व नाना प्रकार से उनको सहायता पहुंचायी गयी वे भी किसान आज असंतुष्ट क्यों नहीं होते जा रहे ह, मजदूर क्यों असंतुष्ट होते जा रहे हैं। तो यह प्रकृति का जो कोप है उसका ध्यान रखते हुए मैं जब इस बात पर विचार करता हूं तब इस परिणाम पर पहुंचता कि यह अनएकनामिक बजट है। हमारे भारतीय अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राजा को चाहिये कि आय और व्यय को देखकर ही व्यय करे और आय की अपेक्षा व्यय अधिक नहीं करना चाहिए और संतुलन रखना चाहिये। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो व्यय बढ़ता जाता है तो किस तरह से काम होगा। ऋण भी ले सकते हैं लेकिन उनके लिये भी सुहृद् होना चाहिये उसके कितने मित्र हैं यह भी देखना चाहिये और उनसे वक्त पड़ने पर सहायता भी ले सकते हैं। जैसे आज अमेरिका से सहायता लेते हैं लेकिन अन्य बातों में मना भी कर देते हैं। लेकिन लेते हैं प्रोजेक्टों के लिये तो इन प्रोजेक्टों से कुछ होने वाला नहीं है।

इस तरह से मैं कह रहा था कि हमारी एजूकेशन ठीक ठीक नहीं चल रही है। कमीशन बैठ रहा है और उपाय निकाले जा रहे हैं कि क्या किया जाय लेकिन यह सत्य है कि आज भारतीय ढंग से एजुकेशन नहीं हो रही है।

इसी तरह से चिकित्सा के संबंध में कह सकते हैं। मैं प्रायः स्कूलों में पूछता हूं। यह बी० सी० जी० की बला अच्छी पीछे लगी है। लाखों रुपया इंग्लैण्ड जाता है और वहां से इंजेक्शन बनकर आते हैं और हमारे बच्चों को हैरान किया जा रहा है। बहुत कष्ट होता है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार "यस्य देशस्य यो जन्मी, तज्जं तस्यौषधं सितम्" अर्थात् जिस देश में जो उत्पन्न होता है उस देश की औषधि ही उसके दुखों को दूर कर सकती है। इस संबंध में मैं एक बहुत सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गूजर महाशय थे। वे बीमार हो गये और उनको आधा शीशी का दर्द रहने लगा। कम से कम कोई उपाय जब नहीं चला तो कलकत्ते से कविराज गणनाथ सेन को बुलाया गया। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया और वह आयुर्वेद के महापंडित थे। उन्होंने भी महीनों तक इलाज किया और अच्छा नहीं हुआ। तीस हजार रुपये गणनाथ सेन पर खर्च हो गये तब लोगों ने कहा कि यह आयुर्वेद कैसा सड़ियल आयुर्वेद है कि आधाशीशी का दर्द अच्छा नहीं कर सकता। एक वृद्ध गूजर वहीं से निकले तो उन्होंने पूछा कि लोग यहां इकट्ठे क्यों हो रहे हैं। तो लोग कहने लगे कि हुजूर हैं सरकार के आधाशीशी का दर्द है। अच्छा नहीं होता। उसने कहा हमारे साथ आओ। और वहां उसने खेत से बाजरे की जड़ उखाड़ कर दे दी और कहा कि इसको ले जाकर गोलमिर्च के साथ पीस कर पिलाओ। और ८ रोज पिलाने के साथ ही वह अच्छा हो गया। जो शिर दर्द कविराज गणनाथ सेन के इलाज से ठीक नहीं हुआ वह बुढे गूजर के इलाज से ८ दिन में ठीक हो गया। गूजर ने कहा कि गूजर का दिमाग देखना चाहिये था। यह शीशी और बोतलों पर लेबिल लगाने वाले लोगों में वह दिमाग कहां है। हमको भारतवर्ष का दिमाग देखना चाहिये कि किन दवाओं से आराम होगा। तो हमने कहा कि भारतीय औषधालय खोलो, चिकित्सालय खोलो, भारत में ऐसी-ऐसी जड़ी-बूटियां हैं जिनका गुण प्रत्यक्ष है। हमारे गुरु एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल के फेलों थे वह एक दफा बीमार हो गये थे। जांघ में एक फोड़ा हो गया था उन्होंने कहा कि फलाने कविराज को बुलाओ वहां कविराज हर एक को कहा जाता है जो दवा बेचता है। तो वह जब आये तो मैंने कहा कि गुरूजी को दवा दो। उन्होंने पूछा कि इसको दबा दिया जाय या फोड़ दिया जाय। यह निश्चित हुआ कि ८० साल के बूढ़े हैं फोड़े को दबा दिया जाय तो अच्छा है। उन्होंने एक पत्ता दिया और कहा कि सीधा बांधोगे तो दब जायगा और उलटा बांधोगे तो फूट जायगा। मैंने स्वयं देखा। सीधा बांधा गया और आठ दिन के अन्दर उस फोड़े का पता भी न नहीं लगा।

तो शिक्षा के विषय में हमने कहा, चिकित्सा के विषय में हमने यह बताया। अब रहा टैक्स। बेशक टैक्स लगा सकते हैं। यदि हजार गुना प्रजा को मिले तो यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष टैक्स नहीं लगाया। लेकिन जो पहले बहुत सारे लग

[श्री नरदेव शास्त्री]

गये उनका क्या है ? तो अब यह तो टैक्स लग रहे हैं उनको देखना चाहिये। मैं बहुत गम्भीर भाव से विचार कर रहा हूं। गुण को गुण कहना चाहिये और दोष को दोष। लेकिन गुण को दोष और दोष को गुण कहना यह समालोचक दृष्टि नहीं है। मैं तो प्राचीन ढंग का जानने वाला हूं और प्राचीन ढंग से बोलता हूं। बहुत सी बातों का तो मुझे पता भी नहीं लगता कि क्या कहते हैं। इंगलैंड की जो बात हो उसे इंगलैन्ड की पोलिटिकल एकोनामी चलाये और जो हमारे देश की बातें हैं उन्हें हमारे देश की पोलिटिकल एकोनामी चलावे। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे और विचार करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हम कहां हैं और हमको किस प्रकार से चलना चाहिये। यह कोई नयी बात नहीं है कि हम यहां आज इस तरह से बैठे हुए हैं, जब स्वराज्य नहीं आया था तब भी हमारी राजनीति चलती थी, तब भी हमारा साम्राज्य चलता था, उस वक्त भी कमेटियां होती थीं और सलाह से काम किया जाता था। हमारे नेताओं ने अंग्रेजों से जो प्रजातंत्र सीखा उसीको उनके मुंह पर मार दिया। किन्तु अब हमें यह सोचना चाहिये कि उस प्रजातंत्र में हमें किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिये और उसे भारत के वातावरण के अनुरूप लाना चाहिये। तभी जाकर के कहीं हमारा काम होगा। मुझे यही कहना है।

सदन की बैठक के समय में वृद्धि

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत से लोग बोलने वाले हैं और कल चार ही घंटा वाद-विवाद हुआ था इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है आज सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

१९५४–५५ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

***श्री केशव गुप्त**–(जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं १९५४–५५ ई० के बजट के लिये अपने माननीय वित्त मंत्री जी को इस लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये तथा उत्तर प्रदेश की माली हालत को सुधारने के लिये करोड़ों रुपया बजट में रखते हुए भी किसी नये टैक्स या कर का एलान नहीं किया है। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने भाषण में आशा की एक झलक यह भी दी कि अगर संभव हो सका तो सेल्स टैक्स के बोझ को भी कुछ हल्का करने की कोशिश करेंगे। अभी कल विरोधी दल के नेता ने बजट की बड़ी आलोचना की और उसी के साथ ही साथ कर के बोझ और कर की नीति की भी आलोचना की। परन्तु इस आलोचना के होते हुए भी वे यह अवश्य मानते हैं कि किसी भी प्रजातंत्रीय प्रणाली को चलाने के लिये जैसी कि वर्तमान परिस्थितियां हैं, सभी देशों में कर लगाने की आवश्यकता होती है और कर से ही उनका काम चलता है। हां, यह बात अवश्य उस कर के लगाने में देखी जाती है कि उस का बोझ समान रूप से सब पर पड़ता है या नहीं, जहां उसको जितना पड़ना चाहिये वहां उतना पड़ रहा है या नहीं। सही प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है या नहीं और वह सही प्रकार से जनता तक पहुंचता है या नहीं। इस उद्देश्य से अगर आप इस बजट के अकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो टैक्स की नीति इस सरकार की रही है और है वह बिल्कुल उचित है और उसका बोझा बहुत ही कम, चाहे आप दूसरे प्रांतों को लें या आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लें, या आप दूसरे मुल्कों के बजट को देखें, हमारी आमदनी के आंकड़ों को सामने रखते हुए, हमारी सूबे की जनता पर पड़ता है। अगर आप इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बजट के आंकड़ों को देखें और मालूम करने की कोशिश करें तो आपको मालूम होगा कि ऐसी बहुत ही कम मदें हैं जिनको डाइरेक्ट टैक्जेशन कहा जा सकता है। मैंने इसका अन्दाजा लगाया तो सिर्फ ३८ करोड़ के ऐसा रुपया आता है जिसको कि हम टैक्जेशन कह सकते हैं। बाकी जितना रुपया है वह या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इमदाद है—१६, १७ करोड़ के करीब या कुछ ऐसी मदें हैं जिन में व्यापारिक धंधों से हमें कुछ आय प्राप्त होती है। तो ३८ करोड़ रुपया असली टैक्स के रूप में कहा जा सकता है। जो नहर के आंकड़े हैं उनको मैंने कर में शामिल नहीं किया, क्योंकि वह भी सरकार की एक व्यापार नीति के अन्तर्गत आता है। वह पानी का पैसा है, सरकार पानी देती है और उसकी कीमत वसूल करती है। इसलिये मैंने उन आंकड़ों को उससे बाहर रखा है। अब इस ३८ करोड़ के बजट को देखते हुए मैंने यह भी देखने की कोशिश की कि जो जनता की भलाई के काम हैं उनमें कितना रुपया सरकार सीधे जनता के पास पहुंचा देती है। गांव सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐग्रीकल्चर, वेटरिनरी, कालोनाइजेशन, कोआपरेशन, इंडस्ट्रीज, लेबर शेड्यूल्ड कास्ट और प्लॉनिंग इन आठ–नौ विभागों के ऊपर जो खर्च होता है उसको जब मैंने जोड़ा तो उसकी तादाद २५ करोड़ ६८ लाख के लगभग आयी। इसके अलावा सिविल वर्क्स पर जो खर्च होता है उसकी भी तादाद करीब ५ करोड़ ६२ लाख आती है। इस तरह ३८ करोड़ में से करीब ३० करोड़ रुपया सीधे हमारी जनता के पास पहुंच जाता है। बाकी कुछ रुपया जो व्यापार की मदें हैं, जैसे ट्रांस्पोर्ट में जो आमदनी होती है उस आमदनी को करने में खर्च करना पड़ता है या जंगलात की आमदनी करने में कुछ खर्च करना पड़ता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जितना रुपया टैक्स के रूप में सरकार लेती है, वह करीब करीब सब का सब सीधे जनता के पास पहुंच जाता है और उसका उसको लाभ पहुंचता है और उससे अपने प्रदेश की उन्नति होती है। तो इस तरह से मैं अपने भाई राजनारायण जी को शायद यह बताने में सफल हूंगा कि हमारी जो सरकार की टैक्स की वर्तमान नीति है, उसको जैसा कि एक प्रजातंत्र में चलता है, देखें और चाहें पूर्वी चाहे पश्चिमी अर्थशास्त्रियों की नीति से देखें, तो आप को पता चलेगा कि हमारी टैक्स की नीति सही है और हमारा टक्स का बोझा सब से कम है। आज जो हमारी टैक्स की नीति है वह लिबिरल है, उदार है, क्योंकि इस प्रकार यदि हम ३८ करोड़ को ६ करोड़ ३६ लाख की आबादी पर बांटें तो करीब सवा छः रुपया टैक्स का पर हेड पड़ता है जबकि बम्बई या मद्रास में ११, ११, १२, १२ और इससे भी अधिक पड़ता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि हमारी टैक्स की नीति सही है। लेकिन साथ में मैं जब आंकड़ों को देख रहा था तो यह भी मुझे पता चला कि कुछ ऐसी भी व्यापार की मदें हैं जिन में हमारी आमदनी कम होती जा रही है और खर्चा बढ़ता जाता है। मिसाल के तौर पर एक्साइज में हमारी आमदनी कम हुई, लेकिन खर्चा बढ़ा। ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में हमारी आमदनी कम हुई, लेकिन खर्चा बढ़ा। ट्यूबवेल्स में हमारी आमदनी कम होती जा रही है लेकिन खर्चा बढ़ता जाता है। इंटरटेनमेंट टैक्स और वेटिंग टैक्स हमारा खर्चा हर साल बढ़ता जाता है। इसलिये यह सोचने की जरूरत है कि जो आमदनी की मदें हैं और जिनमें आमदनी कम होती जाती है, उनपर खर्चा भी घटाने की जरूरत है इसी तरह से सरकार अगर सतर्क रहे तो बहुत से खर्चे घट सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सब विभागों में मोटर वेहिकिल्स पर बहुत सा रुपया खर्च होता है। आज यह मानी हुई बात है कि जिन मुहकमों का इंसपेक्शन होता था, वह इंसपेक्शन हमारा अब पहले के मुकाबिले में बहुत ढीला हो गया है बावजूद इसके कि हमने बहुत ही सुविधा मोटर वेहिकिल्स की दे दी है। अगर हम इन वेहिकिल्स के खर्चे की तादाद को जोड़ें, तो वह करोड़ों में आता है। इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि अगर किसी तरह यह खर्चा घटाया जा सकता है तो वह इसको घटाने की कोशिश करे।

मुझे और भी कुछ चीजें देखने को मिलीं, जैसे आप ने स्टेनोज को हटाने की बात कही कि हम कुछ मशीनें मंगा रहे हैं और आपने सप्लीमेंट्री बजट में उसको रखा। इस बजट में भी आप ने कुछ ऐसी मशीनों के खरीदने की व्यवस्था की है।

[श्री केशवगुप्त]

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अन्दर जहां इतनी बेकारी है वहां पर इस प्रकार की मशीनें मंगाना जो कि बेकारी को बढ़ाने वाली हों किसी हालत में भी अच्छा नहीं है। उसमें हमारा रुपया बाहर को जाता है और हमारे लोग बेकार होते हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि मैं माल विभाग की इस नीति को पसन्द करता हूं कि वह लोगों को कुएं बनाने के लिये तकावी दे लेकिन ट्रैक्टर मंगाने के लिये भी उनको तकावी दे यह बात मेरी समझ में नहीं आती। ट्रैक्टर्स मंगाने से देश का रुपया बाहर को चला जाता है और बेकारी बढ़ती है, क्योंकि जब एक ट्रैक्टर आ जाता है तो ५ या १० मजदूर हमारे ग्राम के जो उस काश्तकार के पास काम करते थे वे खाली हो जाते हैं और इस देश में जहां कि आदमियों की संख्या ज्यादा हो वहां पर इस प्रकार की व्यवस्थायें करना जिससे कि बेकारी बढ़े, मैं समझता हूं कि यह नीति अच्छी नहीं है।

इसके साथ ही एक बात हमारे गुरु पंडित नरदेव शास्त्री जी ने भी आपके सामने रखी और परिपूर्णानन्द जी ने भी आपके सामने रखी कि हम प्रायः ऐसा करते चले जाते हैं कि बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स के जो व्यापार थे वे भी अपने हाथ में लेते जा रहे हैं। मैं भी इस बात का मानने वाला था कि वास्तव में प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज रहनी नहीं चाहिये, वह तो सरकार के हाथ में आनी चाहिये, लेकिन मैं मिक्स्ड एकोनामी का मानने वाला नहीं हूं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था जब जमींदारी आप खत्म कर रहे थे कि जहां जमींदारी आप खत्म कर रहे हैं वहां इस बात की आवश्यकता है कि जो लोग बेकार हो गये उनका भी आप प्रबन्ध करें। इसलिये मेरा फिर कहना है कि जितने व्यापार आपके हाथ में हैं उनमें आपको घाटा होता जाता है, जितनी आपकी डेरीज हैं वे नुकसान में चल रही हैं, जितने स्टेट फार्म्स हैं वे भी करीब-करीब नुकसान पर ही चल रहे हैं और आपकी जो केसा की आमदनी है वह भी पहले के मुकाबिले में परसेंटेज आफ प्राफिट कम है। इसलिये मुझे आपसे यह प्रार्थना करनी है कि जब तक आपने इस प्रणाली का सहारा ले रखा है उस समय तक प्राइवेट सेक्टर के कम करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्राइवेट आदमी कार्य कर रहे हैं वह उनको करने दीजिये। हां, अगर आप दूसरी प्रणाली को अपनायें और इस प्रणाली को छोड़ दें, नेशनलाइजेशन की प्रणाली को अपनाना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और वह सौभाग्य का दिन होगा जब आप ऐसी प्रणाली को अपनायेंगे। मैं आपसे बताऊं कि बावजूद इसके कि हम पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, प्रदेश को समृद्धशाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी भुखमरी बेकारी, इनसिक्योरिटी आफ लाइफ बराबर बढ़ती जाती है और खरगोश की चाल से तेजी से चल रही है और हमारे जितने साधन हैं वे चींटी की चाल से चल रहे हैं। पंडित नरदेव शास्त्री जी ने ठीक ही कहा कि हालत एक दूसरी सी मालूम होती है। इसलिये मुझे आपके द्वारा यह प्रार्थना करनी है कि आपने अमरीका में भी देखा था कि रूजवेल्ट ने भी इस बात की कोशिश की कि वह अपने देश के अन्दर समृद्धि लाये। उसने भी प्रजातंत्र प्रणाली के अन्दर अपने देश को सम्हालने के लिये नये नये ढंग निकाले, लेकिन बावजूद इसके कि आप देखते हैं कि तमाम संसार का २/५ धन अमरीका में है, वहां के लोगों की जो ऐवरेज इन्कम है वह भी दूसरे देशों से ज्यादा है आज उनको नींद नहीं आती है और वे जागते रहते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य को काला देखते हैं, आज भी उनके यहां गरीबी है, भुखमरी है। यह कहना कि अमरीका में हर एक आदमी खुश है, गलत है। इसलिये मेरा कहना तो यह है कि जिस आर्थिक प्रणाली का हमने सहारा ले रखा है वह हमारा ज्यादा

भला करने वाली नहीं, हमारे भविष्य की आने वाली क्रान्ति को कुछ रोज के लिए शायद वह रोक ले लेकिन वह ज्यादा दिन तक काम करने नहीं जा रही है। हमें जरूरत इस बात की है कि हमारी आर्थिक प्रणाली के अन्दर मौलिक क्रान्तिकारी तब्दीली हो। उसको हम नये सिरे से देखें? हममें खतरा लेने की भावना पैदा हो। हम सोर्स आफ डिनैमिक से और पिछले तजुर्बों को देख कर जनतंत्र प्रणाली में रह कर, अपनी आर्थिक प्रणाली के अन्दर ऐसी क्रान्तिकारी तब्दीली करें जिससे असमानता और विषमता जो हमारे देश में फैली हुई है वह दूर हो और देश के लोग खुशहाल हों और बटवारा भी ठीक हो और हमारा देश आगे बढ़ सके। यही मैं आपसे चाहता हूं और इस ओर संकेत भी हो चुका है कि हम आर्थिक पद्धति के अन्दर मौलिक परिवर्तन करें और पुरानी परिपाटी में तब्दीली करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दो रोज से इस बजट पर सामान्य विवाद जारी है और कुछ माननीय सदस्यों ने इसको जन कल्याण राज्य का बजट बतलाया है और कुछ ने दूसरी तरह का बतलाया है। मैं इस संबंध में विशेष चर्चा नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ एक दो बात ही कह देना चाहता हूं। यह बजट कल्याणकारी राज्य का है अथवा पलिस राज्य का है या नौकर शाही राज्य का है, इस सम्बन्ध में सैकड़ों और हजारों जमादारों एवं चपरासियों से जो यहां हैं उनसे पूछा जाय कि यह कल्याणकारी राज्य का बजट है, प्रदेश में रहने वाले हजारों की तादाद में प्रारम्भिक और जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों से पूछा जाय कि यह बजट कल्याणकारी राज्य का है, २४ हजार पटवारियों से जो पारसाल बेगुनाह निष्कासित कर दिये गये हैं जिनके पीछे उनके बीबी-बच्चे आज भी दाने दाने के लिये मोहताज हैं, उनसे पूछा जाय। इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में करोड़ों की तादाद में खास तौर से हरिजन जो दिन रात चैत के महीने में भी गोबरहा खाकर अपनी जिन्दगी बिताते हैं, उनसे पूछा जाय कि यह बजट कैसा है। अन्त में श्रीमन्, यही उत्तर मिलेगा कि यह बजट पुलिस और नौकरशाही राज्य का बजट है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन दिन से बजट के पन्ने-पन्ने को पढ़ा है और वित्त मंत्री जी के भाषण तथा अन्य सरकारी सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस बजट में आज भी वही पुराना तरीका है जो लगातार वर्षों से चला आ रहा है। इस बजट से उन लोगों को कोई नई जिन्दगी और नई प्रेरणा नहीं मिल रही है, जो कि तरह तरह से परेशान और पददलित हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सरकारी पक्ष के लोगों ने कुछ मेरे दोस्तों की आलोचनायें की हैं, उनका उत्तर मैं बाद में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले मैं बजट के ऊपर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। इस बजट में अध्यक्ष महोदय राजभवन पर २५ हजार रुपये का नया खर्चा रखा गया है और उनमें से नये परदों के लगाने में ५ हजार रुपया खर्च किया जायेगा जो आज तक नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त ५ हजार रुपया राज्यपाल के मनोरंजन के लिये रखा गया है। एक लाख २० हजार रुपया यात्रा व्यय के मद में है। चालू वर्ष में राज्यपाल का खर्चा कम रखा गया है लेकिन ५१–५२ के बजट में बढ़ोत्तरी हुई है।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, राज्य के सचिवालय पर ६८ लाख रुपया खर्च करने के लिये रखा गया है जब कि चालू साल में ६१ लाख हुआ है। इसके अतिरिक्त लोक-तंत्र पर जिसमें कि हम लोग बैठे हुये हैं यानी माननीय मंत्री और उप-मंत्री इन सब पर साढ़े पचास लाख रुपया खर्च रखा गया है विधान सभा में ५० हजार

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

रुपये की कमी हुई है। लेकिन विधान परिषद् में उतने ही की बढ़ोत्तरी हुई है। मंत्रियों, उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों पर ६ लाख १९ हजार रुपया खर्च करने के लिये रखा गया है। इस प्रकार इतना खर्च करके गांधी जी के आदेशों की उपेक्षा की जा रही है।

दुर्भिक्ष अनुदान में बहुत ही कम रुपया रखा गया, इस पर कहा जाता है कि बाढ़-पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिये काफी रुपया रखा गया है। बिहार हमारे प्रदेश के नजदीक में है और उसकी आमदनी बहुत कम है। पिछले साल जब कि उसका ५० करोड़ रुपये का बजट था तो वहां की सरकार ने ३ करोड़ ६० लाख रुपया बाढ़-पीड़ितों पर खर्च किया था। हमारे यहां का चालू वर्ष का बजट ७८ करोड़ रुपये का है जिसमें से केवल ९ लाख रुपया खर्च किया गया है। बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में जहां इतनी विप्लवकारी बाढ़ आई थी कि सब लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे और लोगों ने कहा कि ऐसी बाढ़ तो इस प्रदेश में कभी नहीं आई थी। हमने बहुत ध्यान से इस बजट को देखा है। इसमें कहा गया है कि १,१५ हजार रुपया टिड्डी नाश के लिए खर्च किया जायगा और २ लाख ६० हजार रुपये इसी काम के लिये केन्द्रीय सरकार को दिया जायगा। एक लाख रुपया नावों, गैस और तम्बू में खर्च किया जायगा। ५ लाख रुपया अनुदान संख्या ३३ बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों की सड़कों एवं इमारतों की मरम्मत करने के लिये जिला बोर्डों को दिया गया है। दो-तीन नई मदें इसमें रखी गयी हैं। उनमें से एक १० मोटर बोटों के लिए है। सारे प्रान्त में जहां जहां बाढ़ें आती हैं और प्रत्येक नदियों के किनारे बसे हुए जितने जिले हैं वहां केवल ५ मोटर बोटे रहेंगी। आजमगढ़, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, देवरिया और बलिया इतने जिले हैं जो घाघरा नदी के किनारे पड़ते हैं। इन सभी जिलों के लिए केवल एक मोटर बोट रहेगा। बजट में जो मोटर बोटों की व्यवस्था की गई है उसके अनुसार इन पांचों जिलों में केवल एक मोटर बोट आयेगी। १० देशी नावें हर जिले में रखी जायंगी और प्रत्येक गांव सभा को अधिकार दिया गया है कि वह नावें बना सकती हैं, लेकिन सरकार केवल आधा खर्चा मंजूर करेगी। बाढ़ के समय नाव का प्रबन्ध सरकार के हाथ में रहेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के निवासियों के लिए कोई लाभजनक, ठोस व्यवस्था नहीं होने वाली है। जहां तक सामान्य प्रशासन की बात है वहां पर मैं देखता हूं कि ३,५० हजार रुपया सामान्य प्रशासन में जिलाधीशों को मोटर के लिए रखा गया है। जुडीशल मजिस्ट्रेट जो बरसों से सरकार के इशारे पर चलने वाले हैं, जिलाधीशों के इशारों पर चलते हैं उनके पद को स्थायी करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई माननीय राज्यपाल महोदय और सदन ने दी कि उन्होंने बहुत किफायतशारी की है। मैं जानता नहीं कि किफायतशारी कहां कहां ज्यादा की गयी, लेकिन जिलों में जो अधिकारियों की अदालत में चपरासी रहते हैं उनमें विशेष रूप से दिखाई दी। पहले उनको वर्दियां दी जाती थीं, वह उनसे छीन ली गयीं। केन्द्र के चपरासियों और प्रान्त के चपरासियों की तनख्वाहों में लगभग दूने का अन्तर है। प्रान्त के चपरासियों की हालत यह है कि उनकी महंगाई बढ़ती नहीं है और उनका काम दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। १९ घंटे तक काम लिया जाता है।

इसी प्रकार, अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन में रखा गया, गांव पंचायतों के हिसाब जांच करने के लिये आडिटर रखे जायेंगे जिन पर ४,११ हजार रुपया

व्यय होगा। मैं जानता हूं कि हर एक पंचायत सर्किल में एक पंचायत इंसपेक्टर है, उसका काम होता है कि वह प्रत्येक गांव सभाओं के हिसाबों का लेखा जोखा तैयार करे। लेकिन वह क्या करता है? कुछ नहीं करता है। अब इस व्यवस्था से इंसपेक्टरों का यह भी काम खत्म हो जाता है। ४, ११ हजार रुपया सिर्फ आडिट करने के लिये रखा गया है, जो बहुत ही अनुचित है और अपव्यय का एक नमूना है।

पुलिस पर ३,३५ हजार रुपये का खर्चा बढ़ाया गया है। मैं पुलिस की आलोचना करता हूं और कहता हूं कि पहले की पुलिस आज की पुलिस में बहुत कम अन्तर है। कुछ देर के लिए, माननीय मुख्य मंत्री राजस्व मंत्री या माननीय हुकुम सिंह जी कह दें कि सुधार हो गया है, लेकिन आज देहात में रहने वाला जानता है कि उसकी परेशानी किस हद तक बढ़ गई है। मारना-पीटना, मुकदमे में गलत तरीके से फंसाना, चोरी का ठीक तरह से निराकरण न करना यह पुलिस का काम है। लेकिन जहां पुलिस की निन्दा करता हूं वहीं पर उनके वेतन की ओर ख्याल करता हूं तो देखता हूं कि गांव का जो चौकीदार है उसकी तनख्वाह ५ रुपया है, कान्सटेबिल की ३५ रुपया से ६५ रुपया है। कांस्टेबिल और चौकीदार को वर्दी सरकार देती है और सर्किल इंसपेक्टर से आई० जी० पुलिस तक वर्दी देती है, लेकिन थानेदार जिसके हाथ में थाने का सारा इन्तजाम है उसकी वर्दी के लिए सरकार कुछ नहीं देती। उसके घोड़े के लिये ३५ रु० माहवारी दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं कि जिस थानेदार को कहा जाता हो कि वर्दी साफ रखो, उसमें शिकन न पड़ने पावें, २४ घंटे मेहनत करो और फिर उसको १२० रुपये मासिक तनख्वाह दी जाय क्या वह बेईमानी नहीं करेगा? फिर सरकार कहती है कि बेईमानी मत करो। मैं कहता हूं कि आज तनख्वाहों में इतनी विषमता क्यों रखी गई है? आज गांव में एक हरिजन दो एक आने पाता है, दो पैसे तक मजदूरी मिलती है और दूसरी तरफ तीन हजार मासिक तनख्वाह मिलती है इस तरह की विषमता है। इस तरह की विषमता रखकर यह सरकार कल्याणकारी राज्य का स्वप्न देखती है। यह स्वप्न उसी को मुबारक हो। इस सरकार के रहते कल्याणकारी राज्य नहीं बन सकता है।

पुलिस विभाग में एक गुप्तचर विभाग भी है। यह गुप्तचर विभाग जिले में जिला सुपिरटेंडेंट के अधीन रहता है। वह कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाता जो पुलिस के विरुद्ध हो। इस विभाग के लिए माननीय वित्त मंत्री और रुपया मांग रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है केवल माननीय मन्त्रियों की रक्षा के लिए यह गुप्तचर विभाग रहता है। लेकिन इस गुप्तचर विभाग द्वारा यह पता नहीं लगाया जा सकता कि जिले में कौन कौन लोग घूस ले रहे हैं उनको कैसे पकड़ा जाय आदि-आदि।

बेरोजगारी की चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। इसमें केवल दस लाख रुपये का खर्च रखा गया है। वन विभाग में दो लाख का खर्चा पेड़ लगाने के लिए रखा गया है। यह १२ लाख रुपया खर्च करके सरकार बेरोजगारी को हमारे उत्तर प्रदेश से दूर करना चाहती है यह बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि करोड़ों की तादाद में हमारे सूबे के अन्दर बेकार लोग हैं और दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। सरकारी बेंचेज के किसी माननीय सदस्य शायद रमण जी ने कहा था कि ये लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में भुखमरी हो। मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि इस तरह से माननीय सदस्य किसी पार्टी के ऊपर जो पार्टी सारे देश में फैली हुई हो जिसका एक अपना सिद्धान्त हो और जिसके नेता जयप्रकाश, नरेन्द्रदेव और लोहिया जैसे हों जो देश की आजादी में अग्रणी रहे हों। मैं किसी की शान के खिलाफ नहीं कहना चाहता लेकिन बहुत से माननीय मंत्री एवं सदस्य हैं जो सन् ४२ के जमाने में टेलीफोन करके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जेलखाने गये थे और हमारे नेता जयप्रकाश

[श्री रामसुन्दर पान्डेय]

हजारीबाग जेल से कूद करके आजादी की लड़ाई में आहुति देने लगे। मैं आज इस सदन को, इस प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस समय हमारे देश पर संकट आयेगा हमारे सामने कोई मतभेद की बात नहीं होगी लेकिन इस तरह से कटाक्ष करना इस सदन के किसी माननीय सदस्य के लिये शोभनीय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो बड़े जोरों से उसने घोषणा की कि जल्द से जल्द हम न्याय और प्रशासन विभाग का बिलगाव करेंगे लेकिन इस बजट में जिसके लिए इतना जोर लगाया जा रहा है न्याय और शासन विभाग के बिलगाव की कोई चर्चा नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि न्याय और शासन विभाग का बटवारा कब होगा। न्याय और शासन विभाग का बिलगाव न होने के कारण इस प्रदेश में क्या हो रहा है यह हमारे नेता जी ने बताया। जिलाधीशों के हाथों में सारी शक्ति चली जा रही है। सरकार की ओर से जिलाधीशों को यह आदेश दिया गया है कि हर एक जिलाधीश अपने नीचे के कर्मचारियों और अधिकारियों के रोजाना के कामों को लिखा करे। कोई भी मैजिस्ट्रेट बिना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के इशारे के कोई काम नहीं कर सकता। चाहे न्याय हो या अन्याय हो, ईमानदारी हो या बेईमानी हो, सारा काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कराता है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यह सरकार कराती है। न्याय का बिल्कुल गला घोंटा जा रहा है। न्याय और शासन विभाग के बिलगाव की जल्द से जल्द घोषणा करनी चाहिये, तभी सही मानों में सस्ता तथा शीघ्र न्याय मिलेगा।

इसके अतिरिक्त बजट भाषण में करघे के उद्योग के सम्बन्ध में कहा गया है कि ५० हजार बुनकरों को काम देने की व्यवस्था हो जायेगी। हमारे प्रदेश में २ लाख ६० हजार करघे हैं और उन पर ८ लाख बुनकर काम करते हैं। उनमें से केवल ५० हजार बुनकरों को ही काम दिलाकर वित्त मंत्री संतोष करते हैं। आजमगढ़ जिले में तो बुनकर लोग बेचारे दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। सरकार की इस नीति का परिणाम आजमगढ़ के बुनकरों पर विशेष पड़ा है। परिवहन विभाग के सम्बन्ध में जो किताब सदन में मिली है उसमें कहा गया है कि सितम्बर सन् ५३ तक इस प्रदेश में ४,८८२ मुकदमे चलाये गये, जिसमें ५,३४८ के फैसले हो चुके हैं। १ हजार मुकदमे ऊपर से लाये गये। इसी प्रकार की रिपोर्ट सरकार की ओर से निकलती है।

श्री कालिका सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री को अवश्य ही बधाई दूंगा। यह बजट पंचवर्षीय योजना के साथ नत्थी है। हमको इसे इसी नजर से देखना है कि पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में हम अपनी बजट नीति द्वारा कहां तक सफल हुए हैं। पंचवर्षीय योजना में जो सन् १९५५-५६ तक का लक्ष्य हमने बनाया है उसको हम पूरा कर लेंगे या नहीं। इसमें कोई भी मतभेद कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में नहीं हो सकता कि पंचवर्षीय योजना हमें पूरा करना ही है, अखिल भारतीय प्लानिंग कमीशन ने जो नीति हमारे सामने रखी है यदि उसको हम पूरा कर लेते हैं तो सर्वसम्मति से यह बजट सफल बजट कहा जायगा। पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो इस प्रदेश में रखा गया है वह लक्ष्य पहले से ही एक बहुत उदार लक्ष्य है। हम तो यह कहेंगे कि यह बजट बड़ा माडेस्ट बजट है। इस प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यही रखा गया है कि प्रदेश की जनता के ऊपर कम से कम भार पड़े। बाम्बे में १४६ करोड़ व्यय का लक्ष्य रखा गया, मद्रास ने १४० करोड़ लक्ष्य रखा किन्तु हमारे प्रान्त में पहले ९७ करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। पुनः उसको बढ़ा कर १२१ करोड़ किया गया और इस साल वह १३०

करोड़ हो गया है। हमें मालूम नहीं कि १२१ करोड़ के ऊपर ९ करोड़ कौन सा रुपया है। इसी से यह प्रतीत होता है कि हमने पहले से ही यह उद्देश्य रखा था कि जहां तक हो कम से कम हमारे प्रदेश की जनता के ऊपर भार पड़े। अब इसमें यह प्रश्न उठता है कि हमारी सरकार की जो टैक्सेशन प्रणाली है क्या उसको लेकर हम प्रदेश का समुचित विकास सचमुच कर भी पायेंगे या नहीं? मैं तो यह कहूंगा कि विकास के लिए जो भी टैक्सेशन हो वह अवश्य होना चाहिये। इसमें किसी को भी विरोध नहीं होना चाहिये। हमारे माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी एक पैराग्राफ इसके मुताल्लिक है कि इस सम्बन्ध में कोई एजीटेशन होना अनुचित है। हम जब अपनी स्टेट का वास्तविक विकास कर रहे हैं और पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यदि कोई भी विरोध या एजीटेशन टैक्सेशन के, इर्रीगेशन रेट्स के, या किसी लेबी के मुताल्लिक होता है तो यह उचित नहीं प्रतीत होता। अगर ऐसी नीति है तो फिर कोई नरवसनेस की आवश्यकता नहीं थी। बोल्ड पालिसी यही होनी चाहिये। मद्रास, बम्बई और अन्य प्रदेशों में कोशिशें हो रही हैं, अपने अपने प्रदेशों को विकसित करने के लिये ताकि गवर्नमेंट आफ इंडिया में वे अपना केस रख सकें और अमेरिका से जो सहायता मिल रही है उसमें उचित हिस्सा प्राप्त कर सकें। अपने बजट में वे किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आने देते। उसी प्रकार से हमारे सूबे का भी प्रयत्न होना चाहिये। जब हम इस दिशा में और सूबों से अपनी तुलना करते हैं तो यह देखते हैं कि हमें पंचवर्षीय योजना में कोई भी सहायता गवर्नमेंट आफ इंडिया से नहीं मिल रही है।

अब मैं रेहन्द डैम को लेता हूं। वह बहुत आवश्यक डैम है। केन्द्रीय सरकार ने पंचवर्षीय योजना में चार डैम रक्खे हैं दामोदर वैली, हीराकुंड, भाखरा नागल और हरीके आदि। ७६५ करोड़ रुपये उन पर कुल लागत है। ५१८ करोड़ रुपया सन् १९५६ तक उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट व्यय कर रही है। रेहन्द डैम को केन्द्रीय योजना में पहले शामिल नहीं किया गया। लेकिन प्रदेश ने प्रयत्न किया और लिखा पढ़ी की जिसका नतीजा यह हुआ कि ३५ करोड़ के रेहन्द डैम को फाइनल फाइव ईयर प्लान में रख लिया गया। २०० करोड़ रुपये लागत की और ५ योजनायें उसमें आईं, कृष्णा, कोसी, चम्बल, कोयना और रिहन्द। सन् १९५४–५५ और सन् ५५–५६ में रेहन्द डैम के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रुपया ५ योजनाओं के लिये ४० करोड़ एलाट किया है उसमें वह कितना रुपया देगी इसका कोई पता नहीं। ४ करोड़ रुपया रेहन्द डैम पर प्रदेश बजट में रखा गया है। इसमें २ करोड़ के लगभग टी० सी० ए० अमेरिकन एग्रीमेंट से और दो करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट से दे रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो २० करोड़ का हमारे बजट में है। देखने से मालूम होता है कि हमारे प्रदेश ने उस पर एक पैसा भी नहीं रक्खा है। केन्द्रीय सरकार ने रेहन्द डैम को अपनी योजना में सम्मिलित कर लिया है तो फिर यह उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे पूरा कराये। रेहन्द डैम एक उत्पादक योजना है और यह भी सरकार को मालूम है कि सवा पांच परसेंट का मुनाफा उससे प्राप्त होगा। ऐसी योजना के लिये लोकल लोन्स गवर्नमेंट आफ इंडिया लोन, या अन्तर्राष्ट्रीय बैंक लोन लिया जा सकता है, लिया जाय। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न होना चाहिये। ६ या ७ बरस बाद रेहन्द डैम पूरा होगा, यह तो बहुत विलम्ब की बात है, इतने दिनों तक रेहन्द डैम को रुकना नहीं चाहिये। गवर्नमेंट आफ इंडिया के योजना में है कि जब तक दामोदर, वैली, भाखरा, नागल और हीराकुंड आदि प्रोजेक्ट्स तैयार नहीं हो जाते जिनके लिये उसने ७६५ करोड़ रुपये की लागत रक्खी है तब तक वह नये प्रोजेक्ट्स हाथ में नहीं लेगी। बैकवर्ड एरियाज विकास योजना में यह रेहन्द डैम आता है इसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया का कहना है कि ये

[श्री कालिका सिंह]

बैकवर्ड एरियाज (पिछड़े क्षेत्र) प्रतीक्षा करें जब तक कि पहले के चार डैम तैयार नहीं हो जाते। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे प्रदेश की सरकार को योजना में संशोधन करा देना चाहिये। स्केयरसिटी रिलीफ में कितना ही रुपया बरबाद हो गया पूर्वी जिलों में। अगर रिहंड डैम पूरा किया गया होता तो करोड़ों रुपया टेस्ट वर्क्स में जो खर्च हुआ वह बचाया जा सकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट पर जोर दिया जा सकता था कि रिहंड डैम शुरू करने में इंतजार करने की जरूरत नहीं है बल्कि उसे तुरन्त शुरू करना चाहिये। यह दो करोड़ रुपया जो अभी तक नामिनल ग्रांट दी गई है, यही नहीं, बल्कि ३५ करोड़ रुपया पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राप्त करना चाहिये।

इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एलाटमेंट किये हैं उसमें २१ बड़ी-बड़ी योजनायें हैं जैसे चितरंजन, सिंदरी फर्टीलाइजर फैक्ट्री इत्यादि। ये सभी दूसरे सूबों में ही रखी गई हैं। इंगलैण्ड और अमेरिका में इसके लिये लाइसेंस जारी किये जाते हैं और यह देखा जाता है कि जिस क्षेत्र में गरीबी बहुत है और रामैटेरियल अर्थात् कच्चे माल की प्राप्ति का कोई सवाल नहीं है तो उनको वैसे ही क्षेत्र में कारखाना खोलने का लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स खोलने की स्कीम रखी है उसके मुताबिक हमारे यू० पी० में एक भी इंडस्ट्री नहीं दी गई। बंगाल, बिहार उड़ीसा और दक्षिण भारत में बहुत रखा है। प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री और मिर्जापुर सीमेन्ट फैक्ट्री हमने अपने ही बजट से पूरी कीं। यह हो सकता है कि हमारे प्रदेश के इतने अधिक महान् व्यक्ति गवर्नमेंट आफ इंडिया में हैं कि वहां मौडैस्टी के कारण ही हमारे एलोकेशन में कमी होती होगी। जूट ड्यूटी का तो एक हिस्सा हमको मिला। लेकिन इनकम टैक्स का जहां तक सम्बन्ध है हमारे प्रदेश का बाम्बे और मद्रास से कम हिस्सा है। और प्रदेशों में इतना बड़ा बजट नहीं है। हर तरह से यह प्रदेश बड़ा है। इनकम टैक्स के एलोकेशन में हमारा हिस्सा और प्रदेशों से ज्यादा होना चाहिये।

हमने सन् १९५२-५३ के फ़ोगर्स रिजर्व बैंक के रिपोर्ट आन करेंसी ऐन्ड फाइनेंस में देखीं। उसमें इस प्रदेश को जो परकैपिटा आय रुपयों में पड़ती है वह ९ है बम्बई की १६ है, मद्रास की ११ है और बंगाल की १४ है। इस हिसाब से जब कि वहां १६, १४ और ११ का अनुपात है हमारे उत्तर प्रदेश में केवल ९ रुपया प्रति मनुष्य प्राप्त किया गया है। आय उठाने में या तो विरोधी भावनाओं का आदर किया गया है या उदारता ही दिखायी गई है। क्योंकि १९५५-५६ का जो बजट आवेगा उसमें इस नीति को सही होने का प्रश्न पैदा ही होगा इसलिये सरकार को अभी से टैक्सेशन की नीति के, जो भी हो, चाहे डेवलपमेंट लेवी हो, वाटर रेट का हो या जो कुछ भी हो उसको यथोचित रूप में प्रकट कर देना चाहिये। लेकिन कर नीति में हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिये कि जीवन की आवश्यकताओं पर भार न पड़ने पाये और जो रिअल सेविंग्स अर्थात् शुद्ध बचत हैं उन्हीं पर टैक्स लगाया जाय। जनता को सहनशीलता के साथ बरदाश्त भी करना चाहिये क्योंकि पंचवर्षीय योजना को हम सब को मिल कर ही तो पूरा करना है।

*श्री रामशंकर रविवासी (जिला लखनऊ)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने सन् १९५४-५५ का तखमीना सदन के सामने प्रस्तुत किया है, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। यह जरूरी होता है कि किसी राज्य का राजकाज चलाने के लिये बजट से ही श्रीगणेश होता है। माननीय मंत्री जी ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो बजट सदन के सामने रक्खा है वह बहुत ही सराहनीय है। उसकी बहुत सी मदें बहुत ही सुन्दर हैं? जैसा कि सरकार ने सोचा है कि सरकार ६२ सड़कों पर बसें चलायेगी। मैं समझता हूं कि सरकार जो बसें चलायेगी उससे लाखों जनता को सुविधा मिलेगी और हजारों भाइयों को आराम मिलेगा लेकिन सरकार जो यह बसें चलायेगी और जिन सड़कों पर चलायेगी, उनमें लखनऊ शहर के लिये कुछ भी ध्यान नहीं रक्खा गया। मैं जिस लखनऊ शहर की बात कर रहा हूं वह ऐसा है जिसको सुनकर आपको ताज्जुब होगा। लखनऊ में जो बसें चलती हैं वे किस लखनऊ में चलती हैं? नये लखनऊ में। पुराने लखनऊ में चौक बाजार की तरफ केवल एक ही बस चलती है। वहां जो लाखों उस पुरानी राजधानी के रहने वाले हैं उनको काफी परेशानी है। हम देखते हैं कि लखनऊ कानपुर रोड पर तथा दूसरे मार्गों पर सरकार नयी-नयी स्कीम्स चला रही है, लेकिन लखनऊ शहर के पुराने बाशिन्दे, जो कि खंडहरों की तरफ रहते हैं, उनकी तरफ सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया।

दूसरे सरकार ने हरिजनों के लिये जो रुपया रक्खा है उसको देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। इसके लिये पहले ६ लाख रुपया रक्खा जाता था। अब सरकार ने उसको बढ़ाकर ३४ लाख कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो रुपया रक्खा गया है वह हरिजनों की समस्याओं को देखते हुए नाकाफी है, क्योंकि हरिजनों की समस्या बहुत जटिल है। उनकी आर्थिक हालत ऐसी खराब है, वे इतने ज्यादा गिरे हुए हैं, इतने ज्यादा दबे हुए हैं, इतने ग़रीब हैं कि इतने रुपये से उनका काम नहीं चलेगा। फिर भी मुझे संतोष है कि सरकार ने जो रुपया विकास योजनाओं में रक्खा है उससे भी हरिजन भाइयों और पिछड़ी हुई जातियों को लाभ हो सकता है। इस प्रकार मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने वित्त मंत्री जी को फिर धन्यवाद देते हुए लखनऊ की सड़कों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। लखनऊ शहर में तो सड़कें बहुत सुन्दर-सुन्दर बनी हैं लेकिन जिले की सड़कों की हालत अध्यक्ष महोदय बहुत ही खराब है। वहां की हालत ऐसी खराब है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दो सड़कों का बयान आपके सम्मुख कर दूं। वह सड़क जो कि कानपुर रोड बनी है उसके पहले जो रोड थी, आलमनगर से एक महान् रोड जाती थी और वही पहले पुराना रास्ता कानपुर जाने का था। जब से यह कानपुर रोड सीमेंटेड रोड बनी है तब से इस सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया है। इसलिये अगर आप उस सड़क को देखें तो वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। उसी सड़क पर हमारी सरकार का एक सेटिलमेंट भी कायम है, उसी सड़क पर एक शिवजी महाराज का मन्दिर है जहां पर कि बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें लाखों आदमी जाते हैं, उसी रोड पर एक मस्जिद है जहां नौचंदी जुमेरात को लोग शहरों और कस्बों से आते हैं और उसी रोड पर कुराबशा का मेला होता है। इस तरह से यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। लखनऊ जिले को उससे काफी आमदनी होती है। जो म्युनिसिपैलिटी की चुंगी है उससे यह अच्छी तरह मालूम हो सकता है। तो सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह बजट में और जिलों के साथ-साथ लखनऊ जिले की तरफ भी ध्यान दें।

इसी तरह से जो सरकार ने आदर्श बस्तियां बनाने के लिये मद रखी है, मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में वह लखनऊ जिले की तरफ भी ध्यान अवश्य रखे। लखनऊ जिले में भटगांव एक ऐसा गांव है जहां पर कि आग लगी थी जिससे वहां के ६० झोपड़े जल गये।

श्री अध्यक्ष—यह आम बहस है और आप हर बात लखनऊ जिले के लिये ही न कहें।

श्री रामशंकर रविवासी—श्रीमन्, वहां की ऐसी हालत है जिसे मैं संक्षेप में बतला देना चाहता हूं। उस भटगांव को राज्यपाल महोदय भी देखने के लिये गये थे और माननीय गुप्त जी भी देखने गये थे। तो वहां की हालत ऐसी खराब है कि मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई आदर्श बस्ती बसाने की स्कीम हो तो सबसे पहले हरिजनों के लिये वहीं आदर्श बस्ती बननी चाहिये। लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बहुत सी गन्दी बस्तियां जहां गरीब लोग रहते हैं, बसाने के लिये एक स्कीम निकाली है तो सरकार का उस तरफ भी ध्यान रहना चाहिये।

दूसरे हमारी सरकार ने जो सिंचाई योजना बनायी है उसमें उसने ट्यूबवेल बनाने की योजना भी रखी है, लेकिन लखनऊ के लिये कोई भी ट्यूबवेल लगाने की योजना नहीं है। लखनऊ एक ऐसा जिला है जहां कि बहुत छोटे छोटे काश्तकार रहते हैं और वे अधिकतर साग-सब्जी पैदा करते हैं और इसके लिये उनको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिये मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि यह चीज जरूर की जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वाल्मीकियों के लिये मकान बनाने की जो योजना बनायी है उसे देख कर मुझे बहुत खुशी हुई है। अब मैं अधिक न कह कर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका स्वागत करता हूं और इसके लिये उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं आपकी आज्ञा से अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई इसलिये देने खड़ा हुआ हूं कि उन्होंने जिस बजट को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसको अगर ध्यान से देखा जाय तो वह इस प्रान्त की गरीबी मिटाने वाला बजट कहा जा सकता है। उसे आप पंचवर्षीय योजना का बजट भी कह सकते हैं। उसे आप कह सकते हैं कि इस प्रान्त और देश को उन्नति के शिखर की तरफ ले जाने वाला बजट है। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के प्रारम्भ में ही लिख दिया है कि यह बजट एक ऐसा आईना है जिसमें इस प्रान्त की नीति का दर्शन हो सकता है। मैं तो यह भी कहूंगा कि यह एक ऐसा आईना है जिसमें हर देखने वाले को अपनी शक्ल दिखलाई पड़ती है। मेरे मित्र जब शिक्षा की तरफ दृष्टि डालते हैं तो उनको इसकी शिकायत है कि इसमें और धन होना चाहिये और भाषणों के दौरान में यहां तक कहा गया है कि कम्पल्सरी प्राइमरी एजूकेशन हो और आधे से ज्यादा बजट जब तक शिक्षा पर न लगा दिया जाय तब तक यह अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनसे यह पूछता हूं कि यह भी आप कृपा करके बतावें कि किस मद से रुपया निकाल कर आप इस मद में ले जाना चाहते हैं? बजट की मदों को ध्यान से देखा जाय तो करीब तीन-चौथाई से ज्यादा रुपया या तो पंचवर्षीय योजना पर है या अन्य जनहितकारी योजनाओं पर है, उसके अन्दर शिक्षा भी है, सड़क भी है, मेडिकल डिपार्टमेंट भी है, हरिजनों का मुहकमा भी है, हाउसिंग स्कीम भी है। तो जितनी भी जनहितकारी योजनायें हैं या तो वह हैं जिन पर अधिकतर रुपया लगा हुआ है और या पंचवर्षीय योजना पर लगा हुआ है। जब हम बजट के इन अनुदानों को देखते हैं तब प्रसन्नता इस बात की होती है कि इस देश का भविष्य उज्ज्वल है। किन्तु हमारे नेता विरोधी दल जैसा कि उनका सदा से दृष्टिकोण रहा है प्रारम्भ में ही उन्होंने एक बात कही कि यदि कल्याणकारी राज्य का बजट यही है तो हम इसे नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के साथ साथ उन्होंने यह भी शिकायत की कि उन जैसे व्यक्तियों को, प्रकाशकों तथा पत्रों को इस बात की आजादी नहीं है कि वे अपने मतों को अपने प्रकार से व्यक्त कर सकें। जिस किसी ने चाहे इस प्रान्त का रहने वाला हो चाहे बाहर का रहने वाला हो अथवा विदेश का रहने वाला हो जिसने इस प्रान्त की वस्तुस्थिति को, यहां की सच्ची और वास्तविक स्थिति पर

ध्यान ही नहीं दिया है बल्कि देखा है वह सफाई से कह सकता है कि किसी भी व्यक्ति को जहां तक सही बात का सम्बन्ध है उनकी आलोचना करने की तो आजादी है ही जहां तक गलत बातें हैं उनको भी प्रकट करने की यहां पर पूरी तौर पर आजादी है। अध्यक्ष महोदय, एक बात की ओर आपकी आज्ञा से सरकार का ध्यान मैं भी आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने इस बात की शिकायत की है कि पुलिस विभाग के ऊपर तीन चार लाख रुपये की बढ़ोत्तरी हो गई है। मैं तो आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय यह मौका नहीं है कि पुलिस विभाग की तमाम बातों पर ध्यान दिया जाय। जिन बुराइयों की तरफ, जिन कमजोरियों की तरफ माननीय रामसुन्दर जी ने ध्यान आकर्षित कराया है और उसका विवेचन यहां किया है वह अध्यक्ष महोदय, पुलिस अनुदान का जब बजट आयेगा उस दिन उस पर पूरा विचार किया जायगा किन्तु इस समय तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो बढ़ोत्तरी इस विभाग में की गई है वह बहुत कम है और मैं इस बात को समझने में हैरान हूं कि सरकार क्यों नहीं इस बात के महत्व को महसूस करती है कि हमारे प्रदेश में पुलिस विभाग के जरिये से संगठन करने की आवश्यकता है और जैसा कि अपने भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि पुलिस बजट एक कौमी बजट हुआ करता है। पुलिस बजट देश को आगे ले जाने में सहायक होता है क्योंकि किसी प्रदेश या देश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वहां पर शान्ति व्यवस्था पूरे तौर पर न हो। आज अध्यक्ष महोदय, शान्ति व्यवस्था कायम रखने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर है जैसा कि हमारी तरफ के कई सदस्यों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि हमारे देश में पुलिस विभाग में पुलिस के कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और साथ ही साथ उनके पास मौजूदा तरीके के उन साधनों की कमी है जिसके द्वारा वे जुर्मों का मुकाबला कर सकें। आज हम गांवों के अन्दर देखते हैं कि थानों की तादाद बहुत कम है और बहुत दूर दूर पर हैं। यही नहीं, उन थानों पर रहने वाले पुलिस सिपाहियों और थानेदारों की संख्या भी कम है।

इसके अतिरिक्त मुझे इस बात को देख करके प्रसन्नता हुई कि इस बजट में सी० आई० डी० विभाग को फिर से पुनर्संगठन करने की व्यवस्था है। इस समय पर उसकी आवश्यकता भी बहुत है। अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इसलिये है कि आज इस प्रान्त में और इस देश में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो देश को आगे बढ़ाने के रास्ते में घातक सिद्ध हो रहे हैं और जिनके द्वारा इस देश में विध्वंसकारी भावना बढ़ रही है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात बजट में देख करके प्रसन्नता होती है कि वह सी० आई० डी० डिपार्टमेंट को फिर से संघटित करने जा रहे हैं। लेकिन निराशा इस बात से होती है कि इस विभाग के ऊपर खर्चा बहुत कम किया जा रहा है। आखिर इसमें शरमाने की क्या बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है यदि पुलिस पर बजट बढ़ जाए। अगर पुलिस का बजट कौमी बजट है और हम समझते हैं पुलिस से शान्ति व्यवस्था कायम हो सकती है तब फिर कोई वजह नहीं है और कोई कारण नहीं है कि उसके ऊपर हम काफी रुपया खर्च न करें। उन लोगों को जो देश की शान्ति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं उन्हें सफल न होने दें।

अध्यक्ष महोदय, बहुत वादविवाद इस सदन में बेकारी के प्रश्न को ले करके हुआ है। मेरा अपना एक मत है इस सवाल के ऊपर। यह मैं नहीं कहता, अध्यक्ष महोदय, कि इस देश में बेकारी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कहने वाले कहते हैं कि इस देश में बेकारी दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, इसको मैं सही नहीं समझता हूं। बेकारी का क्या मतलब है? बेकारी का अगर यह मतलब है कि हर पढ़े लिखे आदमी को नौकरी दे दी जाय और अगर उसको नौकरी न मिल जाय तो वह बेकार है, यह तो बेकारी के सही माने नहीं हुये। अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी में ऐसे

[श्री रामनरेश शुक्ल]

लोग आये हैं जिनके पास सौ डेढ़ सौ बीघे का फार्म है, उनका अकेला लड़का है, बी० एस-सी० (ऐग्रीकल्चर) है, लेकिन वह नौकरी के लिये दौड़ रहा है और कहता घूमता है कि हम बेकार हैं। तो सही स्थिति यह नहीं है कि इस देश में बेकारी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है या अधिक है। दिक्कत इस बात की है और जिधर सरकार का ध्यान जाना जरूरी है कि इस प्रकार का एक आंकड़ा तैयार होना चाहिये कि दरअसल इस देश के अन्दर बेकार है कौन और जो बेकार हैं, मेरी राय में बहुत थोड़े हैं और उनको फिर आसानी से जगह पर लगाया जा सकता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सुझाव को समझ नहीं पाया हूं और अगर समझा हूं तो मैं मजबूर हूं। उसका विरोध करने के लिये कि मेरे ही एक साथी ने बेकारी को हल करने के लिये यह सुझाव दिया कि प्राइवेट सेक्टर के जो इंटरप्राइज हैं उनको बढ़ाया जाय और बढ़ा कर के बेकारी की समस्या को हल किया जाय। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर मेरी छोटी सी राय में पूंजीवाद को दावत देना है। इसलिये ऐसी बातों की तरफ सरकार का ध्यान जाना नहीं चाहिये।

मुझे अध्यक्ष महोदय, एक बात और इस सदन में बहुत सुनाई पड़ी है और वह दुर्भाग्य से या सौभाग्य से हमारे विरोधी पक्ष से सुनाई पड़ी है कि इर्रीगेशन का टैक्स बढ़ रहा है और इसके खिलाफ सारे देश में आन्दोलन हो रहा है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि यह बातें पार्टी के फायदे के लिये कही गई हैं। लेकिन मुझे ऐसी भी घटनाएं मालूम हैं जैसे चकबन्दी का बिल है जिसका सर्वसम्मति से समर्थन इस सदन में हुआ था, उस चकबन्दी योजना का भी राजनैतिक लाभ उठाने के लिये सुल्तानपुर जिले में हमारे विरोधी दल के लोग उसके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इसलिये हमें खुशी या दुःख हमको इस बात से नहीं होती है जब हम विरोधी दल के नेता से सुनते हैं कि हमारा इस जालिम सरकार से सहयोग कैसा? सहयोग ऐसी सरकार से और ऐसी संस्था से आपका हो कैसे सकता है। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता और उनकी पार्टी का सहयोग ट्रावंकोर में कम्यूनिस्टों से हो सकता है, बम्बई में अम्बेदकर वादियों से हो सकता है, पेप्सू में जनसंघियों और अकालियों से हो सकता है और उनका सहयोग होगा उन लोगों से और उन इंसानों से हो सकता है जिन्होंने कि उनको मजबूर किया था कांग्रेस से बाहर जाने के लिये। उनसे सहयोग ही नहीं हुआ बल्कि उनको बुला करके अपने शिर पर बिठाया है। सहयोग का हाथ जो हमारी तरफ से बढ़ाया गया वह ठुकराया गया, रोटी मांगी गई, पत्थर दिखाया गया, वह आपको मुबारिक रहे। मैं विरोधी दल को बता देना चाहता हूं कि अगर आप आते हैं तो आपके साथ-साथ और अगर आप नहीं आते हैं तो आपके बिना और अगर आप विरोध करते हैं तो आप के विरोध के बावजूद भी इस देश और प्रदेश को हम वहां ले जायंगे जहां उन्नति, सुख और शान्ति के साधन हैं।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो यह १९५४-५५ का आय व्ययक हमारे सामने प्रस्तुत है वह इस तरह से है कि एक ऐसा आर्थिक ढांचा है पूंजीपतियों का जिसमें एक तरफ तिजोरी भरी जाती है और दूसरी तरफ लोगों को खाना नहीं मिलता है। उस ढांचे के बीच में जो व्यवस्था कायम है उसमें प्रान्तीय सरकार भी किसी हद तक असमर्थ है। जो उन्होंने सुधार की दृष्टि से ये चीजें बनायीं कि हमारे देश का विकास हो वह उसमें यहां कर सकते थे इस माने में हम वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि हर एक आदमी की बेकारी मिटायी नहीं जा सकती है। हमारे अभी एक भाई ने कहा कि बड़े पढ़े लिखे लोग फार्म्स रखते हैं और वे नौकरी के लिये आते हैं।

में अपने अनुभव से कहता हूं कि एक गांव का आदमी कलकत्ता जाता है, ६ महीने वहां घूमता है, फिर चला आता है, वहां काम नहीं मिलता है। इस तरह की भी बेकारी है और आज जो समस्या है, जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि हमारा बेटिंग टैक्स है, सेल्स टैक्स है, शूगर सेस है, उनमें प्राप्तियां घट रही हैं, इसके माने यह है कि हमारी पर्चेजिंग कैपेसिटी का पूरा ह्रास हो रहा है और आज उसको सरकार को बढ़ाना है नहीं तो एक तरफ आप देखते हैं कि कुछ मिल मालिक, और मैं यह कह सकता हूं कि राज्यपाल का जो भवन है, हमारे जिले में ऐसे मिल मालिक हैं कि जिनका उनसे अच्छा बंगला है, वेल फर्निश्ड और दूसरी तरफ १० फिट जमीन में २०, २० कुली रहते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था चलने वाली है या चलेगी ?

मैं अब सिंचाई के बारे में आता हूं। मैं मानता हूं कि सिंचाई के बारेमें बड़ा प्रयास और प्रयत्न किया जा रहा है और सचमुच हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है उसमें सिंचाई एक मुख्य स्थान रखती है। सरकार से मैं यह नहीं कहता कि हम आपको इतना रुपया नहीं देंगे। हम तो सरकार से यह कहते हैं कि यह रुपया जो जाता है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं। आपका जो अमला है वह क्या कर रहा है ? श्रीमान्, मैं कहता हूं कि हमारे जिले में कई एक ट्यूबवेल इस वक्त तक चले नहीं। हमारे एक मित्र ने कहा परिपूर्णानन्द जी से मेरा मतलब है, अगर उनके भाषण को इस तरह से समझा जाय कि रात को आकाश के तारे गिने जायं और घर की धन्नियों का पता न हो, उन्होंने यह कहा कि जो एलेक्ट्रिक के चार्जेज हैं वह धनी लोगों पर पड़ते हैं। मैं कहता हूं कि ट्यूबवेल्स से पानी लेने वाले लोग क्या धनी लोग होते हैं। उन्होंने इस साल पानी नहीं लिया, कई एक ट्यूबवेल्स बन्द हो गये इसके कारण। (एक सदस्य--यह अलग चीज है) अलग चीज आप समझते होंगे, मैं नहीं समझता। डिस्टर्ब मत कीजिये। तो मैं यह कह रहा था कि पानी की जमाबन्दी का अमीन है वह वहां गया और पैसे लेकर चला गया, पता नहीं कहां से फर्जी उसने रसीद दे दिया। फिर सरकार की तरफ से मतालबा किया गया, कुर्की और वारंट निकाले गये यहां तक होता है कि १० खेतों में यूनिट्स से पानी देते हैं, दिन भर में उनकी यूनिट्स चलती हैं, उसमें उन्होंने ८ खेत वालों का तो नाम लिखा और दो से पैसे लेकर छोड़ दिया और इस तरह से बाकी को ज्यादा पैसा पड़ गया तो कौन पानी ले। इस जहमत से बचने के लिये लोगों ने पानी लेना बन्द कर दिया है और जब पानी लेते हैं तो पहले दफा शुकाना भी दीजिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि पानी नहीं चाहिये। पानी बहुत अच्छा है और खास करके जो पिछड़े हुये जिले हैं उनको तो बड़ा लाभकारी होगा, लेकिन सरकार को इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि वे लोग इस तरह से कार्य न कर सकें।

श्रीमान्, ग्रामोद्योग के लिये सरकार ने अच्छी सी रकम दी है, ३ करोड़ रुपये इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन स्थापित करने के लिये दिये हैं, बड़ी अच्छी बात है। अभी तक का हमारा अनुभव है कि बहुत से फर्जी लोगों ने आधे बेंत की कुर्सी बुनी और सरकार से ५ हजार की ग्रांट ले ली। उन्होंने कर्घे से एक गज कपड़ा बुना और एक हजार रुपया सरकार से ले लिया। कुछ प्रोफेशनल लोग इस ताक में हैं कि कहां से कितना पैसा मिले। हां यह सही है कि यूटीलाइजेशन सर्टीफिकेट की जरूरत होती है लेकिन यह सर्टीफिकेटस कौन देता है। वह एक इंसपेक्टर देता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसमें नीचे के आदमी सर्टीफिकेट न देने पायें। वह कम से कम एस० डी० एम० के समकक्ष हों।

मैं आप से यह कहता हूं कि हमारे सूबे में गन्ना के विकास की बात है। गन्ना विकास में १४ लाख रुपये लगे हैं। उसमें कहा यह गया है कि इसकी उपज

[श्री रामजी सहाय]

४६० मन हो गई है। मैं श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत मामूली सी बात है आप फैक्ट्रीज को सप्लाई और यहां के फिगर्स मंगा लीजिये उनसे आपको मालूम हो जायगा कि आपकी क्या उपज है। मैं आपसे कहता हूं। कि ३०० मन से आगे उपज कभी नहीं गयी है। जो अमला वहां रहता है वह एक ह्वाईट एलीफैंट की तरह से है काम नहीं करता है और वह सब कंज्यूम कर जाता है मैंने निवेदन किया कि इसके पूरे वर्किंग की जांच करनी चाहिये। हम कृषक हैं, ईख बोने वाले हैं, इसलिये हम निवेदन करते हैं कि इसके लिये सरकार को सतर्क रहना चाहिये। आपका पैसा लगे तो आपको मालूम होना चाहिये कि आपके पैसे का उपयोग हुआ या नहीं हुआ।

इस प्रकार से मैं प्रतिकर के बारे में कहना चाहता हूं कि आजकल जो जमींदारों को दिया जा रहा है उसमें यह हो रहा है कि छोटे जमींदारों की आधी रकम वहीं समाप्त हो जाती है और उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था करें कि उनके घर पर मनीआर्डर चला जाय और वह उससे लाभ उठा सकें।

इसी प्रकार से श्रीमन्, चारे का सवाल है। हमारे सीड स्टोर्स हैं वह खेती के लिये उपयोगी हैं लेकिन आपकी जो सवाई की नीति है वह बड़ी निर्मम और हृदयहीन है। वह एक जालिम बनिये से भी एक कदम आगे है आप उनसे पैनालिटी लेते हैं। इस तरह से वह वहां से बीज लेते हुए डरता है। जब तक चारे का इन्तजाम न होगा तब तक ऐसे पशुओं से कोई कल्याण नहीं होगा चाहे वे दूध के लिये हों या खेत जोतने के लिये हों। हमारे प्रान्त में फौडर केवल ७० प्रतिशत होता है। आप पशुओं की नस्ल भले ही सुधार दें लेकिन जब तक उनको खाने को नहीं मिलेगा तब तक वे क्या कर सकते हैं। मेरी समझ में यह कहना भी असंगत न होगा कि जमींदारी उन्मूलन के बाद एक दोष यह आ गया है कि बंजर जमीन गांव समाज को दे देते हैं उसके कारण सब लोगों ने अपनी जमीनों को अन्डर प्लाऊ कर लिया है इससे भी सब चरागाह खत्म हो गये। इंगलैण्ड जैसे देश में भी कांटेदार तार लगाकर कुछ न कुछ जमीन मवेशियों के चारे के लिये अवश्य रखी जाती हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये कि हम अपने दशांश में जरूर पास्चर लैंड के लिये रख सकें।

बाढ़ भी हमारे प्रान्त के लिये बड़ी भयंकर चीज है। १६ वर्ष पहले गवर्नमेंट ने एक फ्लड कमेटी मुकर्रर की थी इसके बाद अब हम फिर सुन रहे हैं कि वह फिर से रीसर्वे करेगी। इसमें ५ लाख रुपया रक्खा गया है हां, यह बात अच्छी है कि एक लाख रुपया किश्तियों के लिये भी रक्खा गया है लेकिन हमारा ख्याल है कि वहां बांध बनाना आवश्यक है। एक्सपर्ट्स की ओपीनियन को आप समझ सकते हैं। वे कहते हैं कि बांध से नदी सिल्टअप होती है पर बांध बनाये जाते हैं तब तो नदी गहरी हो जाती है। देवरिया में राप्ती नदी सिल्टअप हुई वह इसलिये हुई कि उसका बहाव दूसरी तरफ को हो गया और एक्सपर्ट की रिपोर्ट के लिये क्या कहा जाय एक्सपर्ट तो एक अजीब जीव हैं। अनुभव की बात हम कहते हैं तो वह उसे देखना नहीं चाहते हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें अवसर दिया उस स्थान पर जाकर स्वयं निरीक्षण करने का और इस बारे में वे कार्यशील भी हैं। श्रीमन्, इसी तरह से हमारी शिक्षा के बारे में यह जो कदम उठाया गया है, हम यह कह सकते हैं कि बड़ा ही अच्छा कदम है। जब आदमी बेकार रहता है तब उसका मारल

खराब हो जाता है। जो आलसी रहेगा वह बेकार जरूर होगा। जन उपयोगी चीजों में हम शिक्षा को ले आये हैं, उससे हमारा स्तर ऊंचा उठेगा और हम व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा देंगे।

हमारे भाई राजनारायण जी ने कहा कि यह जो better management कमेटीज बन रही हैं यह तो सरकार अपनी चीजों को थोपने के लिए बना रही है लेकिन मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट कमेटीज एक व्यापारिक ढंग से काम कर रही हैं। उनमें क्या क्या खराबियां पैदा हो गयी हैं, सरकार को उन्हें रोकना आवश्यक था।

सरकार ने यह भी बड़ा अच्छा किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों के लिए यह ३८ लाख रुपया जो कदाचित् पिछले वेतन के बारे में है वह दिया गया। यह सरकार का कार्य बड़ा ही उपयुक्त है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों का सही मानों में सार्वजनिक सेवकों में सबसे ऊंचा स्थान है। उनको दुर्लक्ष्य करने की आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद फिर मुझे न्याय पंचायतों के बारे में निवेदन करना है। न्याय पंचायतें जो हमारे यहां स्थापित हैं उनके बारे में वित्त मंत्री जी ने कहा कि यह भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार में बेजोड़ हैं और चुनी हुई हैं इसीलिये बेजोड़ हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने जो दूसरा कदम उठाया है नामजदगी का जिसके बारे में विरोधी दल के नेता ने कहा कि जनता तैयार नहीं है और वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी लेकिन मैं कहता हूं कि जनता इन चुनी हुई पंचायतों के पक्ष में ही नहीं है। उनकी धमकी बिल्कुल झूंठी और निराधार है। हमने सरकार को एक सुझाव दिया था कि न्याय पंचायतों को ऐसा न बनाइये कि हरएक में मुकद्दमेबाजी होने की प्रवृत्ति हो जाय। बड़ी उनके अन्दर खराबियां हैं। पंच इकट्ठे नहीं होते। सरपंच को ढूंढ़ ढूंढ़ कर दस्तखत कराने पड़ते हैं। दो महीने पहिले की तारीख डाल कर फैसला दिया जाता है जिससे अपील न हो सके और आज हम नालिश करें किसी थाने में या दूसरी जगह तो उससे पहले ही वहां इस्तगासा दर्ज हो जाता है। आज यह अवस्था हो गई है और यह वास्तव में सचमुच संसार में बेजोड़ अवस्था है। हालत यह हो गई है कि हमारा जहां पर घर है हम बोस तरह से डरते हैं। खेतों से, रिश्ते से। १३ आदमियों में से १२ ने वोट दिया तो १३ को हमें खुश करना होता है। हमने यह कहा था कि थाने को यूनिट मानें। थाने में एक लाख आदमी रहते हैं। तीन ईमानदार आदमियों को आप चुनें और उनको आप चाहे आनरेरी मैजिस्ट्रेट कह दें या पंच कह दें हम भी तो कांग्रेस में प्रारम्भिक पंचायत कहते हैं। फिर जिला कमेटियां होती हैं, सूबा कमेटियां होती हैं। इसी प्रकार आप उनको चुनने के लिये जिले में व्यवस्था करें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं या बार एसोसियेशंस हैं। या दूसरे लोग हैं। वे मिल करके इन तीन आदमियों को चुनें। तो जिले में ६० आदमियों को इस प्रकार चुनना है और आप उनको कुछ आने-जाने का भत्ता थोड़ा सा दे दें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो हमारी दुर्दशा हो रही है वह नहीं होगी और पंच–परमेश्वर के नाम पर कलंक नहीं लगेगा।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)––श्रीमन्. मैंने वित्त मंत्री जी के भाषण को पढ़ा और, उसके पश्चात् बजट को भी देखा लेकिन मैं देखता हूं कि दो बातें हमारे वित्त मंत्री जी ने कहीं। एक बात तो यह है कि हम यह प्रयत्न कर रहे हैं और यह हमारा ख्याल है कि नये टैक्स न बढ़ाये जायं। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने यह कहा है कि हम यह देख रहे हैं कि हमारी सरकार कर्जों में लदी जा रही है और कर्जा बढ़ रहा है। ये दोनों बातें मुझे विचित्र सी मालूम होती हैं। प्रथम तो यह अवश्य ही करना है कि जिस प्रकार हो सके हमको आर्थिक दशा अपनी

[श्री श्रीचन्द]

सुधारनी ही है तथा सम्हालनी भी है, उसके लिये एक बचत समिति भी बनाई गई। गत वर्ष भी इसका जिक्र हुआ था और यह भी कहा गया था कि समिति यह देखेगी कि सब विभागों में किन-किन दशाओं पर व्यर्थ व्यय हो रहा है और इसके साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने ढाई करोड़ रुपये की बचत की है। इस सम्बन्ध में मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह प्रयास किया कि हमारे प्रदेश में जो बेकार व्यय हो रहा है उसको रोका जाय। परन्तु साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि अपने बजट में किस स्थान पर बेकार व्यय हो रहा है और किस स्थान पर उचित काम के लिए व्यय सार्थक किया जाता है। मैं देखता हूं कि अनेकों जगहें ऐसी हैं जहां पर रुपया टैक्स के रूप में लेकर निष्फल व्यय करने का प्रयास किया जाता है परन्तु वास्तविक रूप में जिस स्थान में व्यय करना चाहिये वह फलीभूत नहीं होता है। अनेकों जगहों पर उसको रोकने की आवश्यकता है। नहरों को ही लीजिये और सिंचाई विभागों को भी देखिये। नहर विभाग में ऐसा प्रायः होता है कि रुपया हमारी सरकार सिंचाई के लिये काफी दे रही है और ट्यूबवेल बनाने के लिये भी काफी रुपया दे रही है परन्तु यह रुपया जितना भी पहुंचता है व्यर्थ जाता है जैसे पूर्वी जमुना नहर के संबंध में गत वर्ष ३ लाख रुपया दिया गया परन्तु वहां पर जो अच्छे अच्छे पुल थे उनको भी तुड़वाया जा रहा है और पुलों की यह दशा है कि वह इतने ऊंचे कर दिये गये हैं कि बैलगाड़ी का चढ़ना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव सा हो रहा है। वह पुल पर्याप्त मात्रा में थे आवश्यकता इस बात की थी कि नहर में पानी बढ़ाया जाय और यहां से यह भी प्रयत्न किया गया था कि उस नहर के अन्दर पानी बढ़े। परन्तु इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया। सर्वप्रथम सिंचाई के लिये हमारे प्रदेश में इस बात की आवश्यकता थी कि अधिक संख्या में ट्यूबवेल बनायें जायं और नहरों को भी बढ़ाया जाय। सर्वप्रथम यही एक हमारे प्रदेश के लिये जरूरी चीज थी। हमारे सिंचाई मंत्री जी और उपमंत्री जी दो बार इन नहरों को देखने के लिये वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्वयं ज्ञात किया कि पश्चिमी जिलों में जो सर्वोत्तम दशा पूर्वी जमुना नहर की थी अब सब से खराब और सब से रद्दी दशा वहां पर उसकी है उन्होंने यह भी देखा कि पश्चिमी जिलों में पूर्वी जमुना नहर जिन जिलों के अन्दर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली तक गई है, पहले से एक चौथाई पानी रह गया है परन्तु एक चीज मैं यह भी सदन के सामने रखता हूं कि उस नहर की इतनी बड़ी आमदनी है कि हर तीसरे वर्ष जो कुछ उसमें लागत लगाई गई थी वह पूरा कर देती है।

श्री अध्यक्ष --अब आप कृपा करके अपना भाषण समाप्त करें और कल फिर जारी रक्खें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, अनुदानों का प्रोग्राम नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष--वह कल बंट जायगा।

(इसके बाद सदन ६ बजे सायंकाल को अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ
२३ फरवरी, १९५४

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--१४२ एल० ए०-१९५४-८५०।